चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 27 जून– 03 जुलाई 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

विश्व बैंक का नया पैमाना

आय से असहाय

भारत अब विकासशील देश की जगह निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश हो गया है. विश्व बैंक ने जो नए पैमाने निर्धारित किए हैं उसके मुताबिक भारत अब पाकिस्तान और घाना जैसे देशों के साथ आ खड़ा हुआ है. आखिर, इस वर्गीकरण के क्या मायने हैं? इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है. इनका जवाब तभी मिलेगा जब हम विश्व बैंक की कार्यप्रणाली और वर्गीकरण के तरीके को समझेंगे. इस लेख के जरिए हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. विश्व बैंक ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में बड़ा परिवर्तन करते हुए विकसित, विकासशील और अविकसित देशों की अपनी संकल्पना को खत्म कर दिया है. विश्व बैंक ने इसकी जगह प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकरण की एक नई पद्धति लागू की है. आइए सबसे पहले जानते हैं यह नई पद्धति है क्या...

धर्मेंद्र कुमार सिंह

हर साल जुलाई माह में विश्व बैंक दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के विश्लेषणात्मक वर्गीकरण में संशोधन करता है. इसके लिए पिछले वर्ष की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखा जाता है. जुलाई 2015 के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न भागों में बांटा गया है:

- उच्च आय वर्ग – प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12736 डॉलर से ज्यादा
- मध्य आय वर्ग – प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1045 डॉलर से 12736 डॉलर
- मध्यम आय वर्ग को भी दो हिस्सों में बांटा गया है:–
  निम्न मध्यम आय – 1045 डॉलर से 4125 डॉलर तक
  उच्च मध्यम आय – 4125 डॉलर से 12736 डॉलर तक
- निम्न आय वर्ग – प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1045 डॉलर से कम

इस आधार पर वर्गीकृत देशों की संख्या निम्न है:

विभिन्न वर्गों में आने वाले देशों की संख्या

आय वर्ग	देशों की संख्या
निम्न आय	31
निम्न मध्यम आय	51
उच्च मध्यम आय	53
उच्च आय	80

आम तौर पर विकसित, विकासशील और अविकसित देश की शब्दावलियों का प्रयोग होता रहेगा, लेकिन विशेष मामलों में और विश्व बैंक द्वारा इस नए वर्गीकरण का प्रयोग होगा, क्योंकि उनके अनुसार पुराने वर्गीकरण से देशों की अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। नीतियां बनाने, उनको लागू करने और आर्थिक सामाजिक स्थितियों का आकलन और विश्लेषण करने में सुधार लाने के लिए नया वर्गीकरण किया गया है. पहले दुनिया के अधिकतर देश विकासशील देशों के दायरे में आ जाते थे, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा फर्क होता था. उदाहरण के लिए 4.25 बिलियन डॉलर जीडीपी वाला मालवी 338.1 बिलियन जीडीपी वाले मलेशिया के साथ नहीं रखा जा सकता. इसलिए मलेशिया को उच्च मध्यम आय वर्ग में रखा जाएगा और मालवी को निम्न मध्यम आय वर्ग में.

नए वर्गीकरण के मुताबिक भारत को निम्न मध्यम वर्गीय आय वाले श्रेणी में रखा गया है. इस वर्ग में भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, जाम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला और होंडुरास जैसे देश आते हैं. ब्रिक्स देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश रह गया है जो निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है. बाकी देश जैसे ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका सभी उच्च मध्यम आय या उच्च आय वर्ग में चले गए हैं. सिंगापुर और यूएस को उच्च आय वर्ग में रखा गया है.

विश्व बैंक ने यह वर्गीकरण देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सटीक ढंग से विश्लेषित करने के लिए किया क्योंकि पहले एक ही वर्ग में ऐसे देश आ जाते थे जिनमें भारी आर्थिक असमानता है. विश्लेषण, अध्ययन और नीतियों में सुधार के लिए वर्गीकरण को बेहतर और वैज्ञानिक बनाने के लिए ये सुधार किए गए. लेकिन भारत को ध्यान में रखते हुए अगर इस वर्गीकरण पर नजर डालें, तो इसमें कई असंगतियां और खामियां नजर आती हैं.

इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हम विश्व बैंक के इतिहास पर एक नजर डालते हैं, ताकि विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों और मंतव्यों को समझा जा सके. विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत काम करता है. इसका लक्ष्य दुनिया से गरीबी का उन्मूलन करना है. विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में प्रमुख रूप से यूएस और ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी. विश्व बैंक का मुख्य कार्यालय वाशिंगटन डीसी में है. इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो गए यूरोपियन देशों का दोबारा निर्माण करना था. विश्व बैंक का पहला अध्यक्ष युजिन मेयर को बनाया गया और बैंक ने पहला कर्जा 1947 में फ्रांस को दिया. लेकिन जल्दी ही पूरी स्थिति बदल गयी और विश्व बैंक का रुख पूरी तरह से लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देशों के विकास की ओर मुड़ गया. 1950 और 60 के दशक में बांधों, विद्युत ग्रिडों, सिंचाई प्रणालियों और सड़कों पर बैंक का सबसे ज्यादा ध्यान था. बैंक के कर्ज को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बैंक द्वारा दी जानी वाली तकनीकी सहायता की मांग सदस्य देशों में बढ़ती गयी. 1970 के बाद कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा तो विश्व बैंक ने भी अपना ध्यान उस ओर कर लिया. विकास की योजनाएं सिर्फ ढांचागत विकास की बजाय व्यक्ति आधारित होने लगीं. खाद्य उत्पाद, ग्रामीण और शहरी विकास, जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी योजनाएं इस तरह से बनाने की कोशिश होने लगी, ताकि सीधे गरीबों तक पहुंच सकें.

1980 में बैंक ने अपने को सामाजिक विकास पर और अधिक केन्द्रित किया. सामाजिक जीवन में शिक्षा, संचार, सांस्कृतिक विरासत और बेहतर सरकार सब शामिल थी. इस बदले परिदृश्य के मद्देनजर विश्व बैंक के स्टाफ में भी विस्तार हुआ, पहले जहां सिर्फ इंजीनियर, अर्थशास्त्री और वित्तीय विश्लेषक होते थे, अब उनमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होने लगे, जैसे जन नीति विशेषज्ञ, समाज विज्ञानी वगैरह.

वर्तमान में बैंक ने अपने निम्न लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

1. गरीबी और भूख का उन्मूलन
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का विस्तार
3. लैंगिक समानता का प्रसार
4. बाल मृत्यु दर में कमी
5. मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार
6. एचआईवी/एड्स, मलेरिया व अन्य बीमारियों का नियंत्रण
7. पर्यावरण सुरक्षा
8. विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा

अपने इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बैंक ने इस नए वर्गीकरण के मानदंड को लागू किया है. इसके मुताबिक भारत को निम्न मध्यम वर्ग में रखा गया है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है यह वर्गीकरण कहीं से (शेष पृष्ठ 2 पर)

भारत को इस वर्ग में रखने के लिए प्रमुख कारण ये बताए गए

विश्व विकास सूचकांक (भारत बनाम वैश्विक औसत)

सूचकांक	भारत की औसत दर	वैश्विक औसत
व्यापार आरंभ करने में लगने वाला समय (2015)	29	20
मातृत्व मृत्यु दर (प्रति एक लाख) 2015	174	216
स्टॉक बाजार पूंजीकरण (जीडीपी का प्रतिशत) 2014	76	94
सरकार द्वारा जमा किया गया कर (जीडीपी का प्रतिशत) 2013	11	14
श्रमिक भागीदारी दर (15 वर्ष से ऊपर की आबादी का प्रतिशत) 2014	54	63
राष्ट्रीय सुरक्षित क्षेत्र (समग्र क्षेत्र का प्रतिशत)	3.1	12.8
बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच (कुल आबादी का प्रतिशत) 2015	40	68
विद्युत उत्पादन (बिलियन किलोवाट प्रति घंटा) 2013	1193	23342
प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत किलोग्राम तेल के समतुल्य 2013	606	1894

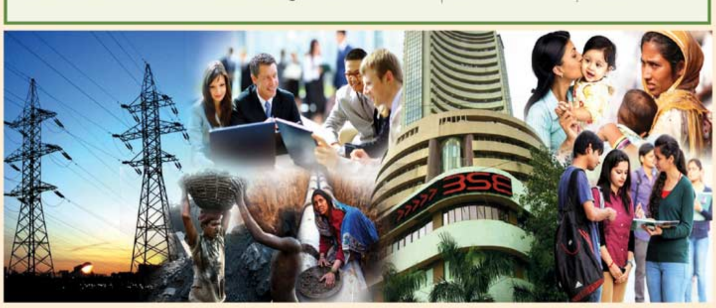

विश्व बैंक का नया पैमाना

आय से असहाय

पृष्ठ 1 का शेष

परिस्थितियों का सही आकलन नहीं करता है. भारत को जिन देशों के साथ रखा गया है उनमें और भारत की अर्थव्यवस्था में जमीन-आसमान का फर्क है. भारत जीडीपी के आधार पर दुनिया की सातवें स्थान की अर्थव्यवस्था है और जहां तक क्रय शक्ति क्षमता (परचेजिंग पावर पैरिटी) की बात है, भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है. भारत की क्रय क्षमता या खरीदारी की ताकत का ही कमाल है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भी भारतीय बाजार में अपना उत्पाद लाना चाहती हैं. नवीन औद्योगीकरण की सूची में शामिल भारत जी-20 देशों में से एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है. ब्रिक्स देशों में भी इसकी अर्थव्यवस्था का एक खास स्थान है और पिछले दो दशकों से इसकी विकास दर 7 प्रतिशत बनी हुई है. महाराष्ट्र यहां का सबसे धनी राज्य है और अकेले उसकी जीडीपी पाकिस्तान या पुर्तगाल से ज्यादा है. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और 2014 के बाद से इसकी वृद्धि दर चीन से भी ज्यादा है. भारत ने अपनी यह विकास दर तब भी कायम रखी है जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के बादल छाए हुए हैं.

1.25 अरब की जनसंख्या और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत की हाल की संवृद्धि तथा इसका विकास मौजूदा समय की अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से है. हाल के दशक में भारत के कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व क्रांति हुई है, जिसकी वजह से काफी समय से अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर यह देश कृषि के वैश्विक पॉवर हाउस में बदल गया है और आज अनाज का शुद्ध निर्यातकर्ता है. औसत आयु बढ़कर दोगुने से भी अधिक हो गई है, साक्षरता की दर में चौगुनी बढ़ोतरी हुई है, स्वास्थ्य-संबंधी परिस्थितियों में सुधार हुआ है और देश में अच्छे ख़ासे मध्य वर्ग का आविर्भाव हुआ है. आज भारत औषधियों, इस्पात, सूचना तथा अंतरिक्ष-संबंधी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विश्वस्तर की जानी-मानी कंपनियों का घर बन चुका है. आज इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आवाज़ माना जाता है, जो इसके विशाल आकार और संभावनाओं के अनुरूप है.

देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे बुनियादी बदलाव हुए हैं, जिससे हम ग्लोबल स्तर पर एक मजबूत देश के रूप में उभर रहे हैं. जल्द ही भारत विश्व का सबसे विशाल और अत्यंत युवा श्रमशक्ति वाला देश बन जाएगा. साथ ही देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ लोग रोज़गार व अवसरों की तलाश में कस्बों और शहरों का रुख कर रहे हैं. यह इस सदी का विशालतम ग्रामीण और शहरी प्रवासन (माइग्रेशन) है. भारत अपनी श्रमशक्ति का किस तरह से विकास करता है और अपने बढ़ते हुए नगरों व कस्बों की संवृद्धि के लिए किस तरह की नई योजनाएं तैयार करता है - इन्हीं चीज़ों से आगामी समय में देश और इसके निवासियों का भविष्य निर्धारित होगा.

लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने, रिहायशी मकानों और बुनियादी सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) का गठन करने के लिए ज़रूरी पूंजी निवेश की ज़रूरत होगी. भारत की 40 करोड़ से अधिक जनता यानी ग़रीबी के चंगुल में फंसे विश्व के एक-तिहाई ग़रीबों का उत्थान करना भारत के लिए चुनौती है. और, हाल में (अकेले 2005-2010 के बीच) ग़रीबी के चंगुल से छूटने वाले 5.3 करोड़ लोगों में से कइयों के दोबारा इसमें फंस जाने की आशंका है. वास्तव में जनसंख्या में वृद्धि होने से भारत के कुछेक सर्वाधिक ग़रीब राज्यों में पिछले वर्षों में ग़रीबों की कुल संख्या बढ़ी है.

देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे बुनियादी बदलाव हुए हैं, जिससे हम ग्लोबल स्तर पर एक मजबूत देश के रूप में उभर रहे हैं. जल्द ही भारत विश्व का सबसे विशाल और अत्यंत युवा श्रमशक्ति वाला देश बन जाएगा. साथ ही देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ लोग रोज़गार व अवसरों की तलाश में कस्बों और शहरों का रुख कर रहे हैं. यह इस सदी का विशालतम ग्रामीण और शहरी प्रवासन (माइग्रेशन) है.

राज्यों, जातियों तथा स्त्री-पुरुषों के बीच भेदभाव समेत सभी स्तरों पर मौजूद समस्त प्रकार की असमानताओं पर ध्यान देना होगा. भारत के सर्वाधिक ग़रीब राज्यों में ग़रीबी की दर अत्यंत विकसित राज्यों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक है. जबकि भारत की वार्षिक औसत प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011 में 1,410 थी (विश्व के मध्यम आय वर्ग के देशों में सर्वाधिक ग़रीब देशों के बीच स्थान) - उत्तर प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या ब्राज़ील से भी अधिक है, यह मात्र 436 और भारत के सर्वाधिक ग़रीब राज्यों में से एक बिहार में केवल 294 थी. ऐसे वर्गों को मुख्य धारा में लाने की, जिससे ये आर्थिक संवृद्धि के लाभों का उपयोग कर सकें और महिलाओं को (विश्व की आधी जनसंख्या) अधिकारिता देने की ज़रूरत होगी, ताकि उन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में अपना न्यायोचित स्थान मिल सके.

शिक्षा तथा कौशल विकास के स्तर को अधिकाधिक उन्नत करना पूरी दुनिया में समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा. हालांकि प्राथमिक शिक्षा काफी हद तक सर्वव्यापी (यूनिवर्सलाइज़) हो चुकी है, अधिगम (लर्निंग) संबंधी परिणाम काफी नीचे हैं. काम करने की आयु वाली जनसंख्या का 10 प्रतिशत से भी कम माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाया है और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वालों में आज के बदलते रोज़गार बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने लायक जानकारी और कुशलता की कमी है.

स्वास्थ्य-संबंधी देखभाल भी समान रूप से महत्वपूर्ण होगी. हालांकि भारत के स्वास्थ्य-संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है, माताओं और बच्चों की मृत्यु दरें बहुत नीचे हैं और कुछ राज्यों में इनकी तुलना विश्व के सर्वाधिक ग़रीब देशों के आंकड़ों से की जा सकती है. भारत के बच्चों में कुपोषण विशेष रूप से चिंता का विषय है, जिनके कल्याण से भारत के प्रतीक्षित जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफ़िक डिविडेंड) का स्तर निर्धारित होगा. इस समय विश्व के कुपोषण का शिकार बच्चों का 40 प्रतिशत (21.7 करोड़) भारत में है.

देश की अवसंरचना-संबंधी आवश्यकताएं काफी अधिक हैं. तीन ग्रामवासियों में से एक की सभी मौसमों के दौरान खुली रहने वाली सड़क तक पहुंच नहीं है और पांच राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक ही चार गलियारों वाला (फ़ोर लेन) है. बंदरगाहों और हवाईअड्डों की क्षमता पर्याप्त नहीं है तथा रेलगाड़ियां बहुत धीरे चलती हैं. अनुमान है कि 30 करोड़ लोग राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से नहीं जुड़े हैं और जो जुड़े भी हैं उन्हें अक्सर आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र अभी छोटा है और पूरी तरह विकसित नहीं है.

दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन के पीछे यहां की युवा आबादी, बचत करने की प्रवृत्ति, बढ़िया निवेश दर और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर सामंजस्य है. भारत में अगले तीन दशकों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के साथ आधी सदी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है. भारत ने 2015-16 के दौरान विश्व बैंक के विकास मानदंड में 7.65 की वृद्धि दर के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और 2016-17 में इसके 8 प्रतिशत से ज्यादा रहने का अनुमान है. सेवा क्षेत्र में भी भारत 9 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. स्टार्टअप के मामले में भी भारत की बादशाहत है और आगामी वर्षों में इसके विश्व की स्टार्टअप राजधानी बनने की प्रबल संभावना है. वर्तमान में स्टार्टअप के मामले में यह विश्व में चौथे स्थान पर है. 2014-15 के दौरान 3,100 तकनीकी स्टार्टअप स्थापित हुए. खेती उत्पादों में भी भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है. भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग भी दुनिया में दूसरी स्थान पर है. यहां 21.48 मिलियन वाहनों का सालाना उत्पादन होता है. दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार के रूप में यहां 2015 में 600 बिलियन डॉलर का रिटेल बाजार कारोबार हुआ. इन सब प्रमाणों और परिस्थितियों को देखते हुए विश्व बैंक को इस वर्गीकरण पर पुनः विचार करना चाहिए, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था का सही आकलन हो सके, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान को और बढ़ाया जा सके और भारत के संबंध में सटीक नीतियां बनायी जा सकें. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 17
27 जून- 03 जुलाई 2016
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के - 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

दिल्ली सरकार और केन्द्र आमने-सामने

दिल्ली के लोग अरविन्द केजरीवाल सरकार और केन्द्र (खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार के बाबुओं के नियत्रंण के सवाल पर) के बीच की आपसी नोक-झोंक के अभ्यस्त हो गए हैं. नया झगड़ा तब शुरू हुआ जब केंद्र ने दिल्ली सरकार से डेपुटेशन पर काम कर रहे बाबुओं की पूरी जानकारी मांगी. गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी दिलीप कुमार ने एक पत्र लिख कर केजरीवाल सरकार को यह आदेश दिया है कि वह राज्य सरकार के तहत काम करने वाले सभी कंसल्टेंट्स की जानकारी उपलब्ध कराए. ज़ाहिर है दिल्ली सरकार को इस में ज़्यादती नज़र आ रही है.

दिल्ली सरकार ने इस पर तल्ख़ प्रतिक्रिया दी. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केन्द्र पर अपनी हद पार कर एक चुनी हुई सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया. सूत्रों के मुताबिक नए झगड़े की जड़ में उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को लिखा गया पत्र है, जिसमें उपराज्यपाल ने इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के एक अधिकारी एसके नगरवाल की शिकायत की है. नगरवाल पर आरोप है कि स्टडी लीव पर रहते हुए वह दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन के कार्यालय में काम कर रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने इसका ज़ोरदार खंडन किया है. लेकिन आप-भाजपा युद्ध को हवा देने के लिए एक हल्की चिंगारी ही काफी है.

टैक्स बाबुओं का मोदी से सामना

वित्तीय समावेशन और कर प्रणाली में पारदर्शिता मोदी सरकार की प्रमुख नीति है. इस नीति पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते हैं कि आयकर विभाग, कस्टम (सीमा शुल्क) विभाग और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के आला अधिकारियों की सेवाएं ली जाएं. सूत्रों ने यह संभावना व्यक्त की है कि भारत सरकार के दो सबसे बड़े विभागों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीइसी) के महानिदेशकों और प्रधान मुख्य आयुक्तों (प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर) के साथ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस महीने के अंत में होने वाले वार्षिक कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत कर सकते हैं.

यह पहला मौक़ा है, जब दो बोर्डों के वार्षिक कॉन्फ्रेंस एक साथ हो रहे हैं. पूर्व में दोनों बोर्ड अलग-अलग समय अपने कॉन्फ्रेंस आयोजित करते थे, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री हुआ करते थे. लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फ्रेंस के की-नोट स्पीकर होंगे जबकि वित्त मंत्री जेटली लीड स्पीकर होंगे. आयकर विभाग के बाबू यह मान रहे हैं कि अपने संबोधन में नरेन्द्र मोदी अपनी सरकार के लक्ष्यों को रेखांकित करेंगे. यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री बाबुओं से आग्रह कर सकते हैं कि वे करदाताओं की शिकायतों को कम करने का उपाय करें और इन विभागों के समक्ष खड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशें.

कठिन नियुक्ति

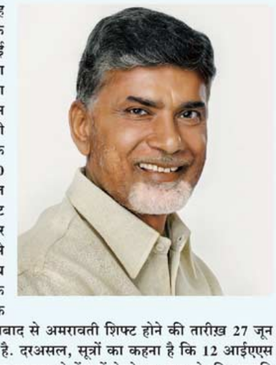

आंध्रप्रदेश सरकार शायद यह नहीं सोच रही थी कि सरकार के बाबू नई राजधानी अमरावती, जिसका निर्माण कार्य अब भी जारी है, जाने का विरोध करेंगे. हाल में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य सचिवालय और लगभग 80 विभागाध्यक्षों को इस महीने के अंत तक हैदराबाद से अमरावती शिफ्ट कर दिया जाए. लेकिन बेहतर सुविधाओं के अभाव की आशंका से सचिवालय के बाबू मध्यांतर में मुख्य सचिव एसपी टकर के कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं. मुख्य सचिव के इस आश्वासन के बाद भी कि हैदराबाद से अमरावती शिफ्ट होने की तारीख़ 27 जून से बढ़ा दी जायेगी, यह धरना जारी है. दरअसल, सूत्रों का कहना है कि 12 आईएएस और 8 आईपीएस अधिकायिों ने राज्य सरकार से केंद्र में डेपुटेशन पर जाने की अनुमति मांगी है. इसका एकमात्र कारण अमरावती शिफ्ट होना बताया जा रहा है. जिन बाबुओं ने डेपुटेशन पर जाने की अनुमति मांगी है उनमें आईएएस अधिकारी केएस जवाहर रेड्डी और ए गिरिधर के नाम शामिल हैं. इन दोनों अधिकारियों ने बहुत साल तक मुख्यमंत्री कार्यालय में काम किया है. ज़ाहिर है जो बाबू अमरावती जाने के खिलाफ़ हैं उन्हें लगता है कि अमरावती एक कठिन पोस्टिंग है.

महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान

नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र

● किसान मंच ने पूछा, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों का क्या हुआ

शशि शेखर

मध्य महाराष्ट्र के किसानों ने इस साल प्याज का रिकॉर्ड उत्पादन किया, लेकिन हालत यह है कि किसानों को लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो रहा है. नासिक में इस बार किसानों को एक रुपये किलो तक में अपना प्याज बेचना पड़ा है, जबकि इसकी लागत 15 रुपये प्रति किलो से अधिक थी. अब ऐसे में कुछ सवाल उठने जायज हैं. मसलन, राजनेताओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया में कहीं आपने यह सुना कि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों की क्या हालत है? क्या किसी भी दल के नेता की बाइट आपने इस मुद्दे पर सुनी? क्या कोई एनजीओ या सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर आवाज उठाता नजर आया? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि किसानों को लागत मूल्य पर अलग से 50 फीसदी का मुनाफा दिया जाएगा, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ई-मार्केट बनाया जाएगा, इन वादों का क्या हुआ? बकायदा मूल्य स्थिरीकरण फंड की स्थापना तो की गई, लेकिन क्या इसका फायदा महाराष्ट्र समेत देश के किसानों को मिल रहा है? क्या देश के आम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (50 फीसदी अतिरिक्त लाभ की तो बात ही छोड़ दीजिए) तक मिल पा रहा है?

हाल में मध्य महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों से मिल कर आए किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह बताते हैं कि 2014 तक 18 हजार टन प्याज का निर्यात हुआ था. इस वजह से यहां के किसानों को राहत मिली थी, लेकिन पिछले दो सालों से इनकी हालत खराब हो रही है. किसान मंच ने अकेले मध्य महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों की दुर्दशा को लेकर आवाज उठाई. उन क्षेत्रों का दौरा किया और प्याज उत्पादक किसानों की खराब हालत को जनता के सामने लाने की कोशिश की. विनोद सिंह बताते हैं कि अब तक केंद्रीय स्तर के किसी भी मंत्री या नेता ने इन क्षेत्रों में जाकर किसानों से बात करने की जहमत नहीं उठाई है.

हमने जब इस मुद्दे को उठाया तब जाकर मीडिया में भी इस संबंध में थोड़ी-बहुत खबरें आनी शुरू हुईं. विनोद सिंह सीधे यह सवाल उठाते हैं कि क्या मोदी सरकार किसानों के मरने के बाद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी. दो साल बीत गए लेकिन अब तक इस आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आखिर किसानों को उनका सही हक कब तक मिलेगा? वह कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि यूपीए और एनडीए, दोनों की आर्थिक व कृषि नीति एक ही है. दोनों के एजेंडे में किसान सिरे से गायब हैं. अगर, भाजपा के एजेंडे में किसान कहीं होता तो आज नासिक और मध्य महाराष्ट्र के किसानों की हालत इतनी खराब नहीं होती.

किसान मंच के महाराष्ट्र इकाई के नेता धनंजय धोर्डे पाटील ने किसान मंच के नेताओं राष्ट्रीय सचिव प्रमोद दल्वी, दिल्ली प्रभारी श्री चंद जैन, उत्तर प्रदेश से किसान मंच के नेता राजेश और किसान मंच यूपी अध्यक्ष शेखर दीक्षित के साथ मिल कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा था और उनसे इस मामले में आवाज उठाने और साथ देने का अनुरोध किया था. इसके बाद नीतीश कुमार ने बकायदा केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को पत्र लिख कर इस समस्या की जानकारी दी और ऐसे कदम उठाने की मांग कि जिससे प्याज उत्पादक किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके. नीतीश कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि अकेले महाराष्ट्र देश का 28 फीसदी प्याज उगाता है, लेकिन किसानों को प्याज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. किसान अपना ऋण चुकाने के लिए मजबूरी में कम दाम पर प्याज बेचने को मजबूर हैं. इस पत्र में यह सवाल भी उठाया गया है कि कृषि पदार्थों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण फंड बनाने का दावा किया था, उसका क्या हुआ?

क्या मोदी सरकार प्याज उत्पादक किसानों के मरने के बाद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी. दो साल बीत गए लेकिन अब तक इस आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है, आखिर किसानों को उनका सही हक कब तक मिलेगा?

विनोद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मंच.

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सरकार ने प्याज को एसेंशियल कमोडिटी में तो शामिल किया लेकिन प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया. हालांकि, यह अलग बात है कि जिन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है, उसकी खरीद कितनी होती है. फिर भी, बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्याज जब एसेंशियल कमोडिटी में शामिल हुआ तो इसका नतीजा यह हुआ कि किसान अब अधिक मात्रा में प्याज जमा कर नहीं रख सकते. नतीजतन, किसानों को अपना उत्पाद औने-पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है. जाहिर है, प्याज उत्पादक किसानों की दुर्दशा पर अब फैसला तो केंद्र सरकार और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को ही करना है. महाराष्ट्र समेत देश के तमाम प्याज उत्पादक किसान उनके फैसले के इंतजार में हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

पूरा हुआ राज्यसभा चुनाव का सियासी प्रहसन

सारे खास हो गए पास

दीनबंधु कबीर

राज्यसभा की 57 सीटों के लिए हुए चुनाव में कम से कम 27 फजीहतें तो जरूर दर्ज हुईं. चुनाव की प्रक्रिया 27 सीटों पर हुई, बाकी निर्विरोध चुन लिए गए. कुछ सीटों को लेकर खरीद-फरोख्त की भी शिकायतें दर्ज हुईं और उस पर चुनाव आयोग को बैठक भी करनी पड़ी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. इस बार 11 नए प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन ये चेहरे भी खास ही हैं. पुराने चेहरे तो खास तौर पर जाने-पहचाने हैं. अब जिस तरह की व्यवस्था काम कर रही है, उसमें किसी आम चेहरे का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल है. राज्यसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश का विधान परिषद चुनाव भी लोगों के ध्यान में था. इसे लेकर मचे घमासान में पूरे देश के लोग दिलचस्पी ले रहे थे. कर्नाटक में विधायकों की खरीद-फरोख्त का स्टिंग सामने आया, लेकिन चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. इसी तरह हरियाणा में विधायकों को मैनेज करने का विचित्र खेल सामने आया, जिसने चुनाव पर असर डाला और चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बनाने में भूमिका अदा की.

इस साल राज्यसभा की खाली हुई 57 सीटों पर चुनाव होना था. इसमें 30 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, जबकि 27 सीटों पर चुनाव हुआ. केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए. राजस्थान से राज्यसभा की चार सीटों पर वेंकैया नायडू के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, हर्षवर्धन सिंह और रामकुमार वर्मा ने भी जीत दर्ज की. राजस्थान से कांग्रेस पार्टी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी व मशहूर उद्योगपति कमल मोरारका चंद वोटों से चुनाव हार गए. उत्तराखंड से राज्यसभा की सीट पर कांग्रेस के प्रदीप टम्टा जीते. बेंगलुरू से राज्यसभा की चार सीटों में से तीन कांग्रेस को मिली और भाजपा को एक सीट मिली. बेंगलुरू से कांग्रेस के ऑस्कर फर्नांडीज़, जयराम रमेश और केसी राममूर्ति राज्यसभा के लिए चुने गए. वहां से भाजपा नेता निर्मला सीतारमण की जीत हुई. जनता दल सेकुलर प्रत्याशी हार गए. झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख़्तार अब्बास नक़वी और महेश पोद्दार जीते. मध्यप्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेता एमजे अकबर और अनिल माधव दवे राज्यसभा का चुनाव जीते. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी सात उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत गए. यूपी में बहुजन समाज पार्टी के दो और भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के एक-एक उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीते. कांग्रेस प्रत्याशी कपिल सिब्बल के मुकाबले खड़ी हुई भाजपा समर्थित प्रीति महापात्रा चुनाव हार गईं. हरियाणा में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाषचन्द्र चुनाव जीत गए.

बीते 11 जून को राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए. इसमें शराब व्यवसायी विजय माल्या द्वारा खाली की गई एक सीट भी शामिल थी. पंद्रह राज्यों से 55 सदस्यों का कार्यकाल जून और अगस्त के बीच पूरा हो रहा है. राजस्थान और कर्नाटक से क्रमशः आनंद शर्मा (कांग्रेस) और विजय माल्या (निर्दलीय) की सीटें खाली हुई हैं. 57 सीटों में 14-14 सीटें भाजपा और कांग्रेस से जुड़ी हैं, जबकि छह सदस्य बसपा, पांच जदयू और तीन-तीन सदस्य सपा, बीजद व अन्नाद्रमुक से हैं. दो-दो सदस्य द्रमुक, एनसीपी और टीडीपी से हैं, जबकि एक सदस्य शिवसेना के हैं. विजय माल्या निर्दलीय सदस्य थे, जिन्होंने पांच मई को इस्तीफा दे दिया था. जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ उनमें केन्द्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सुरेश प्रभु, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व मंत्री जयराम रमेश और जदयू नेता शरद यादव वगैरह शामिल हैं. राज्यसभा की खाली हुई सीटों में सबसे अधिक 11 सीटें उत्तर प्रदेश की थीं, वहीं रिटायर होने वालों में छह-छह सदस्य तमिलनाडु व महाराष्ट्र से हैं. बिहार से पांच सीटों पर चुनाव कराए गए, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से चार-चार सीटों पर चुनाव हुए. मध्य प्रदेश और ओडिशा से तीन-तीन सीटों, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से दो-दो सीटों और उत्तराखंड से एक सीट पर चुनाव हुए. व्यावहारिक तौर पर 27 सीटों पर ही चुनाव हुआ बाकी सीटों पर मामला निर्विरोध निपट गया.

यूपी में राज्यसभा की 11 में से सात सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा. राजस्थान की सभी चारों सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी. उत्तराखंड की अकेली सीट पर कांग्रेस का दांव सफल रहा, जबकि मध्य प्रदेश की तीन में से दो पर भाजपा ने कब्जा जमाया. उत्तर प्रदेश में सपा के सात प्रत्याशी पास हो गए. बसपा के दो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, वहीं भाजपा और कांग्रेस के एक-एक प्रत्याशी ने सफलता हासिल की. राज्यसभा चुनाव में 401 विधायकों ने वोटिंग की. सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की तरफ से अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा के अलावा सुखराम सिंह, कुंअर रेवती रमण सिंह, सुरेंद्र नागर, विवादास्पद बिल्डर संजय सेठ, विश्वंभर निषाद ऊपरी सदन के सदस्य होने का इम्तिहान पास कर गए. बसपा से सतीश चन्द्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की. जबकि कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे कपिल सिब्बल ने निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति महापात्रा को हरा कर अपनी इंट्री की. भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला भी चुनाव में जीते. उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर हंगामा भी हुआ. समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने गुड्डू पंडित पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया, जिसके बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया. वोटिंग के दौरान सपा विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान और भाजपा विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया के बीच भी खूब कहा-सुनी हुई. राजस्थान से राज्यसभा की चारों सीटें भाजपा के खाते में गई हैं. यहां से संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू के साथ ही यूपी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, डुंगरपुर राजघराने के पूर्व सदस्य हर्षवर्धन सिंह और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त अधिकारी रामकुमार वर्मा चुनाव जीते. कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री व उद्योगपति कमल मोरारका चुनाव हार गए. मध्य प्रदेश में भी भाजपा को लाभ मिला. वहां तीन में से दो सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया. भाजपा के एमजे अकबर और अनिल माधव दवे को जीत मिली, जबकि तीसरी सीट पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विवेक तन्खा सीट हासिल करने में कामयाब रहे. झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार भाजपा के उम्मीवार के बतौर विजयी हुए. नकवी को पहली प्राथमिकता के रूप में 2900 वोट मिले और उनके अतिरिक्त 264 पोद्दार को मिले. इससे पोद्दार को मिले मतों की संख्या बढ़कर 2624 हो गई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) उम्मीदवार वसंत सोरेन को 2600 मत मिले. वह तीसरे स्थान पर रहे. 81 विधायकों में से 79 ने ही अपना मताधिकार इस्तेमाल किया.

विधान परिषद पहुंचे सपा के आठों प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव पर भी लोगों का ध्यान था. इसमें सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के आठों प्रत्याशी चुनाव जीत गए. इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तीनों प्रत्याशी भी जीते. कांग्रेस के दीपक सिंह और भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह चौधरी जीते. भाजपा के दयाशंकर सिंह को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा. उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव हुआ था.

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव जीतने वालों में समाजवादी पार्टी के यशवंत सिंह, रणविजय सिंह, बलराम यादव, बुक्कल नवाब, रामसुंदर निषाद, कमलेश पाठक, जगजीवन प्रसाद और शतरुद्र प्रकाश शामिल हैं. बसपा के अतर सिंह राव, दिनेश चंद्र और सुरेश कश्यप भी चुनाव जीत गए. भाजपा के भूपेंद्र सिंह चौधरी और कांग्रेस के दीपक सिंह चुनाव जीते.

कर्नाटक में पांच उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे. यहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, ऑस्कर फर्नांडिस और केसी राममूर्ति को जीत मिली है. यहां मुकाबला कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार और जनता दल सेकुलर प्रत्याशी के बीच था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को कामयाबी मिली. हरियाणा में भाजपा के पास दो प्रत्याशियों को राज्यसभा पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था. केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह राज्यसभा में आसानी से पहुंच गए, लेकिन भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की लड़ाई कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आरके आनंद से थी. आनंद को इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) से भी समर्थन मिला था, लेकिन वे फिर भी हार गए. विपक्ष के 14 वोटों को मतगणना के दौरान तकनीकी तौर पर गलत पाया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया. इसका फायदा सुभाष चंद्रा को मिला और उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया. कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने 14 विधायकों को मतदान में तकनीकी गलती करने के लिए पहले से मैनेज कर रखा था. भाजपा प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि सियासत में ऐसी तकनीकी भूलों का फायदा तो मिलता ही है. उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा का दो निर्दलीय से मुकाबला था. वहां बसपा फैक्टर को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन अकेली सीट पर कांग्रेस के टमटा ने आखिरकार कामयाबी दर्ज की.

उधर, बिहार में राज्यसभा के लिए खाली हुई 5 सीटों पर तीन जून को चुनावी औपचारिकता पूरी की गई और सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए. नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) से पूर्व अध्यक्ष शरद यादव और आरसीपी सिंह निर्वाचित हुए. वहीं लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल से उनकी बेटी मीसा भारती और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए. भाजपा उम्मीदवार गोपाल नारायण सिंह भी निर्विरोध निर्वाचित हुए. लालू की बिटिया मीसा भारती पिछले लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गई थीं. ओडिशा में भी बीजू जनता दल के तीन उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए. बीजद नेता प्रसन्ना आचार्य, विष्णु दास और एन. भास्कर राव राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए.■

feedback@chauthiduniya.com

जन औषधि केंद्र

सेंटर्स खुलें, तब तो गरीबों को मयस्सर हों सस्ती दवाएं

क्यों विफल हो रहे जन औषधि केंद्र

- राज्य सरकार की हेल्थ पॉलिसी में बदलाव
- राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भरता
- जेनरिक दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे डॉक्टर
- सभी दवाओं का स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं होना
- जागरूकता कैंपेन का अभाव
- प्राइम लोकेशन पर जेनरिक स्टोर्स का नहीं खुलना
- स्टोर्स से जेनरिक दवाओं की बिक्री में कमी
- ब्रांडेड दवाओं की तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट का न होना.

चंदन

महंगी ब्रांडेड दवाएं खरीदने में असमर्थ गरीब मरीजों के लिए जन औषधि केंद्र लाइफलाइन की तरह हैं. सस्ते दर पर बेहतर क्वालिटी की दवा उपलब्ध कराने के लिए यूपीए सरकार ने 2008 में जन औषधि केंद्र खोले जाने की योजना बनाई. अब मोदी सरकार इस योजना को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 2017 तक 3000 जन औषधि केंद्र खोलना चाहती है. लेकिन हालात ये हैं कि राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खुले सभी जन औषधि केंद्र बंद हो चुके हैं. 2014 तक 178 जन औषधि केंद्र 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में खोले गए थे, जिसमें मात्र 98 ही कार्यरत हैं. लगभग आधे जन औषधि केंद्रों को सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में बंद करना पड़ा. जरूरत थी कि योजना की विफलता से सबक लेते हुए कोई ठोस कारगर नीति अमल में लाई जाए, ताकि जन औषधि केंद्रों को एक लाभकारी संस्था में बदल गरीबों को सस्ते इलाज का भरोसा दिलाया जा सके.

एनजीओ ने लगाया योजना को पलीता

दिल्ली में इस योजना के नोडल ऑफिसर अवधेश कुमार ने बताया कि शुरू में कई एनजीओ ने इस योजना का अनुचित लाभ उठाया. उन्होंने सरकार से जन औषधि केंद्र खोले जाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि ले ली. उन्होंने कुछ महीने तक दिखावे के लिए जन औषधि केंद्र चलाया और फिर घाटा होने का बहाना बनाकर बंद कर दिया. इससे सबक लेते हुए सरकार अब किसी जन औषधि केंद्र को 15 महीने तक चालू रखने पर ही पूरी रकम किश्तों में उपलब्ध कराती है. अगर कोई केंद्र 15 माह तक खुला रहा, तो स्वाभाविक रूप से बिक्री होने लगती है.

एक साल में कैसे खुलेंगे 3000 केंद्र

सस्ते दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ग्रामीण इलाकों व हर जिले में एक जन औषधि केंद्र खोलना चाहती है. 2017 तक ही 3000 जन औषधि केंद्र खोले जाने हैं, लेकिन आलम यह है कि मई 2016 तक जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए मात्र 800 आवेदन ही आए हैं. ऐसे में एक साल के अंदर 3000 जन औषधि केंद्र खोले जाने का लक्ष्य सरकार के लिए दिवा स्वप्न ही साबित होगा. जन औषधि केंद्रों की विफलता से निराश होकर लोग अब इन केंद्रों के खोले जाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं.

अनुमान है कि देश भर में आठ लाख से अधिक रिटेल फार्मेसी स्टोर्स हैं. जब तक सभी जिले में एक जन औषधि केंद्र नहीं खुल जाता, तब तक यह समुद्र में एक बूंद के समान ही होगा. जहां फार्मेसी कंपनियां अस्सी हजार करोड़ रुपये से अधिक घरेलू बाजार में दवाओं की बिक्री कर रही हैं, वहीं जेनरिक दवाएं दो करोड़ के आस-पास ही सेल कर पा रही हैं.

आपसी सहयोग से होगा विकास

हरियाणा, राजस्थान व तमिलनाडु समेत कई राज्य सरकारें सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराती हैं, जिसके कारण भी कई जन औषधि केंद्रों को बंद करना पड़ा. वहीं, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब उन आठ राज्यों में शामिल हैं, जहां राज्य के हेल्थ विभाग ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को केवल जेनरिक दवाएं लिखने के निर्देश जारी किए हैं. लेकिन डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड कंपनियों की दवा प्रेसक्राइब कर रहे हैं या जेनरिक, इसकी जांच करने के लिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया गया. ऐसे में अस्पताल परिसर स्थित जन औषधि केंद्र ब्रांडेड दवाओं के कंपटीशन में गायब होते जा रहे हैं. समुचित लक्ष्य पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एकसमान नीतियां व आपसी सहयोग का होना नितांत आवश्यक है.

लुभा रहा गिफ्ट्स व ऑफर का खेल

किसी भी बिजनेस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मजबूती ही सफलता की गारंटी होती है. ब्रांडेड दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्स (एमआर) की पहुंच शहर के सभी नामी-गिरामी डॉक्टरों तक होती है. वे अपनी कंपनी की दवा चलाने के लिए डॉक्टर्स को दवा का सैंपल देते हैं. लेकिन बात इतनी सरल नहीं, जितनी सतही तौर पर दिख रही है. एमआर दवाओं के सैंपल के साथ-साथ महंगे गिफ्ट आइटम्स भी डॉक्टर को देते हैं. इसके अलावा साल में एक या दो बार सपरिवार विदेश टूर के पैकेज व कई लुभावने ऑफर भी दिए जाते हैं. डॉक्टर भी दवा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मरीजों को ब्रांडेड कंपनियों की दवा प्रेस्क्राइब करते हैं. ब्रांडेड दवा कंपनियों और डॉक्टरों के इस नेक्सस में फंसकर आम आदमी दम तोड़ रहा है. इस व्यूह जाल को भेद पाने में असमर्थ जेनरिक दवा कंपनियां गरीबों को सस्ते दर पर उत्तम क्वालिटी की दवा तो उपलब्ध कराती हैं, लेकिन डॉक्टर्स को अपनी दवाएं लिखने के लिए तिकड़म नहीं भिड़ा पातीं. यहीं पर सरकारी मदद व प्रोत्साहन की जरूरत होती है, ताकि डॉक्टरों को गरीबों के लिए जेनरिक दवाएं लिखने के लिए बाध्य किया जा सके.

दवाओं का स्टॉक खत्म, लौट रहे मरीज

वहीं कई जन औषधि केंद्रों पर सभी जेनरिक दवाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से भी मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है. सरकार कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग व हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 400 जेनरिक दवाएं इन केंद्रों पर उपलब्ध कराने का दावा करती है. हालांकि, अब सरकार 577 जेनरिक दवाएं इन स्टोर्स पर उपलब्ध कराने जा रही है. लेकिन हकीकत यह है कि दवाएं खत्म होने के बाद इन केंद्रों पर दवाओं का स्टॉक समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है. इन केंद्रों पर दवाएं नहीं मिलने के बाद मरीज भी इन जन औषधि केंद्रों से मुंह मोड़ लेते हैं. हाल में हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक जन औषधि केंद्र को इसलिए बंद करना पड़ा, क्योंकि वह ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा था. दवाओं की समय पर आपूर्ति नहीं होने की वजह से संचालक की कमीशन भी प्रभावित हो रही थी. आखिर में ग्राहकों की भारी मांग के बावजूद जन औषधि केंद्र के संचालक ने इसे बंद करने का फैसला किया.

दवा	ब्रांडेड	जेनरिक
सीप्रोफ्लोक्सेसिन 250 एमजी (एंटीबायोटिक)	55.00	11.10
डिक्लोफिनाक 100 एमजी (पेन किलर)	36.70	3.50
सिट्रीजीन 10 एमजी (कॉमन कोल्ड)	20.00	2.75
पारासिटामोल 500 एमजी (फीवर)	10.00	2.45
निमेस्यूलाइड 100 एमजी (पेन एवं फीवर)	25.00	2.70
कफ सिरप 110 एमएल	33.00	13.30

* मूल्य रुपये में

प्रचार पर ध्यान दे सरकार

नामी-गिरामी दवा कंपनियां टेलीविजन, प्रिंट व सोशल साइट्स के द्वारा अपने दवाओं के प्रचार पर काफी पैसे खर्च करती हैं. मरीज इलाज के लिए अपने डॉक्टर पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता है. दवा कंपनियों के पास एमआर का एक विकसित तंत्र होता है, जो डॉक्टर को लोक-लुभावन ऑफर देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है. वहीं, जब तक आम लोगों को जेनरिक दवाओं की जानकारी नहीं होगी, वे इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं. दवाओं की जानकारी होने पर ही वे डॉक्टर से जेनरिक दवाएं लिखने के लिए कह सकते हैं. सरकार को भी जेनरिक दवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रचार माध्यमों का यथोचित इस्तेमाल करना चाहिए.

जो दिखता है वही बिकता है

शहर में प्राइम लोकेशन पर जन औषधि केंद्र नहीं होने की वजह से आमलोगों को इनकी जानकारी नहीं मिल पाती है. वहीं ब्रांडेड दवा कंपनियों के स्टोर्स शहर में मेन मार्केट व अस्पताल परिसर के आस-पास होते हैं. जो दिखता है, वही बिकता है, के सिद्धांत पर चल दवा कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं, वहीं जन औषधि केंद्रों पर मरीजों के नहीं आने का असर उनकी बिक्री पर पड़ता है. ऐसे में जेनरिक दवाओं की कम बिक्री होने की वजह से जन औषधि केंद्र के संचालक स्टोर का किराया भी मुश्किल से निकाल पाते हैं. आखिर सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में वे इन केंद्रों को बंद करने में ही अपनी भलाई समझते हैं. अवधेश कुमार बताते हैं कि डेढ़ साल में देश भर में करीब 300 जन औषधि केंद्र खुले हैं. हालांकि इसमें कितने स्टोर्स कार्यरत हैं, पर उनसे कोई जानकारी नहीं मिल पाती. उन्होंने बताया कि पहले जेनरिक दवाओं की बिक्री पर दवा विक्रेताओं को 16 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है. साथ ही ज्यादा दवाओं की बिक्री होने पर अलग से इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि पहले पांच में से दो दवाएं ही जन औषधि केंद्रों पर मिल पाती थीं. लेकिन अब 500 से अधिक जेनरिक दवाएं व दो सौ सर्जिकल आइटम्स इन स्टोर्स पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा जन औषधि केंद्र पर 25 प्रतिशत तक आउटी आइटम्स जैसे हॉर्लिक्स, आयोडेक्स व कॉस्मेटिक सामान भी दवा विक्रेताओं को रखे जाने की छूट दी गई है.

उन्होंने बताया कि सरकार रेलवे स्टेशन पर भी जन औषधि केंद्र खोलने जा रही है. हालांकि उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन पर ऐसे केंद्र खोलने से जन औषधि केंद्रों की पब्लिसिटी तो हो सकती है, लेकिन यहां बिक्री की गुंजाइश बेहद कम है. लोग यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, एक मरीज को दवा लेने के लिए तो शहर में मेडिकल स्टोर पर ही आना होगा. इससे बेहतर होगा कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल, ईएसआईसी व पीएचसी में जेनरिक दवाओं का स्टोर खोलने पर ध्यान दे.

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स (डीओपी) की वेबसाइट में जानकारी दी गई है कि अभी 293 जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में संचालित हो रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक 108 छत्तीसगढ़ में ही खुले हैं. इसके बाद ओडिशा में 23, महाराष्ट्र व पंजाब में 22, यूपी में 12, दिल्ली में 9 स्टोर खुले हैं और बिहार में 1 स्टोर खुला है. छत्तीसगढ़ में दुर्ग में जन औषधि केंद्र चला रहीं लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि हफ्ते में एक से डेढ़ हजार रुपये तक की जेनरिक दवाओं की बिक्री हो जाती है. केंद्र पर 150 जेनरिक दवाओं की सप्लाई विभाग द्वारा की जा रही है. यहां से पीएचसी और सीएचसी में भी दवाओं की सप्लाई की जाती है, जिससे कुछ आमदनी हो जाती है. वहीं दिल्ली स्थित शाहदरा में जन औषधि केंद्र चला रहे संजय राघव ने बताया कि हम केंद्र पर 300 प्रकार की जेनरिक दवाएं रखते हैं. दिल्ली में होने के कारण दवाओं की सप्लाई समय पर हो जाती है, जिससे ग्राहकों को केंद्र से लौटना नहीं पड़ता है.

अब डॉक्टर भी उठा रहे सवाल

ब्रांडेड दवा कंपनियों की नुमाइंदगी कर रहे डॉक्टर भी अब जेनरिक दवाओं की क्वालिटी पर सवाल उठाने लगे हैं. एक डॉक्टर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि ब्रांडेड दवाओं के इस्तेमाल से हमें पूरी उम्मीद होती है कि मरीज बेहतर दवा ले रहा है. जेनरिक दवाएं सस्ती होने की वजह से गरीब मरीजों के लिए एक बेहतर विकल्प है. लेकिन जेनरिक दवाओं की इफिशियंसी और क्वालिटी की परख होने के बाद ही इन दवाओं को मरीजों को लेने की सलाह दी जा सकती है. तब तक हमें इंतजार करना होगा. डॉक्टरों का जेनरिक दवाओं को लेकर संशय दूर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स (डीओपी) उन्हें ट्रेनिंग और प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रही है. जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए डीओपी, जो इस योजना की नोडल एजेंसी है, लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ विचार-विमर्श कर रही है. सरकार ने जेनरिक दवाओं के प्रमोशन के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800 180 8080 जारी किया है. इसमें ब्रांडेड दवाओं के बदले समान कंपोजिशन वाले जेनरिक दवाओं के बारे में आम आदमी जानकारी ले सकता है.

सरकारी अधिकारियों को पता है कि ब्रांडेड दवा कंपनियों के चक्रव्यूह का भेदन किए बिना इन जन औषधि केंद्रों पर लगे ग्रहण को दूर नहीं किया जा सकता है. लेकिन एक सवाल जो हमेशा अनुत्तरित रह जाता है कि गरीबों के लिए लाई जाने वाली योजनाओं को हमेशा सरकारी अधिकारियों की बेरुखी का सामना क्यों करना पड़ता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

सत्ता और धनबल के आगे विपक्ष धराशायी

प्रशान्त शरण

राज्यसभा चुनाव में झारखंड में फिर इस बार वही हुआ, जिसकी आशंका थी. इस बार चुनाव में फिर क्रॉस वोटिंग हुई और विपक्षी दलों के साझा प्रत्याशियों की हार हो गई, जबकि विपक्ष के पास जीत का आंकड़ा था. झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो के पुत्र वसंत सोरेन की जीत पक्की मानकर विपक्षी नेता आश्वस्त थे. लेकिन भाजपा ने अपने दूसरे प्रत्याशी की जीत के लिए ऐसी रणनीति बनायी कि विपक्ष के सभी पत्ते धराशाई हो गए. भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि सत्ता और पैसे में काफी ताकत है.

भारतीय जनता पार्टी भले अनुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करे, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने इसे फिर झूठा साबित कर दिया. भाजपा ने राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी. प्रशासन और सत्ता के अलावा पैसे का भी भारी खेल हुआ. सूत्रों की मानें तो पार्टी के रणनीतिकारों ने रांची से 30 किलोमीटर दूर पतरातू की हरी वादियों में ऐसे विधायकों से सम्पर्क किया, जिन्हें रिझाया जा सकता था. पलामू प्रमंडल के दो विधायकों पर डोरा डाला गया. हरी घास के लालच में कई विधायक आ गये और भाजपा ने अपनी जीत के लिए जादुई आंकड़ा छू लिया. भाजपा ने सत्ता का प्रभाव दिखाते हुए उन विधायकों को हड़काया जिन पर कुछ मामलों में वारंट जारी था. भाजपा ने झामुमो के एक विधायक चमरा लिंडा को भी अस्पताल के एक कमरे में बंद करा दिया और चिकित्सकों से यह लिखवा दिया कि उनकी तबियत ज्यादा खराब है इसलिए उन्हें मतदान के लिए नहीं ले जाया जा सकता है. जब झामुमो के नेताओं ने एम्बुलेंस से लाने की कोशिश की तो पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार कर उन्हें अस्पताल में ही घेरे रखा. इस मामले में न्यायालय ने भी संज्ञान लेते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि झामुमो विधायक चमरा लिंडा को गिरफ्तार करने के 24 घंटे बाद भी उन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया. भाजपा के रणनीतिकारों ने पांकी से कांग्रेस विधायक देवेन्द्र सिंह बिट्टू को भी नहीं निकलने दिया और मतदान में जाने से रोक दिया. वैसे इस मामले में देवेन्द्र सिंह का कहना है कि उन्होंने गिरफ्तार होने के डर से मतदान में भाग नहीं लिया और इस मामले में पार्टी के आला नेताओं को भी सूचना दे दी थी. लेकिन सूत्रों की मानें तो भाजपा के रणनीतिकारों ने उन्हें भय के साथ ही सब कुछ दे दिया जो वे चाहते थे. इसके साथ ही पलामू प्रमंडल के एक अन्य विधायक को भी भाजपा अपने साथ करने में सफल रही. इस चुनाव में दो विधायक अनुपस्थित रहे जबकि दो ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के दूसरे करोड़पति उम्मीदवार को राज्यसभा भेज दिया.

दरअसल राज्यसभा चुनाव के एक दिन पहले दस जून को जगन्नाथपुर थाने की पुलिस ने 2013 के एक मामले में आवेदन देकर झामुमो विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया था. चमरा लिंडा रांची के आर्किड अस्पताल में इलाज करा रहे थे. 10 जून को रात जगन्नाथपुर थाने के इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ आर्किड अस्पताल पहुंचे और लिंडा को गिरफ्तार करने की कोशिश की. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबियत खराब है और वे गिरफ्तार करने के लायक नहीं हैं. इसके बाद उनके कमरे के बाहर और अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. मतदान के दिन 11 जून की सुबह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया पर उन्हें कोर्ट में अगले दिन पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को जमकर फटकार लगाई और

पुलिस से पूछा कि आखिर 24 घंटे के अंदर उन्हें न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया गया.

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होना था इसके लिए तीन प्रत्याशी मैदान में थे. जाहिर है किसी एक को हारना था. भाजपा के दो प्रत्याशी थे और दोनों ने जीत हासिल की, झामुमो एक सीट पर लड़ा था और हार गया. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की जीत को लेकर किसी को संशय नहीं था. भाजपा के पास आजसू को लेकर 47 मत थे इसलिए नकवी की आसान जीत तय थी, वे जीते भी पर भाजपा के दूसरे प्रत्याशी महेश पोद्दार के पास जीत का आंकड़ा नहीं था, लेकिन वे जीत गये. इधर विपक्ष के पास 30 मत थे और उन्हें जीत के लिए सिर्फ 28 मत चाहिए था दो मत विपक्ष के पास अधिक था इसलिए विपक्ष अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था. चुनाव के ठीक एक दिन पहले नजारा बदल गया और मतदान होते-होते सारा समीकरण बिगड़ गया. किसी ने क्रॉस वोटिंग की तो कोई गायब रहा और भाजपा ने दोनों सीट पर अपनी जीत दर्ज कर ली. जाहिर है 30 विधायकों के समर्थन वाला प्रत्याशी हार जाये तो इसका साफ-साफ अर्थ है कि किसी ने पार्टी को गच्चा देकर दूसरे को समर्थन दिया. आरोप लग रहा है कि इसके पीछे कोई न कोई खेल हुआ है. अगर पुलिस ने किसी को रोका, तंग किया और विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया तो यह लोकतंत्र का मजाक है. जिस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, वे यह कह रहे हैं कि अन्तर्रात्मा की आवाज पर उन्होंने वोटिंग की, तो यह नैतिकता का खुला मजाक है. हर कोई जानता है कि झारखंड राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कितना बदनाम रहा है.

भाजपा पर सवालिया निशान उठना लाजिमी है. पार्टी ने धन बल और सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया. चमरा लिंडा के खिलाफ जब पुराने मामले थे तो ऐन वक्त पर मतदान के एक दिन पहले क्यों गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ? ऐसे समय पर पुलिसिया कार्रवाई होने से तो गलत संदेश जायेगा ही. चमरा लिंडा भी संदेह के घेरे में हैं. सवाल उठ रहा है कि चमरा लिंडा ने वोट देने के लिए निकलने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगर वे वोट देते तो विपक्ष का प्रत्याशी नहीं हारता.

इस चुनाव में दूसरे विधायक जो सबसे चर्चा में हैं, वे हैं पांकी से कांग्रेस के विधायक देवेन्द्र सिंह बिट्टू. चर्चा है कि उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दायर है और पुलिस ने उन्हें धमकाया भी था. वे इस डर से गायब हो गये और मतदान करने नहीं आये. वैसे वे कहते हैं कि इस बात की सूचना उन्होंने अपने वरीय नेताओं को दे दी थी, पर सवाल उन पर भी यह उठ रहा है कि आखिर वे गायब क्यों हो गये? ठीक एक दिन पहले जब रांची में थे और दिन भर मीटिंग में पार्टी नेताओं के साथ रहे तो अचानक मतदान के दिन कहां गायब हो गये और अपने मोबाइल को स्वीच ऑफ क्यों कर दिया? क्या वे पुलिस की डर से गायब रहे या वे इसकी आड़ में अप्रत्यक्ष ढंग से भाजपा को मदद कर रहे थे? सूत्रों की मानें तो वे 11 जून को मतदान के दिन रांची में ही थे और भाजपा के रणनीतिकारों के सम्पर्क में थे.

अब दो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उसका तो पता चलना मुश्किल है, पर यह तो सच है कि किसी ने गद्दारी की है. दो विधायकों ने विपक्ष की जगह भाजपा को वोट दे दिया ये दोनों किसी भी दल के हो सकते हैं, पर विपक्षी इसका ठीकरा झारखंड विकास मोर्चा के प्रकाश राम और मासस के एकमात्र विधायक अरूप चटर्जी पर फोड़ रहे हैं पर दोनों ने इससे इंकार किया है. वे कहते हैं कि उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट को दिखाकर वोट किया है. इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि पार्टी के दो विधायकों ने पार्टी आलाकमान के फैसले के विरुद्ध काम किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी पांकी के विधायक देवेन्द्र सिंह बिट्टू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जायेगा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में आलाकमान को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है कि पांकी विधायक ने पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान किया है.

वहीं भाजपा के रणनीतिकार हॉर्स ट्रेडिंग से इंकार करते हुए कहते हैं कि उन्हें निर्दलियों का साथ मिला. विपक्षी दल हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि उनके सहयोगी दलों ने ही उन्हें छला है.

जो भी हो झारखंड अपनी बदनामी से उबर नहीं पा रहा है. उम्मीद थी कि पिछले राज्यसभा चुनाव में पूरे देश में यहां के माननीयों का जो छीछालेदार हुआ था, उससे सबक लेकर इस बार वे अपनी नैतिकता का परिचय देंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सियासत में उलझा टॉपर्स घोटाला

सरोज सिंह

टॉपर्स घोटाला पर रोज नए-नए राज बेपर्दा हो रहे हैं. ये तथ्य मामले को कहां और किस दिशा में ले जाएंगे, कहना कठिन है. पुलिस की जांच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. लालकेश्वर प्रसाद सिंह, वैशाली जिला के वीआर कॉलेज के प्राचार्य (कर्ता-धर्ता) अमित कुमार उर्फ बच्चा राय और जनता दल(यू) की नेता व पूर्व विधायक उषा सिन्हा तक आकर सिमट गई है. उषा सिन्हा डॉ. लालकेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी और मगध विश्वविद्यालय के गंगादेवी महिला कॉलेज की प्राचार्य हैं. लालकेश्वर और उनकी पत्नी ने इंटर परीक्षा को कामधेनु समझ कर जमकर दुहा. उषा सिन्हा ने अपने कॉलेज परिसर और वहां के कर्मचारियों का भी इस मामले में भरपूर इस्तेमाल किया. इंटर टॉपर्स घोटाला को बेपर्दा और दोषियों को कानून के हवाले करने में बिहार पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कुछ दिनों में काफी उपलब्धि हासिल की है. अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें घोटाला का सूत्रधार (मास्टर माइंड) बच्चा राय तो है ही, लालकेश्वर का मददगार पटना विश्वविद्यालय का तदर्थ शिक्षक अजित शक्तिमान, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का संदीप झा आदि भी शामिल है. उनसे पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी मिली है. जद(यू) संगठन की महत्वपूर्ण पदाधिकारी और दो बार विधायक रह चुकी उषा सिन्हा इस रैकेट को संचालित कर रही थी. लालकेश्वर-उषा के मददगारों के ठिकानों से जांच दल को काफी मात्रा में सादी और लिखित उत्तर पुस्तिकाएं और प्रमाण पत्र की सादी प्रतियां व अन्य कागजात मिले हैं. वहीं बच्चा राय के वीआर कॉलेज (किरतपुर, भगवानपुर, वैशाली) व अन्य ठिकानों से नकद पच्चीस लाख रुपए से अधिक मिला है. लेकिन, इस घोटाले का सूत्रधार लालकेश्वर, उसकी पत्नी उषा सिन्हा और इस प्रकरण में नामजद चार टॉपर्स भी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस का मानना है कि लालकेश्वर-उषा की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश को अंजाम तक पहुंचाना आसान हो जाएगा. देखना है कि अधिकतर मामलों की तरह इसमें भी आरोपी खुद ही अदालत में समर्पण करते हैं या पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में सफल होती है.

टॉपर्स घोटाला बिहार की इंटर शिक्षा की पुरानी कोढ़ की ताज़ा अभिव्यक्ति है. इसका मवाद अब राजधानी में राजपथ पर फैलने लगा है. सूबे में इंटर शिक्षा के लिए 1980 में इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी. यह संस्था इंटर कालेजों को मान्यता देने, पाठ्यक्रम तय करने के अलावा परीक्षा आयोजित करती रही. संस्था को मजबूत बनाने की जगह राजनेताओं-नौकरशाहों की जोड़ी ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया. बदनामी के बाद इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद की जिम्मेवारी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंप दी गई. राजनीति बदली और सूबे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी. इस सरकार ने बिहार की वित्त-रहित शिक्षा नीति, जिसके तहत नए इंटर और डिग्री कॉलेजों को मान्यता और सम्बद्धता दी जाती रही, में बदलाव किया. निजी इंटर व सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों को इंटर की परीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुदान देने का फैसला लिया गया. इसके पहले इन कॉलेजों को सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती थी. अनुदान मिलने के साथ इंटर शिक्षा-परीक्षा में शुरू से जारी माफियागिरी और मजबूत हुई. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों व राजनेताओं ने इसे खूब खाद-पानी दिया. पिछले दस वर्षों में शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा, जब इंटर परीक्षा-फल में धांधली की खबर सुर्खियां न बनी हों. पिछले ग्यारह वर्षों में - अर्थात् 2005 के बाद से- औपचारिक तौर पर पांच बार मेधा सूची बदली गई है. इंटर परीक्षा में टॉप पचहत्तर प्रतिशत से अधिक छात्र बिहार के ग्रामीण इलाकों के इन्हीं निजी व साधन-विहीन इंटर कॉलेजों के रहे हैं. टॉप छात्रों में अधिकतर की प्रतिभा' रूबी राय और सौरभ श्रेष्ठ से बेहतर रही है, यह कहने में किसी को भी संकोच हो सकता है. मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर, मुंगेर, कैमूर, नवादा आदि दर्जनों जिलों के ग्रामीण इलाकों के निजी इंटर कॉलेज और उनके संचालक इंटर के परीक्षा-परिणाम हर साल अपने मन माफिक जारी कराते रहे हैं. बिहार की राजधानी स्थित साइंस कॉलेज सहित तमाम सुविधा-सम्पन्न नामचीन कॉलेजों के छात्र इन बच्चा राय जैसों की जोड़-तोड़ के कारण दोयम श्रेणी के साबित होते रहे हैं. टॉप सौ छात्रों में नामचीन अंगीभूत कॉलेजों के छात्रों को शायद ही जगह मिलती रही है.

हालांकि, घोटाला केवल इसी साल नहीं हुआ है और इसके नायक बच्चा राय और लालकेश्वर ही नहीं हैं. इंटर के परीक्षा परिणाम को मैनेज कराने में माफिया नियंत्रित निजी इंटर-डिग्री कॉलेजों के अलावा कोचिंग संस्थानों की भी बड़ी भूमिका रहती है. राजधानी सहित सूबे के बड़े व प्रमंडलीय शहरों के कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालक अपने इलाके के बच्चा राय से सीधे सम्पर्क में रहते हैं. ये कोचिंग संस्थान और इंटर कॉलेज छात्र से मनमाफिक परीक्षा परिणाम के लिए डील करते हैं. प्रथम श्रेणी के लिए प्रति छात्र साठ से सत्तर हजार रुपए तो द्वितीय श्रेणी के लिए तीस से चालीस हजार रुपए की रकम तय की जाती है. टॉप सौ में स्थान सुरक्षित कराने की दर प्रति छात्र लाख रुपए से ऊपर होती है. ऐसे परीक्षा-फल से इंटर कॉलेजों को ही लाभ नहीं होता, बल्कि कोचिंग संस्थानों में भी छात्रों की आमद बढ़ जाती है. इस जुगाड़ तकनीक के कारण बिहार के कुछ कोचिंग की कई शाखाएं संचालित होती हैं. प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अधिक होने पर अनुदान की रकम में भारी इज़ाफा होना तय है. एक तीर से कई शिकार करते हैं ये कोचिंग संस्थान व इंटर कॉलेज के संचालक. निजी इंटर-डिग्री कॉलेज के संचालक,कोचिंग संस्थान, परीक्षा समिति के अधिकारियों का एक त्रिकोण राज्य के इंटर परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर बिहार की युवा प्रतिभाओं को निष्तेज कर रहा है.

सूबे के राजनेता बच्चा राय को पक्ष-विपक्ष की गोद में दिखाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, वे समस्या को लेकर गंभीर नहीं. शिक्षा पद्धति में सुधार के बजाय वे इस बात पर चर्चा में मशगूल हैं कि टॉपर्स घोटाले का सूत्रधार और वैशाली जिला के वीआर कॉलेज का प्राचार्य अमित कुमार उर्फ बच्चा राय किसका बच्चा' है, किस राजनेता का करीबी है. सबसे पहले यह बात सामने आई कि यह शिक्षा माफिया राजद प्रमुख लालू प्रसाद का खास' है. लालू प्रसाद के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई. यह भी खबर है कि गत विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव की जीत सुनिश्चित कराने के लिए महुआ में वहां के स्थानीय शिक्षा माफिया की काट के लिए बच्चा राय का उपयोग किया गया. यह भी खबर आई कि बच्चा राय ने तेजस्वी प्रसाद यादव के पक्ष में राधोपुर विधानसभा क्षेत्र में भी काम किया था. इन बातों पर राजनीति गरम हो रही थी और प्रतिपक्षी भाजपा नेता महागठबंधन से सवाल-जवाब कर रहे थे कि बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता वृषिण पटेल के साथ उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी. इस पर चर्चा शुरू होने के पहले ही भाजपा के लोग काफी हमलावर हो गए. इन हमलों के बीच केन्द्रीय राज्य मंत्री गिरीराज प्रसाद सिंह और बच्चा राय के रिश्तों को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिया और वह बिहार के अखबारों में खूब छपा. तेजस्वी के इस पोस्ट में बताया गया कि गिरीराज और बच्चा राय के व्यावसायिक हित जुड़े हैं, दोनों एक साथ मिल कर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे. इस पर अभी चर्चा गरम ही हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बच्चा राय की तस्वीर अखबारों में छपी. इस पर जनता दल(यू) के नेता सफाई दे रहे हैं कि यह तस्वीर एक शादी समारोह की है.

बिहार की ख्याति ज्ञान और मेधा की भूमि के तौर पर रही है. लेकिन हाल के दशकों में यह शिक्षा माफिया का क्रीड़ा-केन्द्र बन गया है. सूबे के वित्त रहित इंटर-डिग्री कॉलेजों के संचालकों की बड़ी जमात सूबे की राजनीति में सक्रिय है और चुनावों में वे दलों के अधिकृत उम्मीदवार होते हैं, जीत कर सदनों में जाते हैं. सूबे की राजनीति में शिक्षा माफिया की मजबूत पकड़ और सक्रियता का ही परिणाम है कि टॉपर्स घोटाला को इसी साल के परीक्षा परिणाम तक सीमित रखने की पूरी रणनीति अपनाई गई है. सच तो ये है कि बिहार के लाखों किशोरों और तरुणों के भविष्य से जुड़े इस सवाल को राजनीतिक दल आरोप- प्रत्यारोप के दायरे से बाहर जाने ही नहीं देना चाहते. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में पूरी तरह बेमानी साबित हुई पंचायती राज व्यवस्था

तीसरी सरकार भी फेल

कुमार कृष्णन

झारखंड राज्य के गठन के बाद दो पंचायत चुनाव हो चुके हैं. राज्य में 24 जिलों के 263 प्रखंडों में पिछले वर्ष हुए चुनाव में 4402 ग्राम पंचायतों में मुखिया पद के लिए चुनाव हुए. इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के 54330 वार्ड सदस्यों, पंचायत समिति के 5423 व जिला परिषद के 545 सदस्यों के लिए चुनाव हुए. इस बार झारखंड में पंचायती राज चुनाव में 54 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आई हैं, जो आरक्षण सीमा से चार प्रतिशत ज्यादा है. झारखंड में इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. पंचायती राज मामले में झारखंड की स्थिति दूसरे राज्यों से कुछ अलग है.

झारखंड प्रदेश के गठन के 10 वर्षों बाद 2010 में पहली बार झारखंड में पंचायत प्रशासन की नींव पड़ी. सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में इस पहल की प्रशंसा हुई थी. संविधान के 73 वें संशोधन में पंचायत प्रशासन के लिए जिन 29 अधिकारों की परिकल्पना की गई थी, उसका अनुपालन नहीं हुआ. इस अवधि में सरकार ने तकरीबन डेढ़ दर्जन विभागों की शक्तियां पंचायतों के हवाले कर दी. उम्मीद थी कि विभागीय अधिकारों के हस्तांतरण के बाद गांवों की तस्वीर बदल जायेगी. लेकिन संविधान प्रदत्त अधिकारों की मांगों को लेकर आवाजें बुलंद करने में ही समय बीत गया. पर्याप्त कर्मियों तथा पंचायत भवनों के अभाव में नयी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना बड़ी चुनौती थी. इससे बढ़कर यह कि आम जनता और नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से लेकर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तक को पंचायती राज व्यवस्था के काम-काज के तरीकों, परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों इत्यादि की समुचित जानकारी नहीं थी. पंचायत चुनाव होने के बाद भी झारखंड में पंचायत निकायों को अधिकार प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा.

इसके बावजूद गांव की सरकार को सरकारी महकमा सहजता के साथ आत्मसात करते नहीं दिख रहे. संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए वर्षों से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की मांग को सूबे की सरकार ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हालात जस के तस हैं. कहने को तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाएं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) को अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन अब भी मामला फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज में ही लटका है. लालफीताशाही की वजह से ये अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रही हैं. पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक और वित्तीय अधिकार सौंपे जाने की घोषणा करने भर से ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका भी स्पष्ट करनी होगी. न तो उन संस्थाओं के लिए मैन पॉवर को लेकर कोई दिशा निर्देश है और न ही उनसे जुड़े कामों को लेकर कोई तस्वीर साफ़ की गयी है. कई दौर की बैठकों के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला. तेरह ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन्होंने तीनों स्तर के पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां तो दे दी हैं, लेकिन उनमें कई कमियां रह गयी हैं. इस बाबत पिछले महीने की 31 तारीख़ को उन सभी विभागों को एक लेटर भेजा गया है.

तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव गौबा ने पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती और सरकारी विभागों में उनकी भूमिका को लेकर एक पत्र लिखा है। लेकिन वह चिट्ठी भी सरकारी फाइल में कहीं धूल खा रही है. संविधान की 11 वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों को जोड़ते हुए राज्य के 13 विभागों में तीनों स्तर की पंचायतों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं. इसके बावजूद ढेरों खामियां हैं. सबसे बड़ी बात यह सामने आयी है कि अधिकतर विभागों में उन संस्थाओं के लिए फंड ही नहीं है. दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ विभागों ने उन शक्तियों का बंटवारा अलग-अलग लेवल पर नहीं किया है। इससे यह कंफ्यूजन बना है कि किस लेवल पर और किस प्रक्रिया के तहत कार्य किए जायेंगे. इसके अलावा विभाग कर्मियों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनका कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, छुट्टी और गोपनीय रिपोर्ट जैसे मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है. इन बिन्दुओं पर सरकार से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिला है. उदहारण के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए खादी बोर्ड, स्मॉल इंडस्ट्री और झारक्रॉफ्ट जैसी संस्थाओं में पंचायती राज की क्या भूमिका होगी यह स्पष्ट नहीं है. इन बॉडीज से जुड़े लाभुकों को पंचायती राज संस्थाएं कैसे चयनित करेंगी यह भी स्पष्ट नहीं है. वहीं, वन एवं पर्यावरण विभाग अब भी दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने में लगा है कि किस तरह वहां की पंचायती राज संस्थाएं इस विभाग से जुड़ी हैं. इसी तरह समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार और खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी अपनी समस्याएं सरकार को बताई हैं. आलम यह है कि जब मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हुई थी और सरकारी विभागों को जब इन बिन्दुओं पर विमर्श करने के लिए बुलाया गया तो 13 में से सात विभागों के प्रतिनिधि पहुंचे ही नहीं.

आज भी झारखंड जैसे राज्य में 35 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं. झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लोग बीपीएल दर्जे और इंदिरा आवास की जितनी मांग करते हैं, उतनी किसी दूसरी चीज की नहीं. ग्रामीणों को लगता है कि अगर वे बीपीएल के दायरे में आ जायेंगे तो बहुत सारी सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. वहीं, अगर लोग इस स्तर से ऊपर आ जायेंगे, तो उनकी मांगों की प्राथमिकता स्वत: बदल जायेगी. तब वे गांव में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा व रोजगार जैसी पांच प्राथमिक चीजों की मांग करने लगेंगे. लेकिन अभी इन मांगों का दर्जा यहां बीपीएल व इंदिरा आवास के बाद ही आता है. बहरहाल, सरकार गांव की सूरत बदलने का ढोल खूब पीटती है. गांव बदले हैं, लेकिन उस स्तर तक नहीं जिस तरह उसे प्रचारित किया जा रहा है.

सरकार ने ग्रामीण विकास व ग्रामीणों के कल्याण के लिए दर्जनों योजनाएं संचालित कर रखी हैं. झारखंड जैसे जनजातीय राज्य के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की योजनाएं और अधिक हैं. लेकिन, गांव के लोग इन योजनाओं की स्पष्ट जानकारी नहीं होने से इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं. केंद्र सरकार पंचायतों को एक मजबूत व स्वायत्त शासन इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना, बीआरजीएफ, पंचायत महिला एवं शक्ति अभियान, रूरल बिजनेस हब, पंचायत इंपावरमेंट एंड एकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम जैसे कार्यक्रम चलाती है. लेकिन कई पंचायत प्रतिनिधियों को इसके तकनीकी पक्ष की जानकारी नहीं है.

श्रीकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रांची के महानिदेशक सुधीर प्रसाद के अनुसार राज्य में पंचायत राज के गठन के बाद उन्हें जिला स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया. राज्य स्तर पर सर्ड व एटीआइ में निरंतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है. अलग-अलग संगठनों व विभागों की ओर से उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं. इसका लाभ हुआ है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण से विषयों व अपनी जिम्मेवारी के प्रति उनकी जानकारी गहरी होती है, जिसका लाभ

> **तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव गौबा ने पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती और सरकारी विभागों में उनकी भूमिका को लेकर एक पत्र लिखा है। लेकिन वह चिट्ठी भी सरकारी फाइल में कहीं धूल खा रही है. संविधान की 11 वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों को जोड़ते हुए राज्य के 13 विभागों में तीनों स्तर की पंचायतों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं. इसके बावजूद ढेरों खामियां हैं.**

जरूरतमंदों तक योजनाओं की प्रभावी पहुंच व ग्रामीण विकास के रूप में दिखता है.

पंचायतीराज विभाग के सचिव प्रवीण शंकर बताते हैं कि पिछले साल विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 40 पंचायत प्रतिनिधियों को गुजरात के पुंसारी पंचायत के सरपंच हिमांशु पटेल से रूबरू कराया गया. पुंसारी पंचायत गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में स्थित है. हिमांशु पटेल के नेतृत्व में इस पंचायत ने विकास के नये आयाम गढ़े हैं और आज यह पंचायत भारत के आदर्श पंचायतों में शुमार है. विकास व नवाचार कार्यक्रमों के लिए पुंसारी पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुका है.

पंचायती राज विभाग के सचिव डॉ. प्रवीण शंकर के अनुसार राज्य में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं. अब पंचायत स्तर पर योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन किया जाएगा. हमारी योजना हमारा विकास के तहत योजना बनाओ अभियान चलाया जा रहा है. अब अधिकारियों को पंचायतों के साथ समन्वय के अतिरिक्त योजनाओं का क्रियान्वयन करना है. योजनाओं का निर्माण पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा. मनरेगा और 14वें वित्त के माध्यम से राशि का विकास व योजनाओं का क्रियान्वयन होना है. ऐसे में समन्वय के साथ वित्तीय पक्ष पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.

पटेल ने पुंसारी में किये गये कुछ उत्कृष्ट कार्यों जैसे पंचायत स्तर पर सूचना-तंत्र प्रणाली का विकास, शुल्क-आधारित पेय जल की व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरे द्वारा पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था के अनुभव भी साझा किए. उन्होंने झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक यह भी बताया कि किस तरह सिर्फ सरकारी स्कीमों के तहत मिलने वाली राशि से पंचायत के विकास कार्यक्रमों को अंजाम दिया गया.

पंचायती राज के जानकार डॉ.विष्णु राजगढ़िया कहते हैं, जिन चीजों की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी गयी है, उसकी जानकारी उन्हें है और जिन विषयों की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी ही नहीं गयी उन्हें उसकी जानकारी कैसे होगी. वे कहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि मनरेगा, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के संचालन-प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहे हैं. डॉ. राजगढ़िया के अनुसार, पंचायत प्रतिनिधि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस काम की जिम्मेवारी उन्हें नहीं देंगे, उसकी जानकारी उन्हें कैसे होगी. वे कहते हैं, अधिकारी भी काम करते हुए सीखते हैं, पहले से सबको जानकारी नहीं होती. राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजमंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा कहते हैं कि पंचायती राज के लिए केंद्र से मिली पहली किश्त की राशि चुने गए मुखियों के खाते में डाल दी गई है. मुंडा ने कहा कि पंचायतों में विकास के लिए डीआरडीए को पूरा अधिकार दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि झारखंड में बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है.

मुख्यमंत्री रधुवर दास ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पंचायतें ग्राम सचिवालय की तरत काम करेंगी. जल्द ही सभी पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय बनेंगे. कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मी भी बहाल होंगे. पंचायतों की एक कार्यकारिणी होगी. पंचायतों के अलावा प्रखंड व जिला स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे. सभी पंचायतों को यह सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए कि उन्हें किस काम के लिए कितनी राशि मिली है. जनता (ग्राम सभा के सदस्यों) को भी यह पता होना चाहिए. सभी पंचायतों में 2017 तक इंटरनेट होगा. मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि बहुत से पंचायत प्रतिनिधि सोचते हैं कि मुखिया बन गये, जिला परिषद में आ गये, तो जितना भ्रष्टाचार करना है कर लें. चुनाव के वक्त खबर आती थी- लोग पूरी घूमते थे. काम नहीं करनेवाले पहले के 80 फीसदी मुखिया इस बार हार गये. ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा बताते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश की प्राचीन व्यवस्था है. पंचायतें सिर्फ सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी नहीं हैं. यह सामाजिक समरसता तथा विकास के लिए जरूरी कई ऐसे कार्य भी करती हैं, जिसमें कोई खर्च जुड़ा नहीं होता. सिन्हा ने बताया कि 14 विभागों के काम, मनरेगा व 14वें वित्त आयोग को मिलाकर पांच वर्षों में पंचायतों को करीब 15 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे.

वहीं फादर स्टेन स्वामी सवालिया लहजे में कहते हैं कि राज्य गठन के 15 वर्षों के दौरान पेसा कानून नहीं लागू किए जाने के पीछे क्या साजिश है. 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार कानून पारित किया गया. इस कानून का मकसद है कि पूंजीवाद के मकड़जाल में फंसे आदिवासी समाज को कैसे बचाएं और संस्कृति तथा परंपरा को केंद्रित करते हुए उनके बीच सुशासन कैसे स्थापित किया जाए. वे साफ तौर पर कहते हैं कि यदि पेसा कानून को सही तरीके से लागू किया जाए तो नौकरशाही का वजूद खत्म हो जाएगा. पंचायती राज के क्षेत्र में तीस वर्षों से काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए. सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही पंचायतों का विकास होगा. झारखंड सरीखे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य के लिए पंचायतों का सशक्त होना आवश्यक है. पंचायती राज की मूल अवधारणा स्थानीय योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

तबला के औघड़ उस्ताद लच्छू महाराज बोले

तुम मुझे गुरुकुल दो मैं नायाब कलाकार दूंगा

फोटो-प्रभात पाण्डेय

लक्ष्मी नारायण जिन्हें तबला के विधा-संसार में पंडित लच्छू महाराज के नाम से जाना जाता है, जो तबले पर हाथ रखते हैं तो उंगलियां दिखाई नहीं देतीं और श्रोता मस्त हो जाते हैं. बनारस घराने के लच्छू महाराज ने तबला के दस हजार से अधिक बोलों को आत्मसात किया और 12 से 14 घंटे तक लगातार तबला बजाने का रिकॉर्ड एक बार नहीं, कई-कई बार बनाया. संगीत के लगभग सारे महापुरुषों के साथ संगत कर चुके लच्छू महाराज एक संजीदा कलाकार भी हैं और फक्कड़ संत भी. आधुनिकता और भौतिकता की अंधी दौड़ में भारतीय संस्कृति, खास कर शास्त्रीय संगीत के खोते जाने के प्रति लच्छू महाराज चिंतित रहते हैं और संगीत की विधा में फिर से गुरुकुल परंपरा की बहाली की हिमायत करते हैं. वे मानते हैं कि भारतीय संगीत और संस्कृति को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी शासक की होती है. औघड़ संत-संगीतकार लच्छू महाराज से पिछले दिनों दिल्ली में मुलाकात हुई तो बस उनको सुनता ही रहा... कोई औपचारिक सवाल नहीं. सवाल के नाम पर अपनी जिज्ञासाओं का केवल एक इशारा भर, और एकबारगी सारा समाधान सामने... जिस व्यक्तित्व को मैंने सुना, उसका शब्दरूप आप भी पढ़ें -

प्रभात रंजन दीन

सवालः पहले ही कह दूं कि जो आपकी विधा है, जो आपका संसार है, उसमें हम कोई सवाल पूछने में सक्षम नहीं हैं. जो आप कहेंगे, जो आप बताएंगे, जो अपने संस्मरणों से गुजरेंगे, शास्त्रीय संगीत का क्या हाल है, शास्त्रीयता किस जगह आकर खड़ी है और इन स्थितियों में आप खुद को कहां खड़ा पाते हैं, मेरी इन जिज्ञासाओं पर आप जो कहेंगे, वही साक्षात्कार है...

जवाबः हम व्यक्तिगत अपने बारे में बता रहे हैं आपको, हमारी जिंदगी तो वैसी ही रही कि जिस डाल पर बैठे उसी को काटते रहे. जो कल के आकार के लिए चिंतित हो, वही कलाकार हो सकता है मेरी नजर में. कल की चिंता आज केवल पैसे और शोहरत पर टिक गई है. मुझे भगवान ने वह सब कुछ तो दिया, लेकिन जो कल का आकार इस मुल्क का, इस देश का होना चाहिए, वह बिल्कुल नहीं है, मुल्क के कल के लिए कोई चिंतित नहीं है और इसी वजह से हम अत्यंत दुखी हैं आत्मा से. हम देश के उसी कल के लिए जी रहे हैं, और तो कोई इच्छा बची नहीं शरीर में. जितनी भी विधाएं हैं संसार में, जैसे मान लें योग ही है. इस समय जो युग चल रहा है, उसमें रामदेव जी का उदाहरण सामने है. पहले उन्होंने न कोई दवा बेची न घी-तेल बेचा. पहले तो सबको समझाया, गंजे को बाल आ जाएगा, जिसको देखो उसी को नाखून निकल आया और वो रगड़े जा रहा है. पहले दो साल तो रामदेव-रामदेव का जप कराया. लोगों की मानसिकता को कैश किया, फिर धीरे-धीरे लिपस्टिक भी ले लीजिए, पाउडर भी ले लीजिए और मंजन भी ले लीजिए. ये साधु का काम तो नहीं है न बाबा. ये तो व्यापारी का काम है, धंधा करने वाले का काम है. कहने का मतलब यह है कि इसी तरह सारी विधाओं का हाल हुआ है. हर आदमी दूसरे का आसरा तलाश रहा है. जैसे अपनी कोई सोच ही नहीं है. कोई पंडित खोज रहा है, कोई मौलवी की तलाश में है तो कोई ज्योतिषी के चक्कर में पड़ा है. और ये सब अपनी विधाएं भूल कर अपना धंधा चला रहे हैं. वर्तमान स्थिति वैसी ही है कि मुझको इंजीनियरिंग की कोई जानकारी नहीं और मुझे मंत्री बना दिया जाए. तो मैं क्या दे पाऊंगा देश को? यही हो रहा है देश में. यहां कवि होना फैशन हो गया है, साहित्यकार होना फैशन हो गया, कलाकार होना फैशन हो गया. अपनी प्राचीन सभ्यता में ऋषि-मुनियों ने जंगलों में रहना क्यों पसंद किया. जंगल में ही रहकर उनलोगों ने जो समाज के लिए कर दिया, वह आज लोगों के बीच रह कर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फलाने बापू हैं, फलाने कथा वाचक हैं तो कोई आशा दिखा रहे हैं तो कोई बताशा. सब सारंगी, तबला और पचासों यंत्र ले लेकर मंडी में बैठ गए हैं. जितने भी आश्रम हैं, सब शहरों में बन रहे हैं. ये आश्रम शहरों में क्यों बन रहे हैं, इन्हें शहरों में आश्रम बनाने के लिए क्यों इजाजत दी जा रही है? इनके ऊपर कोई प्रतिबंध या नियंत्रण क्यों नहीं? इससे सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा या घटेगा? कोई बाबा कहता है कि समोसा खा लो, तो कोई कहता है कि गोल गप्पे खा लो. यह संत परंपरा के साथ तो मजाक ही है न?

सवालः तबला विधा के बारे में कहें...

जवाबः तबला..! तब ला, जब दुनिया में कोई काम न हो. फिर हास्य का भाव छोड़ लच्छू महाराज गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि जब सुर को ताल के साथ मिलाना हो, संतुलित करना हो तब ला, तबला. यह तबला या ढोल या मृदंग, ये सब नाद स्वर के स्रोत हैं. नाद ही ब्रह्मस्य, नाद ही स्वरूपः जगतः, नाद ही सर्व भूतेषु, नाद ही सर्वम मम्म...दुनिया का कोई भी व्यक्ति बताओ जिसे रोना और गाना न आता हो. कोई बच्चा पैदा हुआ और रोया तो वही नाद है. प्रलय भी होगा तो ध्वनि होगी. तितली भी फड़फड़ाती है तो संगीत बजता है, हिरन के कुलांचे में भी संगीत है. ऊं में सारा संगीत, सारे स्वर और सुर निहित हैं. मुझमें तुझमें खड्ग खंभ में घट घट व्यापत राम... ताल की मंद गति स्वास से जुटी रही, चूर भई खोपड़ी मसान में पड़ी रही... आदमी जैसे-जैसे उस प्रकृति के पास पहुंचता जाता है, वैसे-वैसे भौतिक लिप्साओं से दूर होता जाता है. फिर उसमें विशुद्ध मनुष्य होने की इच्छा जाग्रत होती है. तब यह इच्छा बलवती होती है कि हमारे देश के बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, अच्छा जीवन मिले, अच्छा विचार पैदा हो, सब ईमानदार हों. लोग ईमानदार तो तभी होंगे न, जब उनका मूल ठीक होगा. बबूल का वृक्ष लगाएंगे और आम की कल्पना करेंगे, क्या यह संभव है? क्या यह उचित है?

सवालः संगीत की साधना ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय है. इस विधा का हमारी भावी नस्लों में विकास हो इसके लिए आपके प्रयास क्या हैं?

जवाबः हां, संगीत की साधना ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है. लेकिन उपाय कह देने से तो नहीं होगा. जबतक समर्पण न हो, तब तक संभव नहीं है. जिस तरह का वातावरण जरूरी है संगीत के प्रति समर्पण का संस्कार पैदा करने के लिए, वह मौजूदा समय में है ही नहीं. समर्पण के अनिवार्य खाद पर हम ध्यान ही नहीं देते. इसीलिए संस्कार सूखते जा रहे हैं. ऐसे में राजसत्ता का धर्म होना चाहिए कि नई पौध में ऐसा समर्पण जाग्रत करने के लिए जिस तरह का वातावरण जरूरी है उसे जंगल में सृजित करे और फिर हमारे साथ दस बरस के लिए विद्यार्थियों को छोड़ दे... फिर खुद ही देख ले कि हमारी असली औकात क्या है. अब जैसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद वे अपने कर्म के प्रति समर्पण की बात कहते हैं, तो उन्हें संगीत की विधा के विकास के लिए सोचना चाहिए. देश से अगर वास्तविक प्रेम हो तो प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए. अब हमारी यह इच्छा नहीं कि भीख में तुम जमीन दे दो और हम चार सौ बीसी का धंधा शुरू करें.

हम लोग आज तक अपनी भुजा के बल पर ही जो संभव रहा है वह करते रहे हैं. अभी हिमाचल के एक विद्यार्थी को संगीत की दीक्षा दे रहे हैं. विद्यार्थी का हमारे साथ सीखना और उसका खाना-पीना-रहना, सारा इंतजाम मैं कर रहा हूं. वह एक दिन अच्छा नागरिक भी तैयार होगा और अच्छा संगीतकार भी बनेगा. वह तबला की गरिमा को जिंदा रखेगा और अपने गुरु की गरिमा को भी जिंदा रखेगा. ऐसा एक साथ कई विद्यार्थियों के साथ हो सकता है. यह केवल भाषण नहीं है. हमें ऐसे दस बच्चे दे दो तो हम उसे अपनी विधा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना कर दिखा दें. अगर ऐसे दस निष्णात विद्यार्थी हमने बना दिए तब हम अपनी आत्मा से संतुष्ट हो जाएंगे.

सवालः तबला गुरुकुल की स्थापना के लिए आप अपने स्तर से कोई पहल कर रहे हैं?

जवाबः जिसे देखनी हो जन्नत मेरे साथ-साथ आए... हम चलें, इसके लिए लिखा-पढ़ी करें, चिरौरी करें, इतना समय नहीं है न अपने जीवन में. राजाओं ने जो परंपरा जीवित रखी देश में, उसके मुताबिक राजा को खुद ही ज्ञान रहता था कि किस ऋषि की सेवा करने से क्या प्राप्त हो सकता है. किस ऋषि की क्या खासियत है, किस ऋषि के गुरुकुल में किस तरह की विधा पनपती है और वहां से कैसे पारंगत तैयार हो सकते हैं, यह सब राजा को ज्ञात होता था. राजा और उसका तंत्र गुरुकुलों में उस अनुकूल व्यवस्थाएं देता था. गुरु खुद व्यवस्थाओं में नहीं लगा रहता था. ऋषियों-गुरुओं का एकमात्र काम होता था, शिष्यों को सम्बद्ध विधा में दीक्षित करना, उन्हें संस्कारित करना. हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक या दो शिष्य की सीमा तक ही हो पाता है न. आज जो स्थिति है वह अत्यंत विषम है.

सारी विधाएं धंधा बन गई हैं. भूख अब विधा की नहीं रही. सारी विधाएं पेट की भूख, यश की भूख, महत्वाकांक्षा की भूख और भौतिक सुखों की भूख के आगे-पीछे नाचने लगीं. यह अत्यंत चिंता का विषय है. आज किसी बच्चे को दांत का डॉक्टर बनाना हो तो 50 लाख रुपये डोनेशन के नाम पर घूस दीजिए. अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है तो लगभग एक करोड़ डोनेशन दीजिए. तो वह सेवा धर्मी डॉक्टर कैसे बन पाएगा? ऐसे डोनेशन देकर कोई कलाकार कैसे हो सकेगा?

सवालः किन-किन चोटी के संगीतकारों के साथ संगत रहा है?

जवाबः देखो बाबा, भारतवर्ष के जितने भी चोटी के कलाकार हुए, लगभग सभी कलाकारों के साथ मैं संगत कर चुका हूं. अपनी प्रशंसा खुद करना मुझे पसंद नहीं. लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताया न कि बड़े गुलाम अली, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, रईस खान, अमजद अली, निखिल बनर्जी, हरि प्रसाद चौरसिया... ऐसे लगभग सारे बड़े कलाकारों के साथ तबले पर लच्छू महाराज संगत कर चुके हैं.

सवालः ...और प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं में?

जवाबः सितारा देवी, दुर्गालाल, गोपीकृष्ण, बिरजू महाराज जैसे ख्यातिलब्ध नर्तकों और नृत्यांगनाओं के साथ तबले पर मेरी संगत कभी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी. देशभर के मंचों पर हम लोगों ने कई कार्यक्रम दिए. लेकिन बिहार की राजधानी पटना में दुर्गापूजा के मौके पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सड़कों-चौराहों पर हुआ करते थे, उसका कोई सानी नहीं था. वहां के श्रोता भी शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित श्रोता थे, जो शाम से लेकर सुबह तक बैठे ही रह जाते थे. एक बार का वाकया सुनाता हूं, पटना के गांधी मैदान में आठ बजे रात से लगातार तबला बजा रहा था, सुबह चार बजे सितारा देवी के कार्यक्रम का एनाउंसमेंट हुआ. फिर सितारा देवी के साथ घंटों कार्यक्रम चलता रहा. तो 14 घंटे लगातार तबला बजाने का एक प्रतिमान भी स्थापित हुआ. कार्यक्रमों में 12 से 14 घंटे तक लगातार तबला बजाना तो मेरे जीवन में कई बार हुआ.

सवालः ऐसा क्या हुआ कि बिहार, जो ढाई-तीन दशक पहले तक सांस्कृतिक तौर पर सम्पन्न था, देश के सारे ख्यातिलब्ध कलाकार पटना के मंचों पर अपना कार्यक्रम देकर खुश हुआ करते थे, वही राज्य इतना रिक्त हो गया?

जवाबः देखो, बिहार, आसाम और बंगाल, इन तीनों राज्यों को हम लोग शक्तिपीठ मान कर चलते हैं. कहते हैं न, नाहं बसामि वैकुण्ठे योगिनाम ह्रदयेन च, मद्भक्तः यत्र गायन्ति तत्र निष्ठामि नारदा... अर्थात् न मैं बैकुंठ में रहता हूं न योगियों के ह्रदय में, मेरा वास तो वहां है जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं. बिहार देश का बौद्धिक केंद्र रहा. संस्कृति इस राज्य की आत्मा में बसती रही. लोग श्रद्धा और समर्पण से विधाओं का आप्यायन करते रहे. संगीत के प्रति बिहारवासियों की अटूट श्रद्धा रही. बिहार में सांस्कृतिकता के साथ सांस्कारिक लगाव रहा है लोगों का. आज भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा आईएएस पैदा करता है बिहार. यह ऐसे थोड़े ही हो रहा है! बिहार में केवल पटना ही नहीं अन्य शहर भी दीवाली से लेकर दशहरे तक शक्तिमयी हो जाते थे. बिहार से लेकर नेपाल तक संस्कृति की धारा बहती थी. तुलसी गिरी उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे. तुलसी गिरी, मैं, डॉक्टर नागोश समेत कई लोगों की नेपाल में एक सांस्कृतिक टीम जैसी थी. अनगिनत प्रोग्राम हुआ करते थे उन दिनों नेपाल में. अब तो बिहार क्या, पूरा दौर ही स्खलन के काल से गुजर रहा है. पुण्य संगीत पाप-म्यूजिक में तब्दील हो गया है. भारत की संस्कृति से जुड़ा शास्त्रीय संगीत पुण्य संगीत था. जहां म्यूजिक ही पाप हो जाए, तो उसे झेलना हमें ही पड़ेगा न.

एक उदाहरण देता हूं. तब लखनऊ में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक हुआ करता था, जो बाद में बदल कर भातखंडे संगीत विद्यापीठ हो गया. उस समय सम्पूर्णानंद यूपी के मुख्यमंत्री थे. उस समय अहमद जान थिरकवा, रोजवेल लॉयल, आफाक, राधावल्लभ, कल्याणपुरकर, संगीतकार रौशन जैसी हस्तियों का बैच हुआ करता था. अभी तो आप किसी भी म्यूजिक कॉलेज में चले जाएं, समझ में ही नहीं आता कि ये आखिर करते क्या हैं. अब तो संगीत की विधा में भी डॉक्टर होने लगे हैं. मेरी समझ में नहीं आता कि यह डॉक्टर क्या बला है. तानसेन, बैजू बावरा, हरिदास के जमाने में क्या डॉक्टर-बैध थे? ऋषि-मुनि जो एक ही जगह से पूरी दुनिया को देख लेने की क्षमता रखते थे, क्या उनके जमाने में डॉक्टर-बैध थे? वो प्रकृति के साथ रहते थे, प्रकृति का अध्ययन करते थे, जीवों के स्वर से संगीत तलाशते थे. उन लोगों ने जो कुछ भी दिया भारतीय संस्कृति को वह नायाब है, दुर्लभ है. संगीत जैसी कई विधाओं की समुन्नत संस्कृति को जितना मनुष्य से नहीं मिला, उससे एक लाख गुना अधिक पक्षियों और प्राणियों से मिला, जंगल के अपने सुर-ताल से मिला, इसे हमारे ऋषि-मुनियों ने समझा और उसे लयबद्ध करके दुनिया के समक्ष रख दिया. यह विधा अपनी है, मौलिक है. लेकिन इसे विकसित करने के बजाय हमने क्या किया? हमने विधा के नाम पर अपनी दुकान चलाई. अपने ही प्रचार और मार्केटिंग पर ध्यान लगाया. जो हम जैसे लोग तो कर नहीं सकते, न कभी किया और न करेंगे. अब देखिए, काशी में तैलंग स्वामी हुए. तैलंग स्वामी का काल सबसे अच्छा काल है. वे चाहते तो एक लाख चेला बना लेते उस समय, लेकिन नहीं, उन्होंने दो ही चार शिष्य पैदा किए जो अतुलनीय हैं. जो प्रकृति से प्रदत्त विधाएं हैं, उन विधाओं के उस्ताद हमेशा अपनी विधा के संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं.

सवालः पुरस्कार और सम्मान पर आपकी राय?

जवाबः मशहूर वायलिन वादक एम राजम थीं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष. उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का एकेडमी पुरस्कार देने का प्रस्ताव दिया था. कोई तीस साल पुरानी बात हो गई. राजम खुद कलाकार थीं और संगीत की योग्य हस्ताक्षर थीं, तो उनके हाथों से सम्मान प्राप्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई थी. सम्मान के सामने मैंने पद्म पुरस्कार तक की परवाह नहीं की. चंद्रशेखर जी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पद्मश्री पुरस्कार के लिए मेरा नाम नामित हुआ था. तब मुझसे बात करने के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर के किसी अधिकारी का मेरे यहां वाराणसी आना तय हुआ था. उनकी तरफ से 11 बजे दिन में आना तय किया गया था. लेकिन वे दोपहर दो बजे के बाद मेरे घर पहुंचे. मैंने उन्हें नीचे से ही लौटा दिया. उस समय मेरे रियाज और शिष्यों को सिखाने का वक्त था, मैंने पीएमओ के अधिकारी को वापस लौटा दिया. जिसे लोभ-लिप्सा हो, वह सब कुछ छोड़ कर पद्म पुरस्कार के लिए जतन करे. मैंने तो अधिकारी महोदय को वापस कर दिया और फिर कभी चंद्रशेखर जी से इस बारे में कुछ कहा भी नहीं.

सवालः फिर सरकार ने आपकी सुध ली..?

जवाबः अरे बाबा... लो कमाल है. ऐसे खतरनाक लोगों की कोई सुध लेगा? नीति-नैतिकता की अवहेलना पर हम कब किसको क्या बोल देंगे, उसकी कोई गारंटी है क्या? देखो, हम तो जयप्रकाश नारायण के साथ भी रहे हैं. चंद्रशेखर जी जरूरत से ज्यादा मुझको प्रेम और आदर करते थे. विश्वनाथ प्रताप जी और नेहरू परिवार से भी मुझको बहुत प्रेम मिला. लेकिन अपनी कोई महत्वाकांक्षा इच्छा तो रही नहीं. हमलोग अपने विचार के मुताबिक ही जीते रहे! आप हमको क्या दोगे, इस बारे में कभी सोचा नहीं, हम आपको क्या दे सकते हैं, इसके बारे में ही सोचते रहे और करते रहे. इच्छा तो यही रही कि मुझसे जितना हो सके, उतना ले लो. देखिए हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तो व्यक्ति से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है. आपसे हम मिल लिए तो हमारे मन में आपसे मिलने की इच्छा हमेशा बनी रहे, हमसे आप मिल लिए तो आपके मन में हमसे मिलने की इच्छा बनी रहे... इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है. कागजों पर पुरस्कार की परंपरा थी, कागज का जमाना था, उसे तो अब तक दीमक खा गया होगा. मेरी नजर में न तो उस पुरस्कार का कोई मतलब था और न आज के पुरस्कार का कोई मतलब है. ■

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

दुर्भाग्य से देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है. लोगों ने इस सरकार को इस उम्मीद के साथ चुना था कि महंगाई पर लगाम लगेगा और ढेर सारे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. ऐसे लोग आज वास्तव में सरकार से बहुत निराश हैं. ये दोनों चीज़ें आसान नहीं हैं. लोगों की जेब में अधिक पैसा आ जाने से वे वैसा भोजन ख़रीद पा रहे हैं जो पहले नहीं ख़रीद सकते थे, इसलिए महंगाई कम करना आसान नहीं होगा. लेकिन जहां तक रोज़गार का सवाल है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है जिसके द्वारा सरकार औद्योगिक रोज़गार पैदा कर सकती है और वह है सार्वजनिक क्षेत्र में भारी निवेश. यदि सरकार यह सोच रही है (और इसमें रघुराम राजन, अरविन्द सुब्रमण्यन और अमेरिकी सिद्धांत शामिल हैं) कि आप सब कुछ मुक्त कर दीजिए और प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा.

काम कम, शोर ज्यादा

आजकल राजनीतिक गतिविधियां उतनी नहीं हो रही हैं, जितनी अलग-अलग विषयों (जिनमें से कुछ प्रासंगिक हैं और कुछ अप्रासंगिक) पर ज्यादा शोरगुल हो रहा है. वित्त मंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी मानसून सत्र में पास कराया जाएगा, जो अच्छी बात है. लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं. पहली, पेट्रोल और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. मेरे विचार से एक खराब जीएसटी, किसी जीएसटी के नहीं होने से ज्यादा बुरा है. जो भी हो जीएसटी किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में लागू है और यह एक तरह का कर सुधार है. सरकार जो भी करेगी हम आगे की ओर ही जाएंगे. लेकिन यह धारणा बनाई जा रही है कि जीएसटी के पारित नहीं होने से अर्थव्यवस्था में रुकावट आ गई है और एक बार जीएसटी पारित हो गया तो अर्थव्यवस्था में उछाल आ जाएगा. यह बिल्कुल बेतुकी बातें हैं. जीएसटी एक तरह का कर सुधार है. व्यापार जगत हमेशा चाहता है कि कर व्यवस्था आसान हो, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, उससे तो व्यापार जगत में विश्वास नहीं पैदा होगा.

इसके उलट उन्हें करना यह चाहिए था या अब भी कर सकते हैं कि उन्हें केंद्रीय वैट की तरह केंद्रीय जीएसटी लाना चाहिए. इसके लिए उन्हें न तो राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी, न ही संविधान संशोधन और न ही कांग्रेस की सहायता की. केन्द्र सरकार वैट लागू कर राज्यों पर छोड़ देती कि वे चाहें तो इसे अपना लें और इसके बाद समय के साथ उस पर आम सहमति बन जाए. लेकिन सरकार फिलहाल इसे लेकर आश्वस्त है. देखते हैं आगे क्या होता है?

दूसरी बात मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का तेज़ स्वर में बोलना है. वे ऐसा केवल अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हैं. उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा क्षेत्र के मामलों की अधिक जानकारी नहीं है. लेकिन एक मंत्री, मंत्री होता है. उसे पीएमओ और नौकरशाही के सलाह पर काम करना होता है. वे अच्छा कर सकती हैं अगर वे निष्पक्ष होकर और अधिक ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, जैसा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के शुरू में किया था. मैं समझता हूं कि फिलहाल वे आगे निकलने की जल्दबाज़ी में हैं. वे चाहती हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, जो फिलहाल मुश्किल लग रहा है. इसमें कोई शक नहीं कि वे भाजपा के लिए सफल उम्मीदवार नहीं हो सकती हैं.

सुब्रमण्यम स्वामी, आरबीआई के गवर्नर को हटाने की बात कर रहे हैं. यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था. आरबीआई गवर्नर कोई निर्वाचित पद नहीं है. यह सरकार का प्रशासनिक दायित्व है कि वह रिज़र्व बैंक के गवर्नर को नियुक्त करे. सरकार उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर कोई फैसला ले सकती है. लेकिन इस सिलसिले में दोनों तरह की धारणाएं गलत हैं कि रघुराम राजन की नियुक्ति देश को एकदम आगे ले जाएगी या उनकी जगह किसी और की नियुक्ति से भारतीय अर्थव्यस्था का विश्वास डगमगा जाएगा. भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है. आरबीआई गवर्नर पर तो कतई नहीं. आरबीआई का काम मौद्रिक नीति और ब्याज दर की निगरानी करना होता है ताकि महंगाई की दर को क़ाबू में रखा जा सके. उनके काम का दायरा बहुत सीमित होता है. लिहाज़ा यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपर इतना ध्यान दिया जाए.

एक और मुद्दा है, कुछ लोग गाय के नाम पर एक मंत्रालय बनाने की मांग कर रहे हैं. अगर हमें आर्थिक विकास की राह पर

> सुब्रमण्यम स्वामी, आरबीआई के गवर्नर को हटाने की बात कर रहे हैं. यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था. आरबीआई गवर्नर कोई निर्वाचित पद नहीं है. यह सरकार का प्रशासनिक दायित्व है कि वह रिज़र्व बैंक के गवर्नर को नियुक्त करे. सरकार उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर कोई फैसला ले सकती है. लेकिन इस सिलसिले में दोनों तरह की धारणाएं गलत हैं कि रघुराम राजन की नियुक्ति देश को एकदम आगे ले जाएगी या उनकी जगह किसी और की नियुक्ति से भारतीय अर्थव्यस्था का विश्वास डगमगा जाएगा.

चलना है तो धर्म, आरएसएस, वीएचपी को पीछे छोड़ देना होगा. एक समय था जब भारतीय गायों की गिनती अच्छी नस्ल की गायों में होती थी. गीर, थरपारकर, साहिवाल इत्यादि गायें उत्तम नस्ल की मानी जाती थीं. ये गायें जो दूध देती थीं उसमें ए2 प्रोटीन होता था, जो दुनिया के किसी और नस्ल की गाय की दूध में नहीं मिलता था. न तो जर्सी और न ही किसी दूसरी आयातित गाय में. दरअसल, ब्राजील भारत से बहुत सी गीर गायें अपने देश ले गया. मैं समझता हूं कि ब्राजील के पास गीर गायों की अच्छी संख्या है और वे आगे भी इसकी नस्ल बढ़ा रहे हैं ताकि ए2 श्रेणी का अच्छा दूध मिल सके. हमें ऐसे देशों से सीखना चाहिए कि हम अपनी गायों की नस्ल कैसे सुधारें और दूध की पैदावार को कैसे बढ़ाएं. हमारे साथ समस्या यह है कि हम विदेशों की नकल करने लगे हैं. आस्ट्रेलिया से जर्सी गायें आने लगीं और हमारी अपनी उत्तम नस्ल की गायों की देश में अनदेखी होने लगी. लिहाज़ा इस पर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे एक अलग मंत्रालय बना कर, एक विभाग बना कर या कोई मिशन शुरू कर. देश में कई डेयरी इन्स्टीट्यूट हैं, जहां बेहतर अनुसंधान कार्य हो रहे हैं. करनाल में एक डेयरी इन्स्टीट्यूट है, ऋषिकेश में एक इन्स्टीट्यूट है, जहां बहुत काम हो रहा है. फिलहाल सरकार यह कर सकती है कि ऐसे सभी संस्थानों को एक महानिदेशक के मातहत कर एकीकृत कर दिया जाए. बेशक यह एक ऐसा मसला है जिसपर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस क्षेत्र में निवेश की भी आश्यकता है. साथ ही इस क्षेत्र में फोकस रिसर्च की भी ज़रूरत है. हमें आशा करनी चाहिए कि इस दिशा में कुछ काम होगा.

दुर्भाग्य से देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है. लोगों ने इस सरकार को इस उम्मीद के साथ चुना था कि महंगाई पर लगाम लगेगा और ढेर सारे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. ऐसे लोग आज वास्तव में सरकार से बहुत निराश हैं. ये दोनों चीज़ें आसान नहीं हैं. लोगों की जेब में अधिक पैसा आ जाने से वे वैसा भोजन खरीद पा रहे हैं जो पहले नहीं खरीद सकते थे, इसलिए महंगाई कम करना आसान नहीं होगा. लेकिन जहां तक रोज़गार का सवाल है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है जिसके द्वारा सरकार औद्योगिक रोज़गार पैदा कर सकती है और वह है सार्वजनिक क्षेत्र में भारी निवेश. यदि सरकार यह सोच रही है (और इसमें रघुराम राजन, अरविन्द सुब्रमण्यन और अमेरिकी सिद्धांत शामिल हैं) कि आप सब कुछ मुक्त कर दीजिए और प्राइवेट सेक्टर आ जायेगा. कौन सा प्राइवेट सेक्टर? भारत में जब भी आप पब्लिक सेक्टर के किसी यूनिट का विनिवेश करते हैं, तो यहां पांच घराने हैं जिनके पास पैसा है उन्हें खरीदने के लिए. यही भारतीय प्राइवेट सेक्टर है. अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, रक्षा सामान बनाया जा सकता है, तो यह काम पब्लिक सेक्टर को करना चाहिए. जैसे 1960 के दशक में स्टील प्लांट लगाए गये थे. दो-तीन बड़ी रक्षा कंपनियां बनाइए, चाहे जहां से भी मदद लेनी पड़े, अमेरिका चीन या कहीं से भी, लेकिन अपनी चीज बनाइए ताकि पैसे की बचत हो . यह काम सरकार को करना है. अगर आप लार्सन टूब्रो, अंबानी या अडानी से यह काम कराना चाहते हैं तो इसके लिए लंबा इंतज़ार करना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

पैरवी नहीं तो जज नहीं

कवर स्टोरी-जजों की नियुक्ति के लिए बनी सूची में न्यायाधीशों के बेटों और रिश्तेदारों की भरमार, पैरवी में है दम, जज बनेंगे हम (13 जून- 19 जून 2016) पढ़ा. प्रभात रंजन दीन ने बिल्कुल सही कहा है कि जब न्यायाधीश ही अपने नाते-रिश्तेदारों और सरकार के प्रतिनिधि-पुत्रों को जज नियुक्त करेंगे तो संविधान का संरक्षण कैसे होगा? जब न्यायालय में यह गोरखधंधा चल रहा है, तो बाकी जगहों की बात ही अलग है. सरकारी नौकरी हो, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का मामला हो या कोई और सच्चाई तो ये है कि हर जगह पैरवी पर ही नियुक्तियां हो रही हैं. यह एक सच्चाई है जिसे झूठा साबित नहीं किया जा सकता है. देश की जनता इन पैरवी वाले जजों से न्याय की उम्मीद भला कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से देश की जनता को उम्मीद है. अगर सरकार लापरवाही बरतती है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान हमेशा सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर उसे अपना उत्तरदायित्व याद दिलाने का काम करती है. अब लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट को इन पैरवी वाले जजों की नियुक्ति पर भी बोलना चाहिए.

-सौरभ कुमार, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

पुलिस की बर्बरता

आलेख-शांति दूतों पर पुलिसिया हमला (13 जून-19 जून 2016) पढ़ा. लेखक ने इस आलेख के जरिए बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के हालात यहां से कितने जुदा हैं. पुलिस की बर्बरता एक बेहद गंभीर मसला है. अरुणाचल में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं और आंदोलनकारियों की बर्बर तरीके से पिटाई की गई. अरुणाचल प्रदेश की पुलिस हो या कहीं और सभी जगहों की पुलिस का यही हाल है. हर जगह की पुलिस की बर्बरता न्यूज चैनलों और अखबारों में पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन पूर्वोत्तर की एक भी खबरें न न्यूज चैनलों पर दिखती है और न ही अखबारों में. अरुणाचल प्रदेश में लोगों के हितों के खिलाफ निजी कंपनियां और सरकारी महकमे काम करे रहे हैं जिसके खिलाफ वहां के लोगों ने आवाजें उठाईं, तो उन्हें पुलिस की लाठियां खाने को मिलीं. साथ ही लाठियों के बल पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई. आखिर वहां की जनता अपना दर्द किससे कहे? वहां के लोगों की न केंद्र सरकार सुनती है और न ही राज्य सरकार. वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार को मीडिया भी नहीं दिखाता.

-बिमलेश राय, *मोतिहारी, बिहार.*

जनता में निराशा है

आलेख-असम की जीत भाजपा के लिए उत्साहजनक (13 जून- 19 जून 2016) पढ़ा. लेख काफी विचारोत्तेजक है. मेघनाद देसाई ने सही कहा है कि जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, मोदी अब भी पहले पायदान पर हैं, इसके बावजूद विकास की सुस्त रफ्तार के कारण लोगों में निराशा है. दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार करारी हार के बाद भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी. विपक्षी दल कहने लगे थे कि अब मोदी की हवा निकल गई है और जनता में मोदी सरकार को लेकर निराशा का माहौल है. लेकिन असम की जीत ने विपक्षी दलों का मुंह बंद कर दिया और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में उत्साह भर दिया. लेकिन हालात ये हैं कि भाजपा में तो उत्साह है लेकिन जनता निराश है. महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, रोजगार न मिलने से युवाओं में निराशा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हम महंगाई को 100 दिन के अंदर खत्म कर देंगे. मोदी सरकार को सत्ता में आए दो साल हो गए हैं, इसके बाद भी महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ गई है. सरकार को जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और अपने वादे को पूरा करना चाहिए.

-कोमल गुप्ता, *शहादरा, दिल्ली.*

आप का विवादों से नाता

केजरीवाल सरकार हमेशा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर किसी न किसी बहाने हमला करती रहती है. अरविंद केजरीवाल ने आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्ति किया था, जो लाभ के पद के दायरे में आता है. यह संसदीय सचिव भले ही सैलरी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऑफिस और गाड़ियों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि वह कोई लाभ नहीं ले रहे हैं. आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लगा कि उन्होंने गलती कर दी है. इसलिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा में संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने से संबंधित विधेयक पास कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने सरकार के इस विधेयक को मंजूरी देने से इंकार कर दिया. अब इस विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी न मिलने की वजह से आप के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है. केजरीवाल कई राज्यों और पार्टियों को गिना रहे हैं कि उन्होंने भी संसदीय सचिव रखे हैं और दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी संसदीय सचिव रखा था. अब इस मामले में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को फैसला लेना है और इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती. केजरीवाल और उनकी पार्टी का विवादों से नाता है. उन्हें बस मोदी और केंद्र को गाली देने का मौका मिलना चाहिए.

-गौरव वर्मा, *गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.*

ध्रुवीकरण की कोशिश

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं. इस समय कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें आ रही हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि अलग-अलग अखबारों और न्यूज चैनलों में पलायन को लेकर भी अलग-अलग खबरें मिल रही हैं. इससे पहले देश में राम मंदिर का मुद्दा भी खूब गर्म हुआ था. उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम है. इसलिए राम मंदिर और कैराना मुद्दे को हवा दी जा रही है. पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेता राम मंदिर को लेकर लगातार बयान दे रहे थे, जैसे दिसंबर, 2016 में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी वगैरह-वगैरह. इसके बाद अब कैराना को लेकर भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं. भाजपा के सांसद हुकम सिंह ने एक रिपोर्ट पेश की और हिंदुओं के पलायन की बात कही. राम मंदिर और कैराना को लेकर आजकल जो भी देश में हो रहा है, वह केवल चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. लेकिन, भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि अब देश की जनता गोमांस, राम मंदिर या कैराना जैसे मुद्दों के झांसे में नहीं आने वाली है.

-विनीत यादव, *दानापुर, बिहार.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है

कांग्रेस देश में सशक्त विपक्षी दल की भूमिका निभा सकती है, लेकिन पता नहीं वो कौन सा कमजोर बिंदु है या कमजोर नस है, जिसकी वजह से कांग्रेस सशक्त विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभाना चाहती. राहुल गांधी पर कांग्रेस के नेतृत्व की जिम्मेदारी है, लेकिन वे इन दिनों फिर देश से बाहर हैं. कहा जा रहा है कि वे छुट्टी मनाने के लिए बाहर गए हैं. वे काम पर कब होते हैं, इस सवाल का कभी जवाब नहीं मिलता. काम पर होने का मतलब कांग्रेस पार्टी को सांगठनिक रूप से मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करना और चुनाव जीतने के लिए जिस जुनून की जरूरत होती है उसे पैदा करना है. कम से कम राहुल गांधी इस काम पर लगे तो नहीं दिखाई देते हैं.

अगर पिछले दो-तीन चुनावों को देखें, तो बिहार चुनाव में जब कांग्रेस को दस से कम सीटें मिली थीं, तब उत्तर प्रदेश का चुनाव दो साल बाद होना था. अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पर ध्यान देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. संगठन वैसा का वैसा ही खड़ा रहा. उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और दो तिहाई के आस-पास सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया. लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की और बुरी हालत हो गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन में कोई जान नहीं फूंकी और कार्यकर्ताओं के सामने कोई टारगेट ही नहीं रखा. संयोग से बिहार के चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस नीतीश कुमार के सहारे 27 सीटें पाने में कामयाब हो गई. इसके बाद असम के चुनाव आए और इसमें कांग्रेस को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी. इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख सकती. कांग्रेस को रणनीति के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संभावित साथियों को तोड़कर अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे दो तिहाई बहुमत मिलने वाला हो. असम में शान के साथ पहली बार भाजपा की सरकार बन गई.

उत्तर प्रदेश का चुनाव 6 महीने बाद है, पर कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश को लेकर कोई चिंता नहीं है. उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता अनाथों की तरह चारों तरफ घूम रहे हैं. कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि वे अपनी समस्या किसके सामने रखें ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम चुनाव की बात करने लायक तो कोई बनाए. कांग्रेस को प्रशांत किशोर, जो इन दिनों मीडिया में देश के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं या उन्होंने स्वयं को स्थापित कर लिया है, में अपना तारणहार दिख रहा है. फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता जैसा प्रशांत किशोर की सलाह मिल रही है, वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन संगठन अब भी वहीं का वहीं है. जिन राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस को सक्रिय करने की जिम्मेदारी है, वे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को कहीं नहीं दिख रहे हैं. शायद राहुल गांधी ये सोचते हैं कि चुनाव आएगा, वे पांच सभाएं करेंगे और कांग्रेस जीत जाएगी. हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आज तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीतना दिवास्वप्न सा लग रहा है.

उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को भी कांग्रेस नेतृत्व सौंपने की चर्चाएं हैं उनसे जब पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि हमसे तो किसी ने बात ही नहीं की. अखबारों में इस तरह की खबरें चल रही हैं. सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वे भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं या जो कांग्रेस को समझते हैं उन्हें बुलाकर न तो कोई काम सौंप रही हैं और न ही कार्यकर्ताओं में कोई जान फूंकती नजर आ रही हैं. बाकी जितने नेता हैं, वे राज्यसभा के नेता हैं उन्हें कांग्रेस के चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है, वे राज्यसभा में 6 साल के लिए हैं. वे राहुल गांधी से बात करते हुए डरते हैं, वे सोनिया गांधी से बात करते हुए डरते हैं. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हवा में तैरती उस पतंग की तरह है जिसकी डोर है ही नहीं. हवा में उलझ रही है, लड़खड़ा रही है, बिखर रही है, तैर रही है, तब तक जब तक कि वह नीचे न गिर जाए.

उत्तर प्रदेश में एक रणनीति के तहत यह आम राय बनी है कि शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए. संजय सिंह को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जाए और नवंबर से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के हर कोने में चुनाव प्रचार शुरू करें. एक खबर के मुताबिक चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में दिसंबर में चुनाव कराना चाहता है और इसके लिए उसे प्रमुख पार्टियों की सहमति भी मिल चुकी है.

अगर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं और अक्टूबर या नवंबर में कोई नया समीकरण, कोई नई टीम, कुछ नए लोग चुनाव जिताने के लिए जिम्मेदार बनाए जाते हैं, तो भला वे क्या कर पाएंगे. उनके सामने पहाड़ जैसी मायावती, चीते जैसे मुलायम सिंह और इन दोनों को पछाड़ने की तैयारी में भाजपा रास्ता रोके खड़ी है. कांग्रेस इन तीनों में किसे हराने की योजना बनाएगी, यह अभी तक कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है.

> **उत्तर प्रदेश का चुनाव 6 महीने बाद है, पर कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश को लेकर कोई चिंता नहीं है. उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता अनाथों की तरह चारों तरफ घूम रहे हैं. कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि वे अपनी समस्या किसके सामने रखें ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम चुनाव की बात करने लायक तो कोई बनाए. कांग्रेस को प्रशांत किशोर, जो इन दिनों मीडिया में देश के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं या उन्होंने स्वयं को स्थापित कर लिया है, में अपना तारणहार दिख रहा है.**

बहरहाल कांग्रेस उत्तरप्रदेश में खुद विषादग्रस्त है. उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उसके सामने हार के सिवाय कोई चारा नहीं है, जबकि गांवों में कांग्रेस की हालत इतनी बुरी नहीं है. वहीं अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में चुनाव केंद्रों पर 10 से 15 कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने की रणनीति बनाकर और राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार बनाने का इशारा कर कांग्रेस में एक नया डर पैदा कर दिया है. मायावती ने भी अमित शाह की तर्ज पर हर चुनाव केंद्र पर बीस कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी है. वहीं समाजवादी पार्टी के पास भी हर चुनाव क्षेत्र पर दोबारा सत्ता पर कब्जा करने का जज्बा लिए कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है. इनका मुकाबला कांग्रेस अगर अक्टूबर में अपना प्रचार अभियान शुरू कर करना चाहती है, तो कांग्रेस से बड़ी महान और बुद्धिमान पार्टी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है.

बहरहाल अब कांग्रेस के पास वक्त नहीं है. अगर वक्त है तो यही कि कांग्रेस जुलाई में अपनी नई रणनीति, नए नेता व कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाले लोग और पड़ोस के प्रदेशों के सारे लोगों, जो स्थानीय लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, को जुलाई तक काम सौंप दे. अगर वह ऐसा नहीं करती तो कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश में न विधानसभा का चुनाव जीतेगी और न 2019 में लोकसभा के चुनाव में कुछ कर पाएगी.

कोई अगर बता सके, जिसकी आशा कम है, तो वह सोनिया और राहुल गांधी को बताए कि उत्तर प्रदेश की इस स्थिति में दूसरे के लिए करो या मरो का नारा आज नहीं है. आज खुद उनके लिए करो या मरो का सवाल खड़ा हो गया है. अगर उत्तर प्रदेश में वे कुछ भी करना चाहते हैं, तो उन्हें आज करना होगा. वरना मायावती या मुलायम सिंह नहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कांग्रेस को अपना भोजन बनाने का काम करेगी. तब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इतिहास के पन्नों पर कैद होने वाली एक ऐसी पार्टी बन जाएगी जिसने कई मुख्यमंत्री तो दिए, लेकिन अब उसके पास कार्यकर्ता और नेता देने की भी ताकत नहीं बची है. ■

editor@chauthiduniya.com

भारत-अमेरिकी रिश्तों के लिए राजनीतिक-सांस्कृतिक तालमेल ज़रूरी

मेघनाद देसाई

नरेन्द्र मोदी के हालिया अमेरिका दौरे ने दो महान लोकतांत्रिक देशों के बीच 70 साल से रिश्तों में चली आ रही कड़वाहट और गैर जरूरी विवादों को दूरकर पटरी पर ला दिया है. अमेरिका के नवोदय (अपस्टार्ट) के दौरान ब्रिटेन के संभ्रांत वर्ग में व्याप्त पूर्वग्रहों से जवाहरलाल नेहरू खुद को कभी निकाल नहीं पाए. प्रथम विश्व युद्ध से कुछ समय पहले जब वे एक छात्र थे, तब ब्रिटेन एक महान शक्ति था. उस दौर में अमेरिका ने धीरे-धीरे विकास की राह पर कदम बढ़ाना शुरू किया था. जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तब तक शीत युद्ध शुरू हो चुका था. अमेरिका की सोच थी कि एक लोकतांत्रिक देश की हैसियत से भारत स्वयं उसके खेमे में आ जाएगा. हालांकि युवा नेहरू का कमइन्टर्न के सम्राज्यवाद विरोधी विचारों से हमेशा एक जुड़ाव था, जिसपर अमेरीकियों ने कभी गौर नहीं किया. 1920 के दशक के आखिर में ब्रसेल्स कॉन्फ्रेन्स के दौरान कमइन्टर्न से नेहरू का जुड़ाव हुआ था. लिहाजा, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई. इस नीति का झुकाव सोवियत संघ की ओर था. गुटनिरपेक्ष आंदोलन अमेरिका के प्रति हमेशा उदासीन रहा. दुर्भाग्यवश नेहरू-महालनोविस के दिनों की आर्थिक नीति ने देश के कृषि क्षेत्र की अनदेखी की, जिसके कारण भारत को अमेरिका से सहायता लेनी पड़ी. नेहरू को अमेरिका के पीएल 480 के तहत सहायता स्वरूप दिए जाने वाले गेहूं की जरूरत पड़ी. इसके बावजूद अहंकार ने साम्राज्यवादी अमेरिका को धन्यवाद देने से रोक दिया और भारत का सोवियत संघ द्वारा हंगरी के विद्रोह और पराग स्प्रींग को कुचले जाने का समर्थन जारी रहा.

हालात तब और गंभीर हो गए, जब चीन के साथ सीमा युद्ध में भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी. नेहरू और अन्य राजनेता लड़ाकू जहाज व सामरिक सहायता के लिए अमेरिकी दूतावास गए. वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मौत उसी दिन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भारत का कोई भी गुटनिरपेक्ष मित्र सहायता के लिए आगे नहीं आया. लेकिन ऐसी बातों को अक्सर भुला दिया जाता है. इंदिरा गांधी पीएल 480 सहायता लेती रहीं, लेकिन उनका अमेरिकी विरोध भी जारी रहा. भारत में वामपंथ के समर्थन से साम्राज्यवाद विरोधी आलोचना का दौर भी चलता रहा और समय के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन अमेरिका विरोधी मोर्चे में बदल गया. अमेरिका के वियतनाम में खूनी खेल ने हालात और बदतर बना दिए, लेकिन इस दौरान भी आर्थिक सहायता जारी रही. नेहरू-गांधी परिवार का ब्रिटिश प्रेम जगजाहिर था, साथ में अमेरिका के लिए उनकी उपेक्षा की भावना भी जीवित रही. जब देश में हरित क्रांति का आगमन हुआ तो रॉकफेलर फाउंडेशन की भूमिका को महज़ नाम के लिए ही स्वीकार किया गया.

अमेरिका का अन्य देशों के प्रति साम्राज्यवादी व्यवहार का दौर जारी रहा. इसी दौरान सोवियत संघ का विघटन हो गया. अब शीत युद्ध अमेरिका के विजय के साथ समाप्त हो गया था. इसके बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन जारी रहा. ज़ाहिर है इसके पीछे एक दर्शन था. भाजपा/एनडीए की पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य बनाने का प्रयास किया. इसके बावजूद परमाणु परीक्षण और एनपीटी पर हस्ताक्षर से इंकार ने भारत को अमेरिका से दूर कर दिया.

मनमोहन सिंह पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ व्यक्तिगत घनिष्ठता स्थापित की. मनमोहन सिंह को बाइबिल की गहरी जानकारी थी. उनकी आर्थिक और कई अन्य विशेषताओं से बुश खासे प्रभावित थे. बुश ने एनएसजी के प्रतिबन्ध से भारत को मुक्त कराने में मदद की. ऐसा करने के लिए मनमोहन सिंह को देश में वामपंथ के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी जगह पर डटे रहे. वामपंथ का यह फैसला आत्मघाती साबित हुआ. वामपंथ राहुल गांधी की मदद के बावजूद इस नुकसान से अभी तक बाहर नहीं निकल सका है.

मोदी अब उस रिश्ते को और मज़बूती दे रहे हैं. इस दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके पास ओक्सब्रीज का कोई पूर्वग्रह नहीं है. उन्हें स्वाभाविक रूप से अमेरिका से लगाव है. अमेरिका ने 1960 के दशक के मध्य में अपनी इमिग्रेशन नीति में बदलाव किया, जिसका फायदा बहुत सारे भारतीय परिवारों को मिला. अमेरिका में कई भारतीयों ने सुख-समृद्धि हासिल की. उनमें से बहुतों ने मोदी का तब साथ दिया जब वे कांग्रेस द्वारा तिरस्कृत किए जा रहे थे. अब दोनों देशों के बीच रिश्तों की ठोस बुनियाद स्थापित हो चुकी है. अमेरिका में भारत के दो सबसे बड़े क्रांतिकारी नेताओं बीआर अम्बेडकर और जय प्रकाश नारायण ने शिक्षा हासिल की थी. हालांकि दोनों देशों के बीच अभी और सांस्कृतिक और राजनीतिक तालमेल की जरूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

तैयारी अधूरी
बाढ़ मचाएगी तबाही

बाढ़ व अकाल की मार से उत्तर बिहार दशकों से परेशान रहा है, लेकिन अबकी बार जो हालात लोगों के सामने हैं. उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर बाढ़ आई तो भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के जिलों में भारी तबाही मच सकती है. विशेषज्ञों की बातों पर अगर यकीन करें, तो कोई ऐसी नदी नहीं है जो बाढ़ की तबाही को अपने ही गर्भ तक सीमित रख सके. एक तरफ सरकार ने करोड़ों की लागत से नदियों पर बांध का निर्माण कर उन्हें बांधने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ नदियों में जमा गाद अब तटबंधों के लिए ख़तरा बनने लगा है. सूखे की मार झेल रहे किसानों की समस्या कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही है. समय पर पानी नहीं मिलने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, अब बाढ़ की संभावित तबाही को लेकर किसान सशंकित हैं

अमृता/गोविंद

उत्तर बिहार से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, करेह व अधवारा समूह की नदियां ऐसी हैं जिसमें बाढ़ की सूचना मात्र से लोगों को भारी तबाही का डर सताने लगता है. लगभग डेढ़ दशक से बाढ़ की तबाही को लेकर लोग हमेशा परेशान रहते हैं. हर वर्ष बाढ़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है. लोगों के घर पानी में समा जाते हैं और लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं. अब सवाल यह उठता है कि आखिर नदियां क्यों घातक होती जा रही हैं? तटबंधों की स्थिति कैसी है? इन सवालों के जवाब भी जानना जरूरी है.

बाढ़ आते ही हर दिन बाढ़ से विनाशलीला की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनने लगती हैं. बाढ़ की तेज धारा में बहकर सैकड़ों लोग असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं. बाढ़ की वजह से भारी जान-मान माल का नुकसान होता है, लेकिन पीड़ितों को सरकारी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं मिलता. ऐसे हालात में लोगों का चिंतित होना जायज है. नदियों द्वारा विकराल रूप धारण करने के लिए विशेषज्ञ सरकारी तंत्र को दोषी करार देते हैं. वजह यह है कि सरकारी स्तर पर नदियों को बांधने का कार्य किया गया है. नदियों के गर्भ में गाद जमा होने की वजह से उनकी गहराई कम होती जा रही है जिसकी वजह से बाढ़ के समय जब नदी में पानी बढ़ता है, तो जगह-जगह तटबंधों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है. अगर कहीं तटबंध टूट गए तो संबंधित क्षेत्र में होने वाली तबाही को कोई रोक नहीं सकता.

दूसरी ओर अब नदियों के गर्भ से निकलने वाली गादें किसानों के खेतों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता जा रहा है. नतीजतन ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी है और किसानों का खेती से मोह भंग होने लगा है. वर्तमान में नेपाल से आने वाली कुछ नदियों को अगर छोड़ दिया जाए, तो शायद ही कोई ऐसी नदी है, जिसके गर्भ में सिल्ट न जमा हो. खासकर उत्तर बिहार में तबाही का पर्याय रही बागमती नदी को उदाहरण के तौर देखा जा सकता है. नेपाल से शिवहर होते हुए सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले को पार कर दरभंगा की सीमा तक आने वाली यह नदी तबाही का दूसरा रूप है. अगर पिछले डेढ़ दशक के आंकड़ों को देखें, तो इस नदी ने शिवहर और सीतमढ़ी जिले के दर्जनों गांव का नक्शा बदल दिया है. वर्तमान में हाल यह है कि शिवहर जिले के डुब्बा घाट के समीप नदी के गर्भ में भी पानी सूखने लगा है. इसके बावजूद लोगों के मन में नदी के रौद्र रूप धारण करने का खौफ कायम है. वहीं दूसरी ओर नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की हरदी, रातो, मरहा समेत अन्य नदियों में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ का खामियाजा सीतामढ़ी जिले के सुरसंड, सोनबरसा, पुपरी समेत कई प्रखंडों की जनता को भुगतना पड़ता है. सुरसंड के श्रीखंड भिट्ठा गांव के आस-पास के लोगों को बाढ़ की वजह से हर वर्ष महीनों के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है. बाढ़ की वजह यह है कि नेपाल सरकार ने अपनी रक्षा के लिए भारतीय सीमा से पहले बांध का निर्माण किया है, जिसकी वजह से नदियों में बाढ़ आने की वजह से बिहार में बाढ़ का पानी आते ही बेकाबू हो जाता है और भारतीय क्षेत्र के लिए काल का रूप ले लेता है. पहले से तैयारी न होने की वजह से जब तक सरकारी और प्रशासनिक स्तर बचाव कार्य शुरू किया जाता है, तब तक लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं. उसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा राहत की राजनीति शुरू हो जाती है जो बाढ़ की समय अवधि तक जारी रहती है. बाढ़ समाप्त होने के बाद राजनीतिक दलों को कुछ याद नहीं रहता. जनता मदद का इंतजार करती रहती है कि कोई तो उनकी मदद करेगा. समस्तीपुर जिले में बुढ़ी गंडक में कई सालों से सीमित पानी आने की वजह से लोगों ने नदी के अंदर तक मकानों निर्माण करा लिया है जो आने वाले समय में तबाही का कारण बन सकता है. सीतामढ़ी में भी लक्ष्मणा नदी का हाल यही है.

जहां तक तटबंधों के रख-रखाव का सवाल है तो प्रतिवर्ष तटबंधों की मजबूती और बेहतरी के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन यह करोड़ों रुपये तटबंधों के रख-रखाव के स्थान पर सरकारी तंत्र और ठेकेदारों की जेब में चले जाते हैं. तटबंधों का कभी भी पूरी तरह से मरम्मत नहीं कराया जाता है. शिवहर जिले के डुब्बा घाट के समीप कुछ खनन माफिया प्रशासन की मिलीभगत से बागमती नदी पर बने पुल के समीप तक मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं. अगर बाढ़ आती है, तो पुल के क्षतिग्रस्त होने का भी डर है. लेकिन स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है. सीतामढ़ी जिले में जर्जर हो चुके बागमती नदी पर बने तटबंध की मरम्मत सरकारी मानकों की अनदेखी कर हो रही है, क्योंकि कई स्थानों पर तटबंध के समीप से ही मिट्टी काटकर बांध की मरम्मत की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार बांधों का मरम्मत करा रही है या उसे कमजोर कर टूटने का इंतजाम कर रही है. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में बहने वाली नदियों की गहराई बहुत कम हो गई है जिसकी वजह से नदियों के गर्भ की जमीन दिखाई देने लगी है. अगर इन नदियों में बाढ़ आती है, तो तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता. इसलिए समय रहते ही सरकार को इस समस्या का हल निकालना होगा जिससे लोगों को जान-माल का नुकसान न हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रतिवर्ष तटबंधों की मजबूती और बेहतरी के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन यह करोड़ों रुपये तटबंधों के रख-रखाव के स्थान पर सरकारी तंत्र और ठेकेदारों की जेब में चले जाते हैं. तटबंधों का कभी भी पूरी तरह से मरम्मत नहीं कराया जाता है. शिवहर जिले के डुब्बा घाट के समीप कुछ खनन माफिया प्रशासन की मिलीभगत से बागमती नदी पर बने पुल के समीप तक मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं.

Mob. : 9386745004, 9204791696

www.iiher.org, Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH

Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.

(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)

AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus - Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ

निदेशक प्रमुख

सांसद आदर्श गांवों की नहीं बदली तस्वीर

गोद लिए गांवों की सांसदों ने नहीं ली सुध

घोषणा के कुछ दिनों बाद इन गांवों में सांसदों ने ग्रामीणों को बताया कि आपके सहयोग व सरकारी योजनाओं के सहारे इन गांवों की तस्वीर बदलने वाली है. किसी भी तरह के कार्य के लिए ग्रामीणों को प्रखंड या अन्य किसी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा. लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद भी इन गांवों की तस्वीर जस की तस है.

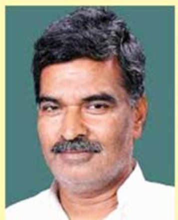
अरुण कुमार

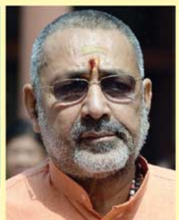
गिरीराज सिंह

सुशील कुमार सिंह

हरि मांझी

औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टिकारी विधानसभा क्षेत्र के केसपा गांव को गोद लिया है. यह गांव मां तारा देवी की प्राचीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है. सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में ग्राम पंचायत की नियमित बैठक, पक्के मकान व सड़क का निर्माण, गलियों और नालियों का पक्कीकरण, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सिंचाई, स्कूल व स्वास्थ्य सेवा की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की बात थी. लेकिन इस गांव में किसी तरह का विकास नहीं हुआ.

सुनील सौरभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित सांसद आदर्श ग्राम योजना का मगध में बुरा हाल है. प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर उसका सर्वांगीण विकास करेंगे. सांसदों ने शुरू में धूमधाम से अपने आदर्श ग्रामों में कार्यक्रम कराकर गांवों को विकसित करने का वादा किया था. इस योजना के घोषित हुए डेढ़ साल से अधिक हो गए, लेकिन इन गांवों की तस्वीर नहीं बदली. समझ सकते हैं कि इन गांवों के विकास में सांसदों की कितनी रुचि है. जब सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत

डेढ़ साल में भी एक गांव का विकास नहीं हो सका, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास की अन्य बातें कितनी सही होंगी. मगध के चार संसदीय क्षेत्र में एनडीए के सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र के चर्चित ऐतिहासिक-धार्मिक गांवों का चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किया था. गया संसदीय क्षेत्र के सांसद हरि मांझी ने बोधगया प्रखंड के बकरौर गांव, औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने टिकारी प्रखंड के धार्मिक महत्व वाले केसपा गांव, जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार ने मखदुमपुर प्रखंड के धराउत गांव, तो नवादा के सांसद और केन्द्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जन्मस्थली खनवां का चयन

किया था. घोषणा के कुछ दिनों बाद इन गांवों में सांसदों ने ग्रामीणों को बताया कि आपके सहयोग व सरकारी योजनाओं के सहारे इन गांवों की तस्वीर बदलने वाली है. किसी भी तरह के कार्य के लिए ग्रामीणों को प्रखंड या अन्य किसी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा. लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद भी इन गांवों की तस्वीर जस की तस है. गया के सांसद हरि मांझी द्वारा गोद लिया गया बकरौर गांव भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा है. तपस्यारत सिद्धार्थ गौतम को इसी गांव की सुजाता ने खीर खिलाया था. इसके कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. यहां खुदाई के दौरान सुजा-तागढ़ नामक बौद्धस्तूप मिला है. 1865 में यहां प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कनिंधम भी आए थे. सांसद ने इस गांव को गोद तो ले लिया, लेकिन कभी इस गांव की सुध नहीं ली. इस गांव में विद्युतीकरण भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है. यहां तक कि ट्रांसफर्मर भी नहीं लगे हैं. 27 चापाकल लगाने की योजना भी हवा-हवाई साबित हुई. निमा-बकरौर पईन का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है. ग्राम कचहरी को अपडेट करते हुए वहां कम्प्यूटराजेइशन होना था, जो अभी तक नहीं हो सका है. 171 बीपीएल परिवारों के लिए आवास निर्माण की योजना भी अधर में है. यहां स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना भी नहीं हो सकी है. बकरौर से मोहनपुर तक जाने वाली सड़क का निर्माण हो चुका है. सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अभी तक केवल इस सड़क का निर्माण कार्य ही हुआ है.

औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टिकारी विधानसभा क्षेत्र के केसपा गांव को गोद लिया है. यह गांव मां तारा देवी की प्राचीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है. सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में ग्राम पंचायत की नियमित बैठक, पक्के मकान व सड़क का निर्माण, गलियों और नालियों का पक्कीकरण, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सिंचाई, स्कूल व स्वास्थ्य सेवा की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की बात थी. लेकिन इस गांव में किसी तरह का विकास नहीं हुआ. प्रखंड व अनुमंडल मुख्यालय टिकारी से केसपा गांव जाने वाली सड़क खस्ताहाल है. विकास कार्य के नाम पर गया के जिला पदाधिकारी की ओर से गांव में लगाने के लिए बीस सोलर लाइटें मिली थीं. इन सभी लाइट्स को भी गांव में जहां-तहां लगाकर केवल खानापूर्ति की गयी. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इस योजना के तहत गोद लेने के बाद गांव की तस्वीर बदल जाएगी. साथ ही

मां तारा देवी की यह प्राचीन भूमि बिहार के चर्चित धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो जाएगी.

नवादा के सांसद व केन्द्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने नरहट प्रखंड के खनवां गांव को गोद लिया है. यह गांव बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जन्मभूमि है. खनवां गांव डॉ. श्रीकृष्ण सिंह का ननिहाल है. वे बचपन में यहीं पढ़े-लिखे थे. दस हजार की आबादी वाले इस गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत घोषित कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है. हालांकि यहां सड़क, बिजली की व्यवस्था पूर्व से ही ठीक ठाक है.

जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार ने अपने संसदीय क्षेत्र के मखदुमपुर प्रखंड के धराउत गांव को गोद लिया है. यह गांव राजा चन्द्रसेन की राजधानी थी. यह गांव बौद्ध धर्म से भी जुड़ा है. इस गांव में खुदाई के दौरान बहुत सी बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं. सांसद के प्रयास से इस गांव में सड़क व पावर सबस्टेशन बना है. उच्च विद्यालय की आधारशिला रखी गई है. इसके साथ ही 52 बीघा के विशाल तालाब को विकसित करने की भी योजना है. इस गांव में सांसद अरुण कुमार के व्यक्तिगत प्रयास से कुछ विकास कार्य हुए हैं. लेकिन प्रशासनिक तथा संबंधित विभागों से समुचित सहयोग नहीं मिलने के कारण कई कार्य अधूरे पड़े हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण विकास की गति तेज करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी. प्रत्येक सांसद को अपने पांच साल के कार्यकाल में कम से कम तीन गांवों को गोद लेकर विकसित करने की योजना थी. हालांकि इस योजना के तहत गांवों में विकास कार्यों के लिए अलग से फंड की घोषणा नहीं होने के कारण अपेक्षित तेजी नहीं आई. संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं से ऐसे गांवों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाने की योजना थी. लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मगध के चार संसदीय क्षेत्र के इन चार गांवों की तस्वीर भी सांसद अपने पांच साल के कार्यकाल में बदल सकें, तो कहा जा सकता है कि उन्होंने कुछ विकास कार्य किया है. लेकिन इन गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार देखकर यह नहीं लगता कि फिलहाल यहां की तस्वीर बदल पाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

मुंगेर पुल

हथियार तस्करों की चांदी

राजेश सिन्हा

दशकों पुरानी जनता की मांग को पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल खगड़िया-मुंगेर रेल सह सड़क पुल का निर्माण कराया, बल्कि अन्य इलाकों के साथ-साथ दियारा इलाके के विकास की नई गाथा भी लिख दी. विकास के साथ-साथ इस इलाके में हथियार तस्करों के द्वारा अपराध की नई गाथा भी लिखी जा रही है. वैसे हथियार तस्करी का खेल पहली बार नहीं शुरू हुआ है. दशकों से जल के रास्ते मुंगेर निर्मित हथियारों की तस्करी का खेल खेला जा रहा है, लेकिन रेल मार्ग अब हथियार तस्करों के लिए सुगम मार्ग बनकर रह गया है. हथियार तस्करी के बारे में शासन से लेकर प्रशासन तक को जानकारी है, लेकिन इस धंधे में लिप्त रसूखदारों की पहुंच इतनी दूर तक है कि शासन-प्रशासन चाहकर भी इन धंधेबाजों पर रोक लगा पाने में नाकाम है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस इस इलाके के न ही जलमार्ग और न ही रेल मार्ग की निगरानी कर पा रही है.

जलमार्ग के जरिए रात्रि में हथियारों की तस्करी होती है, दिन के उजाले में भी नवनिर्मित मुंगेर रेल पुल हथियार तस्करी का सुरक्षित जरिया बन गया है. इतना ही नहीं इस रेल मार्ग पर नियमित चेकिंग की बात तो दूर टिकट चेकिंग की बात भी बेमानी साबित हो रही है, क्योंकि दशकों से अपराध प्रभावित इलाकों में शुमार मुंगेर में किसी भी तरह की चेकिंग करना रेलकर्मी गंवारा नहीं समझते. जलमार्ग के जरिए हो रही हथियारों की तस्करी रोकने की पुलिस ने जब भी कोशिश की तब ग्रामीणों के साथ मिलकर धंधेबाजों ने पुलिस का पुरजोर विरोध किया. मुंगेर रेल पुल के जरिए जिस तरह से हथियार तस्करी का खेल खेला जा रहा है, उसे देखकर यह कहने में शायद कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मुंगेर रेल सह सड़क पुल कहीं तस्करी का पुल न बनकर रह जाए. यह बात अलग है कि अभी फिलहाल सड़क पुल चालू नहीं हुआ है,

इसलिए सड़क मार्ग के जरिए हथियार तस्करी का खेल अभी शुरू नहीं हुआ है. अगर समय रहते पुलिस ने जलमार्ग के साथ-साथ मुंगेर पुल के जरिए हो रही है हथियारों की तस्करी पर विराम नहीं लगाया, तो अक्सर हिंसा की आग में जलने वाला यह इलाका कहीं किसी खूनी खेल का गवाह न बन जाए.

मुंगेर निर्मित हथियारों की बढ़ती मांग को देखते हुए आस-पास के कई दियारा इलाके के गांवों में न केवल अवैध हथियारों का निर्माण हो रहा है बल्कि बिहार के कई जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी इन हथियारों को भेजा जा रहा है. इस दौरान हथियार तस्करों के बीच कई बार हिंसक झड़पें भी हुई और इन झड़पों में कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा. लगभग चौदह वर्षों के लंबे सफर के बाद ही सही लेकिन बीते 12 मार्च 2016 को मुंगेर रेल सह सड़क पुल की शुरुआत होते ही आम जनता चेहरे पर मुस्कराहट आ गई, वहीं तस्करों की भी बल्ले-बल्ले हो गई. लेकिन इस पुल के निर्माण के बाद विकास के कई मार्ग भी खुल गए. इस रेल पुल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ. इस पुल के निर्माण के लिए कई तरह के आंदोलनों का भी इस्तेमाल किया गया. कई चुनाव तक यह पुल प्रत्याशियों के लिए चुनावी मुद्दा बना रहा. पुल के निर्माण कार्य का आगाज होने के बाद भी निर्माण कार्य में तेजी नहीं आने की वजह से आम जनता का गुस्सा एक बार फिर छलका और लोगों ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी. तब जाकर उसके बाद सह रेल सड़क पुल के निर्माण कार्य में तेजी आई और पहले चरण में रेल पुल पर गाड़ियों के दौड़ने की शुरुआत भी हो गई.■

feedback@chauthiduniya.com

फीवर (बुखार) को हल्के में ना लें, करें झोला छाप डॉक्टरों से परहेज

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR.PRABHAT KR. SINGH
KHIZARSARAY(GAYA)
(MBBS) GEN SURGERY

गया खिजरसराय के डॉ. प्रभात कुमार सिंह ने अपने निजि क्लिनिक गायत्री सेवा सदन से बताया कि बरसात में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है जिसमें मलेरिया और मियादी के ज्यादा मरीज आ रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ने का कारण-शहर की गंदगी और लोगों की आदतों को बताया। बात करते हुए डॉ. प्रभात ने बताया कि बरसात के मौसम में बाजार की चीजों को तो खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। साथ ही सबसे पहले बासी खाने से दूरी बनायें दूरी ही नहीं बासी खाने को सीधे ना कहें। दूसरा यह कि पानी हमेशा बॉयल या आधा गर्म कर ठंढा कर पीएं। डॉ प्रभात ने खाना खाने से पहले हाथ को बिल्कुल साफ कर लेने या साबुन से हाथ धोने के अलावे शौच के बाद भी अपने हाथों को साबुन से अवश्य साफ करने की सलाह दी। बरसात के पानी में भिंगने से बचें। डॉ प्रभात ने बताया कि इन दिनों बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं जिनमें मियादी और मलेरिया के मरीज ज्यादा हैं। उन्होंने बताया कि लोग बुखार को साधारण समझते हैं और किसी से भी इलाज करा लेते हैं। ध्यान रहे ऐसा हरगिज न करें और किसी अच्छे डॉक्टर से ही दिखायें झोला छाप डॉक्टर को दूर रखें। उन्होंने बताया कि बुखार आने पर पहले दिन आप पारासिटामोल ले सकते हैं लेकिन यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सम्पर्क करें। उन्होंने बताया कि मियादी बुखार के इलाज या दवा का कोर्स 14-15 दिनों का होता है इसलिए इसे अवश्य पुरा करें।■-भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg

Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.

Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

ARIZOL-D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

शिक्षा में सुधार के हाईकोर्ट के आदेश को अखिलेश सरकार ने दिखाया ठेंगा

समाजवादी सरकार पूंजीवादी शिक्षा की हिमायती

देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू है. पैसे वाले अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं जहां बड़ा शुल्क लिया जाता है और जहां से निकलने के बाद बच्चा उच्च शिक्षा पूरी कर कहीं न कहीं नौकरी पा जाता है अथवा अपना कुछ काम शुरू कर सकता है. जिनके पास इन निजी विद्यालयों में पढ़ाने का पैसा नहीं वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने के लिए अभिशप्त हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इन विद्यालयों के बच्चे आगे चल कर नकल करके परीक्षा देने को मजबूर होते हैं. नतीजा यह होता है कि कक्षा आठ तक आते-आते भारत के आधे बच्चे विद्यालय से बाहर हो जाते हैं या शिक्षा पूरी होने पर भी बेरोजगार रहते हैं. भारत के सरकारी विद्यालयों को ठीक करने का एकमात्र उपाय यही है कि सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाएं...

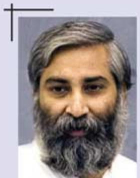

संदीप पांडेय

शिक्षा में सुधार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ठेंगा दिखा रही है. अखिलेश यादव की सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही. 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि सरकारी तनख्वाह पाने वाले जन प्रतिनिधियों, नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सरकार से लाभान्वित होने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ें. उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के छह माह बाद ही उसके अनुपालन के बारे में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन सरकार ने उसकी अनदेखी कर दी. जबकि न्यायालय द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू हो जानी चाहिए थी. जाहिर है अखिलेश सरकार इस दिशा में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रही है.

मुख्यमंत्री ने बीते 8 जून को सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद बेसिक शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट के उक्त आदेश का अध्ययन करने को कहा है. यह मुख्यमंत्री की जानकारी की स्थिति को दिखाता है और यह भी दिखाता है कि वे न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर कितने गम्भीर हैं. शिक्षा में समानता स्थापित करने के लिए व संविधान की भावना को लागू करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) अभियान चला रही है. वर्तमान में प्रचलित गैर-बराबरी वाली शिक्षा व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चुनौती है. शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किए बगैर भविष्य में हरेक गरीब परिवार के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाएगी. हाईकोर्ट ने समाज और राज्य को ठीक ही दिशा निर्देश दिए हैं कि नौकरशाहों, जन प्रतिनिधियों व न्यायाधीशों को अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, जिससे रातों-रात शिक्षा की गुणवत्ता में जादुई सुधार हो जाएगा. यह अभियान शिक्षा के निजीकरण की दिशा को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि समाजवादी पार्टी शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देने की जिद पर अड़ी हुई है. स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी समान शिक्षा प्रणाली के विचार को मानने के लिए ही तैयार नहीं है और हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने में उसे कोई संकोच नहीं हो रहा है. जबकि डॉ. राममनोहर लोहिया, जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना प्रेरणास्त्रोत मानती है, का प्रसिद्ध नारा था कि चाहे राष्ट्रपति की हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान. जाहिर है लोहिया समान शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे और चाहते थे कि अमीर व गरीब के बच्चे साथ में पढ़ें.

मुख्यमंत्री निजी विद्यालयों से बहुत प्रभावित दिखते हैं. वे कहते हैं कि निजी विद्यालयों के अच्छे शिक्षकों का वीडियो बना कर वे दूर स्थित विद्यालयों तक पहुंचाएंगे. किंतु सरकारी विद्यालयों में नियुक्त लाखों शिक्षकों, जो निजी विद्यालयों के शिक्षकों से ज्यादा योग्य हैं, का वे चरमराई शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते. मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे समान पाठ्यक्रम लागू करेंगे किंतु समान शिक्षा प्रणाली नहीं. वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि अमीर व गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, जिसको लेकर अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी प्रावधान है कि 25 प्रतिशत तक गरीब बच्चे अमीर बच्चों के विद्यालयों में पढ़ेंगे और जिसे प्रदेश सरकार लागू भी कर रही है.

पिछले वर्ष जब लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शहर के सबसे बड़े विद्यालय सिटी मांटेसरी में 31 बच्चों के दाखिले का आदेश कर दिया और विद्यालय ने बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया तो सरकार असहाय बन कर खड़ी रही. वह तो विद्यालय के मालिक जगदीश गांधी ने खुद न्यायालय जाने की भूल की तो न्यायालय ने अंततः 13 बच्चों के दाखिले का आदेश दिया. किंतु अखिलेश यादव इसे अपनी सरकार की उपलब्धि मानते हैं. चाहे तो वे बिना मुकदमा लड़े कड़ाई से इस आदेश का अनुपालन करा सकते थे. यह विद्यालय सरकार के कई नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहा है.

जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर गरीबों में लोकप्रियता हासिल कर ली है उसी तरह उपर्युक्त हाईकोर्ट के आदेश को लागू कर अखिलेश यादव चाहें तो उत्तर प्रदेश के गरीबों के बीच लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस फैसले से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ेगी जिसका सीधा लाभ गरीब के बच्चों को मिलेगा. जिस तरह शराबबंदी को लागू करना बिहार के लिए एक कठिन फैसला था, उसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी कठिन प्रतीत होता है. किंतु एक बार अपना मन मजबूत कर जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर दी तो उसका लाभ जनता को मिला. एक तो गरीब परिवारों में पैसे का दुरुपयोग बंद हुआ और पहले जो पैसा शराब में बरबाद होता था वह अब परिवार की जरूरी चीजों पर खर्च होता है. इससे परिवारों में खुशी आई. दूसरा पंचायत चुनावों में शराब न बंटने के कारण उम्मीदवारों का चुनाव लड़ने का खर्च काफी कम हो गया.

इसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने से जब सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधर जाएगी तो सभी लोग जब अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे और तब इससे बच्चों की पढ़ाई पर खर्च काफी कम हो जाएगा. दूसरा फायदा यह होगा कि सभी बच्चे पढ़ने जा पाएंगे, जो आज नहीं हो पा रहा. भारत में 60 लाख बच्चे विद्यालय जाने से वंचित हैं और गरीब परिवारों के 90 प्रतिशत बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय जाते भी हैं तो कक्षा चार तक पढ़ने के बाद भी वे निरक्षर ही रहते हैं. जब सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधर जाएगी और शिक्षा की उपयोगिता नजर आएगी तब माता-पिता भी बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित होंगे. जब सरकार गुणवत्तापूर्ण केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय चला सकती है तो अच्छे प्राथमिक विद्यालय क्यों नहीं चला सकती? उत्तर प्रदेश की ही आईएएस अधिकारी मिनस्ती एस. की प्रशंसा की जानी चाहिए जो अन्य विकल्प होते हुए भी अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं. अन्य आईएएस अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और न्यायाधीशों को मिनस्ती एस. से प्रेरणा लेनी चाहिए.

देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू है. पैसे वाले अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं जहां बड़ा शुल्क लिया जाता है और जहां से निकलने के बाद बच्चा उच्च शिक्षा पूरी कर कहीं न कहीं नौकरी पा जाता है अथवा अपना कुछ काम शुरू कर सकता है. जिनके पास इन निजी विद्यालयों में पढ़ाने का पैसा नहीं वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने के लिए अभिशप्त हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इन विद्यालयों के बच्चे आगे चल कर नकल करके परीक्षा देने को मजबूर होते हैं. नतीजा यह होता है कि कक्षा आठ तक आते-आते भारत के आधे बच्चे विद्यालय से बाहर हो जाते हैं या शिक्षा पूरी होने पर भी बेरोजगार रहते हैं.

भारत के सरकारी विद्यालयों को ठीक करने का एकमात्र उपाय यही है कि सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाएं. इस वर्ग के बच्चों के जाने से सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और फिर गरीब के बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी.

दुनिया में जहां भी सभी बच्चे शिक्षा पाए हैं वह सरकारी शिक्षा व्यवस्था व समान शिक्षा प्रणाली और पड़ोस के विद्यालय से ही सम्भव हुआ है. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा है कि यूपी में तीन श्रेणी के विद्यालय हैं- एक अमीर परिवारों के बच्चों के लिए, दूसरे निम्न मध्यम वर्ग के लिए तथा तीसरा आम इंसान के बच्चों के लिए, जिनमें 90 प्रतिशत आबादी के बच्चे पढ़ते हैं. पहली दो श्रेणियों के विद्यालय निजी हाथों में हैं तो तीसरी श्रेणी के विद्यालय सरकार के परिषद द्वारा संचालित हैं. परिषद द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय खस्ता हाल हैं और यहां न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं हैं. काफी पैसा खर्च करने के बाद भी ये विद्यालय सुधर नहीं रहे, क्योंकि प्रशासन को इनके संचालन में कोई वास्तविक दिलचस्पी नहीं है. सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और सरकारी विद्यालयों के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं. सरकारी विद्यालय मात्र राजनीतिक फायदे के लिए चलाए जा रहे हैं. ये विद्यालय ऊंचे स्तर के कुशासन एवं भ्रष्टाचार का शिकार हो गए हैं. पढ़ाई का स्तर बुरी तरह गिर चुका है. शिक्षकों की नियुक्तियों को राजनीतिक वोट बैंक की दृष्टि से देखा जाता है. नतीजा यह हुआ है कि कम योग्यता वाले लोगों की नियुक्ति शिक्षा मित्र के रूप में हो गई. अब इन शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण के प्रयास चल रहे हैं. नियुक्ति के नियमों में फेरबदल को लेकर न्यायमूर्ति ने खासी कठोर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि नियुक्ति के नियमों को इस तरह तोड़ा मरोड़ा गया है कि एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई तो दूसरी तरफ तमाम मुकदमेबाजी हुई जिसका परिणाम हुआ शिक्षकों की नियुक्ति में देरी. न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ बढ़ा अलग से.

जो इन विद्यालयों का संचालन करते हैं वे काबिल शिक्षकों का चयन क्यों नहीं करते ताकि सरकारी विद्यालयों का स्तर भी उन विद्यालयों जैसा हो जाए जिनमें उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं. चूंकि नौकरशाहों, राजनेताओं व अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अन्य विकल्प खुले हैं इसलिए किसी को भी परिषदीय विद्यालयों की गुणवत्ता के बारे में कोई चिंता नहीं. न्यायालय के फैसले में यूपी सरकार के मुख्य सचिव को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों में काम करने वाले, जन प्रतिनिधियों, न्यायाधीशों व सरकारी कोष से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में ही पढ़ना चाहिए. फैसले में यहां तक कहा गया है कि उपर्युक्त में से जो अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा उसे दंडित करने का भी प्रावधान हो. जितनी फीस वह अपने बच्चे को पढ़ाने पर खर्च कर रहा है उतनी ही राशि वह सरकारी खाते में जमा करे जिसका इस्तेमाल परिषदीय विद्यालयों को सुधारने में किया जाए. इसके अलावा सरकार से लाभान्वित होने वाले जो व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में न पढ़ाएं उन्हें अन्य तरीकों से भी खामियाजा भुगतना पड़े, जैसे उन्हें कुछ अवधि के लिए पदोन्नति या वेतनवृद्धि आदि से वंचित किया जाए. सरकार को प्रावधानों में बदलाव लाकर उपर्युक्त श्रेणी के लोगों को अपने बच्चों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिए ही मजबूर करना चाहिए कह कर अदालत ने इस तर्क को ही सिरे से खारिज कर दिया कि लोगों का अपने बच्चों को अपने मनपसंद विद्यालय में पढ़ाने का अधिकार है. सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सभी निजी संस्थानों के सरकारीकरण के पक्ष में है, जिससे सभी नागरिकों को शिक्षा व चिकित्सा का लाभ एक समान व मुफ्त मिल सके. समय बीतता जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. ■

feedback@chauthiduniya.com

गोरखपुर के बेसिक शिक्षा विभाग का फर्जीवाड़ा

मृतकों को भी दे रहे हैं वेतन

एक शिक्षिका को दो-दो शिक्षकों का वेतन, एक नाम-पता और पैन नंबर पर कई-कई शिक्षक उठा रहे हैं सैलरी

शत्रुंजय सिंह रैकवार

गोरखपुर के बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों के घालमेल के रवैये से आए दिन अजीबोगरीब करामातें देखने को मिल रही हैं. कहीं स्वर्गीय हो चुके शिक्षकों को वेतन भेजा जा रहा है, तो कहीं एक शिक्षिका को दो-दो शिक्षकों का वेतन मिल रहा है. इस तरह के कारनामे चल ही रहे थे कि एक ही नाम पते की शिक्षिका का बलरामपुर और गोरखपुर में फर्जी तरीके से वेतन उठाने का मामला सामने आ गया. इसके उजागर होने से अधिकारियों में बेचैनी है. बेचैनी इसलिए भी है कि मामला खुल जाने के बाद वे पैसे कैसे खा पाएंगे.

ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इन घपलों के बारे में पता नहीं रहता. उन्हें पता सब रहता है, लेकिन कमीशनखोरी के चक्कर में अनदेखी की जाती है. मामला प्रकाश में आने पर अधिकारीगण लापरवाही का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ने में लग जाते हैं. सात महीने पहले अलग-अलग दुर्घटनाओं में जनपद के दो शिक्षकों की मौत हो गई. इसकी जानकारी पूरे विभाग को थी, लेकिन विभाग मृत शिक्षकों के बैंक खाते में हर महीने वेतन भेजता रहा. किसी ने गोपनीय शिकायत की तो मामला उजागर हुआ और मई महीने का वेतन रोका गया. अब बीएसए और लेखा अधिकारी एक दूसरे के मत्थे दोष मढ़ रहे हैं.

कौड़ीराम ब्लॉक के मलाव द्वितीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक नवीन चन्द मल्ल की गत सितम्बर 2015 में ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. सूचना मिलने के बाद विभाग के अधिकारी और शिक्षक संगठन के नेतागण भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे. मरहूम शिक्षक का इकट्ठा हिसाब-किताब करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद वेतन रोका भी गया, लेकिन फिर अगले ही महीने से मरहूम शिक्षक का वेतन भुगतान नियमित(रेगुलर) कर दिया गया. विभाग के अधिकारियों, लिपिकों और कुछ शिक्षक नेताओं की मिलीभगत से वेतन जारी होने का सिलसिला इस वर्ष (2016) के अप्रैल महीने तक चला. शिक्षक की पत्नी भी एक परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापिका हैं.

इसी तरह कौड़ीराम ब्लॉक के ही सोनवापार पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक रामप्रकाश की मौत पिछले वर्ष (2015) जुलाई महीने में हो गई थी. उनके परिजनों ने इस बारे में विभाग को बाकायदा समय से सूचना भी दे दी थी. लेकिन उन मरहूम शिक्षक का वेतन भी एक महीने रुकने के बाद दोबारा जारी हो गया. मृतक शिक्षक के बैंक खाते में हर महीने वेतन भेजने का सिलसिला इस साल अप्रैल महीने तक जारी रहा. मई में यह मामला खुलने के बाद वेतन रोका गया. उक्त दोनों मामले में खंड शिक्षाधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में है. वित्त एवं लेखाधिकारी आलोक राय का कहना है कि शिक्षकों की उपस्थिति का सत्यापन खंड शिक्षाधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है. वेतन बिल का सत्यापन भी एबीएसए ही करते हैं. उसके बाद ही शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान होता है.

बेसिक शिक्षाधिकारी ओपी यादव का कहना है कि शिक्षकों के खाते में लेखा विभाग वेतन भेजता रहा है. सात और नौ माह पहले मृत शिक्षकों के बैंक खाते में वेतन कैसे जाता रहा, यह लेखाधिकारी ही बता पाएंगे. इतना कह कर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली.

हद तो यह भी हो गई कि खजनी की एक शिक्षिका को कई महीने तक दो-दो शिक्षकों का वेतन दिया जाता रहा. मामला उजागर होने के बाद शिक्षिका से वेतन की रिकवरी की गई. हालांकि वसूली गई रकम अब-तक विभाग के खाते में जमा नहीं हुई है. खास बात यह है कि शिक्षिका को पुरुष शिक्षक बनाकर वेतन बैंक खाते में भेजा जाता रहा. खजनी ब्लॉक के शिक्षकों के मार्च के वेतन बिल में शिक्षिका का नाम सीरियल से दो बार दर्ज मिला. खाते में एक से अधिक वेतन जाने के बाद भी शिक्षिका ने शिकायत दर्ज नहीं कराई. वहीं गोरखपुर और बलरामपुर जिले में भी एक ही नाम, पता, डिग्री और पैन नंबर पर दो शिक्षिकाएं अलग-अलग वेतन उठा रही हैं. असली नकली की पहचान के लिए विभाग ने जांच शुरू की है.

खजनी और कौड़ीराम ब्लॉक में शिक्षा विभाग का एक गिरोह सक्रिय है. लेखा विभाग के लिपिकों की मिलीभगत से यह गिरोह तरह-तरह के फर्जीवाड़े करता रहता है. दो मरहूम शिक्षकों के मामले में भी वेतन बंटवारे का सौदा हुआ था. सूत्रों का कहना है कि पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब सांप को रस्सी और रस्सी को सांप साबित करने के विशेषज्ञ शिक्षा विभाग के अधिकारी जी-जान से अपने इसी पुनीत कर्तव्य में जुट गए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

कौड़ीराम ब्लॉक के मलाव द्वितीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक नवीन चन्द मल्ल की गत सितम्बर 2015 में ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. सूचना मिलने के बाद विभाग के अधिकारी और शिक्षक संगठन के नेतागण भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे. मरहूम शिक्षक का इकट्ठा हिसाब-किताब करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद वेतन रोका भी गया, लेकिन फिर अगले ही महीने से मरहूम शिक्षक का वेतन भुगतान नियमित (रेगुलर) कर दिया गया.

यूपी में पर्यटन-विकास की कई योजनाएं मंजूर

अब विमान से होगी यूपी की तफरीह

सूफी यायावर

केंद्र सरकार के खर्च पर उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने के लिए जल्द ही आगरा से वाराणसी वाया लखनऊ के बीच 18-20 सीटों वाली वायुयान सेवा शुरू की जाएगी. ठीक इसी तर्ज पर लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर के बीच भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी, इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. वाराणसी में संत कबीर के जन्म स्थान कबीर चौरा में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए डॉरमेट्री बनवाई जा रही है और यूपी के मशहूर व्यंजनों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है. प्रदेश सरकार ने यूपी में पर्यटन केंद्र विकसित करने के कुछ प्रस्ताव भेजे थे जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है जिसके तहत करीब 300 करोड़ की पर्यटन परियोजनाओं को प्रदेश में लागू किया जाएगा.

यूपी के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में नई पर्यटन नीति लागू की है जिसके तहत प्रदेशभर में पर्यटन विभाग के जो होटल नहीं चल रहे थे, उन्हें निजी क्षेत्रों को लीज पर देने की कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही गेस्ट हाउसों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है. सहगल के अनुसार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक धार्मिक स्थल को 24 घंटे बिजली की सप्लाई दे रही है. इसके साथ इन स्थानों पर अंडरग्राउंड वायरिंग भी कराई जा रही है. इन स्थानों पर राज्य सरकार अपने संसाधनों से अन्य पर्यटक सुविधाएं भी मुहैया करा रही है.

नई टूरिज्म नीति के तहत प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनके आस-पास रहने वालों को उससे जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है और जल्द ही ऐतिहासिक और हेरिटेज इमारतों की देखरेख तथा उनके रखरखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी. इससे बड़े पैमाने पर प्रदेश में पर्यटक स्थलों से जुड़ने वाले लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा. नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों को आने-जाने के लिए वायुयान सेवा शुरू हो जाने के बाद प्रदेश को पर्यटन से कई गुना अधिक राजस्व मिलने लगेगा. केंद्रीय पर्यटन सचिव विनोद जुत्शी ने बताया कि भारत में पर्यटन का सरताज ताजमहल ही है और वह उत्तर प्रदेश में है. ताजमहल देखने के लिए विदेशी पर्यटकों की आमद में तेजी से इजाफा हो रहा है और दूसरे देशों की तुलना में भारत में पर्यटकों की आमद पिछले दिनों बढ़ी है. जुत्शी के अनुसार भारत को विदेशी पर्यटकों से साल में औसतन एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है. भारत में पिछले चार माह में पर्यटक वृद्धि दर 15.50 प्रतिशत दर्ज की गई जो कि एक रिकार्ड है. जुत्शी ने कहा कि यूपी में तो देसी पर्यटन में तेज उछाल आया है, जहां 15 से 20 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जा रही है जो औसतन 12-15 फीसद हुआ करती थी.

केंद्रीय पर्यटन सचिव ने कहा कि भारत के पर्यटन नक्शे पर सबसे पहले अगर ताजमहल है तो दूसरे स्थान पर बुद्ध सरकिट है और वह भी उत्तर प्रदेश में ही है. बुद्ध सरकिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में 100 करोड़ की सहायता से महात्मा बुद्ध के जीवन, बुद्ध के समय के मंदिर, उस समय के खान-पान और रहन-सहन के साथ-साथ उस काल को लाइट एंड साउंड शो तथा लेजर शो में दर्शाया जाएगा. उनके अनुसार कुशीनगर हवाई पट्टी के चालू करने में जो भी औपचारिकताएं होंगी उन्हें जितनी जल्द पूरा किया जाएगा.

जुत्शी ने कहा कि केंद्र सरकार रामायण सर्किट के तहत अयोध्या, श्रिंगेश्वर (इलाहाबाद) तथा चित्रकूट में बड़े पैमाने पर पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यूपी टूरिज्म को करीब 100 करोड़ की धनराशि मुहैया कराएगी. इस सर्किट के बारे में उन्होंने कहा कि अयोध्या में अगर धन की कमी हुई तो और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. चित्रकूट में साइनेज के अलावा एक विजुअल वॉल तैयार की जाएगी जिस पर थ्री-डी इफेक्ट से उस काल को प्रदर्शित किया जाएगा. चित्रकूट में एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए एक फुट ओवर ब्रिज भी तैयार किया जाएगा. रामायण सर्किट के अलावा कृष्णा सर्किट के अंतर्गत मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव में पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यूपी टूरिज्म को केंद्र से आर्थिक सहयोग मिलेगा. वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यूपी टूरिज्म के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की घोषणा के साथ उन्होंने कहा कि यहां पर एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए करीब 13 करोड़ की लागत से गंगा नदी में रिवर क्रूज जल्द शुरू किया जाएगा. इस पर टिकट लेकर पर्यटक गंगा नदी पर इधर से उधर आ जा सकेंगे. इसका संचालन यूपी टूरिज्म विकास निगम ही करेगा. यूपी टूरिज्म के सहयोग से केंद्र सरकार वाराणसी में भी 100 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करेगी. केंद्रीय पर्यटन सचिव के मुताबिक आगामी चार से 6 अक्टूबर तक वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय बुद्ध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभिन्न देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायियों और बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें सारनाथ के अलावा बिहार के बोधगया भी ले जाया जाएगा. इस कॉन्क्लेव में उन्हें बुद्ध सर्किट के तहत आने वाले पर्यटक स्थलों की सैर भी कराई जाएगी. ■

उन्हें पता ही नहीं कबीर का जन्म-स्थान कहां है!

उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों पर सरकार का सूचनातंत्र ही बट्टा लगा देता है. आधिकारिक तौर पर जारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को यह पता ही नहीं कि संत कबीर का जन्मस्थल कहां है और निर्वाण स्थल कहां. पर्यटन योजनाओं को लेकर सरकार का जो पक्ष प्रेस-विज्ञप्ति के रूप में भेजा गया, उसमें मगहर को संत कबीर का जन्मस्थान लिखा गया था. इतना ही नहीं मगहर को वाराणसी में दिखा दिया. जबकि मगहर संत कबीर नगर जिले में स्थित है.

फ्लॉप लायन सफारी के बाद अब इटावा के बीहड़ों में बनेंगी फिल्में

समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में लायन सफारी स्थापित करने की योजना फ्लॉप ही हो चुकी है. उसे सत्ता के जोर पर जबरन ही चलाया जा रहा है. गुजरात के शेरों की इटावा के कथित लायन सफारी में होने वाली सिलसिलेवार मौतों से पूरा प्रदेश वाकिफ हो चुका है. अब प्रदेश के इटावा निवासी मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए प्रदेश के नौकरशाह इटावा के दुर्गम बीहड़ों में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहे हैं. पांच नदियों के संगम स्थल पंचनदा को फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से विकसित करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है. एक समय खूंखार डकैतों की शरणस्थली के तौर पर कुख्यात रहे पंचनदा में यमुना, चंबल, सिंधु, क्वारी और पहुज नदियों का मिलन होता है. आज भी उस इलाके में कोई अपहरण होता है तो अपहृत को इसी इलाके में छुपा कर रखा जाता है.

बहरहाल, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के सदस्य विशाल कपूर ने बताया कि पांच नदियों के संगम पंचनदा को फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से विकसित किए जाने पर विचार किया जा रहा है. यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से अनुकूल है, साथ ही यहां पर वन्य जीवों की बहुलता भी किसी फिल्म की शूटिंग को जानदार बनाने में सहायक होगी. इस बारे में इटावा के जिलाधिकारी नितिन बंसल से भी विचार-विमर्श किया जा रहा है. शासन को पंचनदा को विकसित करने का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया जा चुका है. उल्लेखनीय है कि पंचनदा सैंक्चुअरी (संरक्षित वनक्षेत्र) में आता है, इसके बावजूद नौकरशाह इस शांत-वनक्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग की चहल-पहल और शोर-शराबे को लाना चाहते हैं. कपूर ने कहा कि वे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पंचनदा को फिल्मों की शूटिंग के मद्देनजर विकसित कराने के बारे में प्रस्ताव देंगे, जिससे देश के नामी फिल्मकारों को वहां शूटिंग के लिए आकर्षित किया जा सके. चंबल के बीहड़ों में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें कई बेहद लोकप्रिय भी हुई हैं.

तय हो युवा लेखकों की उम्र

अनंत विजय

बात नब्बे के शुरुआती दशक की रही होगी, संभवत 1993 की. उस वक्त राजेन्द्र यादव के संपादन में निकलने वाली पत्रिका हंस की हिंदी साहित्य में तूती बोलती थी. यादव जी अपनी पत्रिका में नए-नए प्रयोग कर उसको नई ऊंचाई प्रदान कर रहे थे. आमतौर पर उन दिनों हंस के प्रकाशन की तिथि के आसपास पत्रिका के कार्यालय चला जाता था. उसका एक फायदा यह होता था कि डाक डाकुओं के प्रकोप से पत्रिका बच जाती थी और वक्त से पहले हंस पढ़ने की चाहत भी पूरी हो जाती थी. ऐसे ही एक दिन हंस का अंक छप कर आया था. अंक उलटते पलटते उसमें एक महिला कथाकार की तस्वीर पर नजकर गई. सालों पुरानी तस्वीर छपी थी बल्कि यों कहें कि उनकी उस जमाने की तस्वीर छपी थी जब वो युवा रही होंगी. उस वक्त वो अपने उम्र के चौथे वय में थीं लेकिन यादव जी हंस के पन्नों पर उनको जवान बनाए हुए थे. मैंने यादव जी से चुटकी ली और उसकी वजह जाननी चाही तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो अभी युवा लेखिका है. मेरे अनुमान के मुताबिक जिस यादव जी उनको युवा बता रहे थे उस वक्त वो पैंसठ के आसपास की रही होंगी. यादव जी ने इस तरह के कई युवा लेखक हिंदी साहित्य को दिए. मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि उनका मानना था पाठक कहानीकार की फोटो देखकर कहानियां पढ़ लेते हैं या इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कहानीकारों की ग्लैमरस फोटो देखकर पत्रिका भी खरीद लेते हैं. इसी सोच के तहत यादव जी लेखिकाओं की तरुणाई की तस्वीरें छापते रहे और उन्होंने युवा लेखक के बारे में साहित्य में एक भ्रम की स्थिति पैदा की. जवानी की तस्वीरें देख-देख कर रचनाकार खुद तो युवा मानता रहा और साथी लेखकों से ये अपेक्षा भी करता रहा कि उसे युवा लेखक माना जाए. दूसरी ओर रवीन्द्र कालिया ने युवाओं पर एक के बाद एक कई अंक निकालकर हिंदी साहित्य तो युवामय कर दिया था. दर्जनों लेखक तब से लेकर अब तक युवा ही बने हुए हैं. कालिया जी ने जिस तरह से युवा लेखकों की फौज खड़ी की थी उससे कई बेहतरीन लेखक निकल कर आए, लेकिन जो बच गए वो सिर्फ युवा लेखन की दुकान खोलकर साहित्य में अपने उत्पादन को खपाने की फिराक में रहते हैं. रवीन्द्र कालिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि उन्होंने जिन युवा लेखकों को मंच देकर साहित्य की दुनिया में लॉन्च किया था वो लॉचिंग पैड पर ही जमकर बैठ जाएंगे. इसी तरह से 27-28 दिसंबर 1970 में पटना में एक विशाल युवा लेखक सम्मेलन हुआ था. उस दौर के सभी चर्चित युवा लेखकों को उसमें बुलाया गया था. उस वक्त भी युवा लेखकों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी थी लेकिन मोटे तौर पर चालीस के आसपास के लेखकों को भी उसमें बुलाया गया था. कुछ अपवाद अवश्य थे. जैसे नामवर सिंह तैंतालीस के थे. परंतु ज्यादातर लेखक तीस साल के थे जिनमें अशोक वाजपेयी, रवीन्द्र कालिया, वेणुगोपाल. इब्राहिम शरीफ आदि थे. तब नागार्जुन को उसमें बुलाया गया था परंतु उन्होंने तब लिखा था या कहा था कि वो युवा लेखक सम्मेलन में बूढ़े बंदर की तरह इधर-उधर डोलना नहीं चाहते हैं. उस वक्त जिन युवा लेखकों की पहचान की गई थी उसमें से ज्यादातर कालांतर में हिदीं साहित्य के मूर्धन्य कवि, कहानीकार और आलोचक के तौर पर स्थापित हुए.

दरअसल हिंदी साहित्य में युवा लेखकों को लेकर बेहद भ्रम की स्थिति है. पचास पार के लेखक अब तक खुद को युवा कहलवाना चाहते हैं. इस चाहत का असर यह होता है कि वो साठ-पैंसठ तक आते आते भी लेखन में बौआ जी बने रहते हैं. हिंदी के इस तरह के कथित युवा लेखकों की स्थिति बिहार के जमींदार परिवार के बौआ जी जैसी होती है. बिहार के जमींदार परिवारों में अक्सर देखा जाता है कि जमींदार साहब के घर जब बेटा पैदा होता है तो उसको प्यार से उनके घरवाले और जमींदारी के सारे लोग बौआजी कहकर बुलाते हैं. तरुणाई खत्म होते होते बौआ जी की शादी कर दी जाती है और साल दो साल में बौआजी पिता भी बन जाते हैं. बौआजी

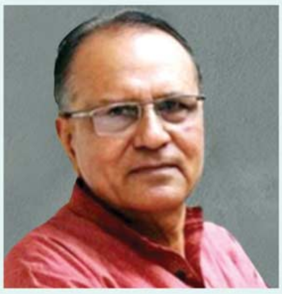

की उम्र बढ़ती जाती है लेकिन पिता के जीवित रहने की वजह से उनको जमींदारी के काम-काज को करने का मौका नहीं मिल पाता है. वक्त बीतने के साथ-साथ बौआ जी का पुत्र बड़ा होने लगता है और उसके दादा जी प्यार प्यार में उसको धीरे-धीरे जमींदारी के गुर सिखाने लग जाते हैं. इन सबसे बेखबर बौआजी तो बौआजी ही बने रहते हैं, वो भी सोचते हैं कि चलो अच्छा है बेटा काम-काज सीख रहा है. इस चक्कर में जमींदार साहब के निधन या उनके बहुत बुजुर्ग होने की वजह से उनके पोते को जमींदारी की कमान मिल जाती है और बौआजी बेचारे पिता और पुत्र के बीच के सत्ता हस्तांतरण के गवाह बनकर रह जाते हैं, क्योंकि वो अधेड़ हो चुके होते हैं. हिंदी की इस वक्त की कथित युवा पीढ़ी भी बौआजी सिन्ड्रोम से गुजर रही है. पिछली पीढ़ी अब तक जीवित और सृजनरत है और अगली पीढ़ी तैयार हो चुकी है यानि कई कथित युवा लेखक बौआजी ही बने रह गए हैं. मतलब ये कि पचास पचपन के अधेड़ होने के बावजूद वो युवा ही बने हैं या बने रहना चाहते हैं, जिसका नतीजा सबके सामने है.

हिंदी साहित्य में युवा लेखक की कोई उम्र सीमा तय नहीं है. पचास तक तो युवा ही माना जाता है. पिछले दिनों एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गया था तो वहां जिस लेखिका की किताब का विमोचन हो रहा था उनके बेटी दामाद भी मौजूद थे, लेकिन संचालनकर्ता बार-बार उनको युवा लेखिका कह रहा था. जब जब संचालनकर्ता उनके नाम के पहले युवा शब्द का उद्घोष करता तो लेखिका महोदय का चेहरा दमकने लगता. इस तरह के कई वाकए आपको साहित्य से जुड़े आयोजनों में जाने पर देखने को मिल सकते हैं. हिंदी के इन अधेड़ लेखकों को युवा कहलवाने की क्या जरूरत है, यह बात आजतक मेरे समझ से बाहर की रही है. इन अधेड़ लेखकों की इस चाहत को समझते हुए युवाओं को मंच देने वाले कई संस्था साहित्य में सक्रिय हैं. वो खुद को युवाओं का माल बेचने वाले दुकानदार के तौर पर पेश करते हैं. तीस के आसापास के उम्र के लेखकों की रचनाओं के साथ-साथ इन बुढ़ाते लेखकों की रचनाएं आदि छापकर उनकी युवा बने रहने की आकांक्षा को तृप्त करते रहते हैं. यहां वो भी राजेन्द्र यादव की राह पर चलते हुए लेखिकाओं और लेखकों की उन तस्वीरों को तवज्जो देते हैं जिनमें बालों की सफेदी न दिखाई दे. वैसे भी हिंदी साहित्य में बालों की सफेदी को छुपाने का जबरदस्त रिवाज है. इसका फायदा यह होता है कि दूर-दराज के जो पाठक इन मंचों पर पहुंचते हैं और इन कथित युवा लेखकों या लेखिकाओं से मिले नहीं होते हैं वो उनको युवा मान लेते हैं और रचनाओं पर प्रतिक्रिया देते वक्त भी युवा छवि को ध्यान में रखते हैं. इन अधेड़ लेखकों को युवा बनाए रखने में पाठकों की प्रतिक्रियाएं संजीवनी का काम करती हैं. रही सही कसर फेसबुक पूरी कर देती है जहां युवा की परिभाषा किसी चौहद्दी में नहीं बांधी जा सकती है. बस आपके चार छह लेखकनुमा फेसबुकिया गुंडे आपके साथ खड़े हों जो सच कहने वालों के खिलाफ अंटशंट लिखकर उनको अपमानित कर सकें. इनके दम पर आप जबतक चाहें युवा बने रह सकते हैं. दरअसल एक और बड़ी बिडंवना इनके साथ है ये खुद को मौके बे मौके वरिष्ठ कहलवाना भी पसंद करते हैं और युवाओं के संग युवा होने का मौका भी नहीं गंवाते हैं. इस वक्त पूरे देश में साहित्य से लेकर राजनीति तक में राग युवा बजाया जा रहा है तो हिंदी के अधेड़ साहित्यकार भी इस राग में शामिल होना चाहते हैं.

इस बात पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि हिंदी के युवा लेखक की अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए. क्या आज हिंदी के किसी लेखक में ये साहस है कि वो नागार्जुन की तरह युवाओं के नाम पर होने वाले अखिल भारतीय आयोजन में जाने से इंकार कर दे. फिलहाल तो ऐसा कोई लेखक या लेखिका दिखाई नहीं देता है. युवा की अगर शब्दकोश की परिभाषा को छोड़ भी दें तो एक सीमा तो होनी चाहिए. हिंदी के मृतप्राय लेखक संगठनों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो इस तरह की कोई पहल करेंगे. पहल तो खुद साहित्यकारों को ही करनी होगी और युवा कहलवाने के लाभ लोभ को त्यागना होगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

आरुक (आड़ू)

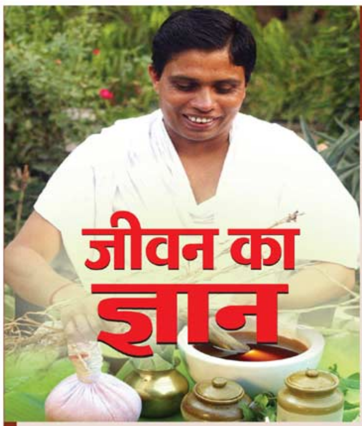

परिचय

यह छोटे कद का वृक्ष होता है. इसमें एक गोंद निकलता है. इसकी गिरी में से एक प्रकार का तैल निकाला जाता है, जो कड़वे बादाम तेल की तरह होता है. इसकी मूल छाल का प्रयोग रंगने के काम में किया जाता है. यह मूल से रूप से चीन में प्राप्त होता है. इसके अतिरिक्त पश्चिमी एशिया, म्यांमार तथा यूरोप में कृषि किया जाता है. उत्तरी भारत में विशेषत: 3200 मी ऊंचाई पर हिमालय के प्रदेशों में जैसे कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि में इसकी खेती की जाती है.

बाह्य-स्वरूप

यह लगभग 8 मी ऊंचा, विशाल, पर्णपाती गुल्म या छोटा वृक्ष होता है, जिसकी शाखाएं अरोमिल होती है. इसके पत्र आम पत्र जैसे गहरे हरे रंग के होते हैं जो पककर गिरने से पहले लाल रंग के हो जाते हैं. इसके पुष्प एकल, हल्के गुलाबी वर्ण के तथा तंतु-युक्त होते हैं. फल गोलाकार, 5-7 सेमी व्यास के, गूदेदार, पीले रंग के, रक्ताभ आभायुक्त तथा अत्यंत कठोर गुठली युक्त होते हैं. इसका पुष्पकाल फरवरी-मार्च में तथा फलकाल अप्रैल से जून में होता है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

- **आरुक का अपक्व फल-** कषाय, मधुर, अम्ल, उष्ण, गुरु तथा पित्तकफशामक होता है. यह मलावष्टम्भक, ग्राही, भेदी, पाचन तथा मुख का शोधन करता है. इसका प्रयोग प्रमेह, गुल्म तथा अर्श की चिकित्सा में किया जाता है.
- **आड़ू का पक्व फल –** मधुर, गुरु तथा कफपित्तकारक होता है. यह रुचिकर, धातुवर्धक, बृंहण, हृद्य तथा शीघ्र पचने वाला है. इसका प्रयोग प्रमेह, अर्श, ज्वर, गुल्म, वातव्याधि, अरुचि, अत्यग्नि, वृद्धावस्था जन्य व्याधि तथा रक्तदोषों की चिकित्सा में किया जाता है.
- आरुक के भ्रूण एवं अपक्व बीजों के मद्यसार में प्रविकारी क्रिया पाई जाती है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

कर्ण रोग:

- **कर्णशूल-** आड़ू बीज तैल को 1-2 बूंद कान में डालने से कान की वेदना का शमन होता है.

उदर रोग :

- **विबन्ध-**प्रतिदिन सोने से पूर्व छिलका सहित 1 आड़ू फल का सेवन करने से कब्ज में लाभ होता है.
- **आमाशय शूल-**10-20 मिली आड़ू फल स्वरस में 500 मिग्रा अजवायन चूर्ण मिलाकर पिलाने से आमाशय शूल में लाभ होता है.
- **आंत्र कृमि-**10-20 मिली आड़ू फल स्वरस में 125 मिग्रा हींग मिलाकर पिलाने से आंतों के कीड़ों का शमन होता है.

वृक्कवस्ति रोग :

- **अश्मरी-**आड़ू फल का नियमित सेवन करने से वस्तिगत पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है.

प्रजननसंस्थान रोग :

- **आर्तव विकार-**आड़ू के पत्तों का शीतकषाय बनाकर 20 मिली मात्रा में नियमित सेवन करने से आर्तव-विकारों में लाभ होता है.
- 1-2 ग्राम बीज चूर्ण का सेवन करने से कृच्छार्तव तथा योनिकण्डू में लाभ होता है.

त्वचा रोग :

- **त्वक्शोथ-**आड़ू की गुठली के तैल को लगाने से पूययुक्त त्वक्शोथ में लाभ होता है.
- **व्रण-**आड़ू के पत्र को पीसकर लगाने से घाव, रोएं की सूजन, खुजली तथा बवासीर में लाभ होता है.
- **चर्म रोग-**आड़ू बीज तेल की शरीर पर मालिश करने से चर्मरोगों में लाभ होता है.

सर्वशरीर रोग :

- **आमवात-** आड़ू की काण्ड त्वक् को पीसकर लगाने से आमवात तथा वातरक्त में लाभ होता है.
- **स्वेद-दौर्गन्ध्य-** आड़ू के पत्तों को पीसकर, शरीर पर मल कर, गुनगुने पानी से शरीर को धो लेने से पसीने से होने वाली दौर्गन्ध का शमन होता है.

बाल रोग :

- **बच्चों के पेट के कीड़े-** आड़ू के पत्तों का रस निकालकर 1-2 मिली मात्रा में पिलाने से बच्चों के पेट में पड़ने वाले कृमि नष्ट हो जाते हैं.

प्रयोज्यांग : त्वक्, पत्र, फल तथा गुठली.

मात्रा : त्वक् चूर्ण 2-4 ग्राम. बीज चूर्ण 1-3 ग्राम. फल स्वरस 10-30 मिली. पत्र-स्वरस 1-2 मिली. पत्र क्वाथ 10-20 मिली. ■

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

गुरु पर अपनी इच्छा थोपना अनुचित

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

गुरु के सन्दर्भ में भक्तों द्वारा अपनी इच्छा या भावनाओं को थोपना क्या उचित है?

बहुत से भक्त गुरु के प्रति अपनी भावना और इच्छाएं नाना रूपों में प्रकट करते हैं. इस संदर्भ में वे यह नहीं सोचते कि गुरु पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा. शिरडी में बाबा जब दमा-रोग से ग्रस्त हुए, तब भी कुछ भक्त इस बात को नजरअंदाज करके उन्हें ठंडे जल से स्नान कराते थे. बाबा को समय-समय पर दमे का दौरा पड़ता था, जिससे उन्हें सांस लेने में कष्ट होता था, लेकिन अनेक भक्त ऐसी स्थिति में भी अपनी भक्ति-भावना प्रदर्शित करने के लिए उन पर चन्दन आदि का लेप पूर्ववत् करते रहते थे और दमे में वर्जित खाद्य पदार्थ-जैसे कि-दूध, दही, चावल आदि खाने के लिए उन्हें बाध्य करते थे, जिससे उनकी स्वास्थ्य-दशा बिगड़ जाती थी.

गुरु-शिष्य-संबंध

आध्यात्मिक रास्ते पर चलते समय गुरु-शिष्य के संबंध की विभिन्न स्थितियों को कैसे समझा जा सकता है?

गुरु का अस्तित्व शिष्य के जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष अथवा स्थूल या सूक्ष्म रूप में सदैव रहता है. समय आने पर यह संबंध स्वत: प्रकट होता है. इसके भी विभिन्न स्तर और स्थितियां होती हैं. पहली स्थिति वह होती है, जिसमें गुरु ही शिष्य को आकर्षित करते हैं, (जैसा कि *श्री साईं सच्चरित्र* में नाना साहेब चान्दोरकर के उदाहरण से स्पष्ट होता है). दूसरी स्थिति यह है, जिसमें गुरु एवं शिष्य दोनों ही एक-दूसरे की ओर बढ़ते हैं. तीसरी स्थिति वह है, जिसमें गुरु आगे-आगे और शिष्य पीछे-पीछे चलता है और चौथी स्थिति में शिष्य कहीं भी रहे, गुरु शिष्य के साथ ही रहते हैं. यह चौथी स्थिति सबसे उत्तम है.

गुरु, शिष्य और माया

ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति गुरु के प्रति आकर्षित होने पर भी कभी तो भाव में डूबा हुआ अनुभव करता है और कभी लाख छटपटाने पर भी वह कुछ अनुभव नहीं कर पाता?

जिनका भाव स्थिर न हो उसी के साथ ऐसा होता है कि कभी तो भावना की बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है. अत: जैसे ही वह अन्तर्मन में अस्थिर हुआ नहीं कि माया अपना खेल आरंभ कर देती है. तब गुरु कभी-कभी भाव-शक्ति पर परदा डाल देते हैं. फिर वह अपने प्रारब्ध-कर्म को भोगता रहता है. इसलिए कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. प्राणी की इच्छा-शक्ति कार्य करती है. गुरु या माया-जिसके प्रति प्राणी के मन में अधिक आकर्षण होगा, वह वैसा ही करने लगता है. यदि माया-शक्ति का आकर्षण प्रबल होगा तो वह माया में फंसेगा और यदि गुरु के प्रति आकर्षण प्रबल होगा तो उसकी माया कटेगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

त्वचा को सुंदर ऐसे बनाएं

डॉ. दीपाली भारद्वाज

ये काम न करें

साबुन का इस्तेमाल न करें

साबुन में पीएच लेवल 9 होता है, जबकि त्वचा का पीएच लेवल 5.5 होता है. इसलिए साबुन आपकी त्वचा को रूखा बना देता है और इसमें एलर्जी और संक्रमण का भी खतरा होता है. इसकी जगह आप अपनी त्वचा के हिसाब से क्लींजर का इस्तेमाल करें.

त्वचा के लिए सुरक्षित उत्पाद पर भरोसा करें

हाइपोएलेर्जेनिक उत्पाद का प्रयोग करें. इसका अर्थ है कि किसी उत्पाद को डर्मेटोलाजिस्ट ने बेहतर तरीके से जांचा-परखा हो और यह सुनिश्चित किया हो कि इसमें एलरजिक तत्व नहीं है. नन-कमोडेनिक उत्पाद का ही इस्तेमाल करें. कमोडेनिक उत्पाद मुंहासे आदि पैदा करता है.

नियमित रूप से फेसियल कराएं

त्वचा पर ग्लो पाने के लिए अल्फा-हाइड्रोक्सी एसिड उत्पाद चुनें, ये उत्पाद है लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड. इन्हें प्राकृतिक रूप से दूध और गन्ना से निकाला जाता है. इससे त्वचा पर प्राकृतिक निखार आता है और दाग-धब्बों को भी दूर रखता है.

उच्चतम एसपीएफ वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें

25 सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाला सनस्क्रीन त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों आदि से बचाता है. एक डर्मेटोलाजिस्ट होने के नाते मैं महसूस करती हूं कि सनस्क्रीन हमारे जवान, कोमल और निखरी हुई त्वचा का सबसे अच्छा दोस्त है. धूप में जाने से 15 मिनट पहले इसे त्वचा पर लगाना चाहिए. तीन घन्टे बाद इसे फिर से लगाना चाहिए.

खाने में ज्यादा नमक का इस्तेमाल न करें

खाने में अधिक नमक का इस्तेमाल आपकी त्वचा के पानी को सोखता है, इससे त्वचा सुस्त पड़ जाती है. इसके अलावा, खाने में प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रक्त में अमीनो एसिड की मात्रा बरकरार रहे.

याद रखें

नहाने के बाद एक अच्छा बॉडी लोशन का इस्तेमाल करें ताकि नमी बनी रहे. यह आपकी त्वचा को मुलायम और चिकना बनाए रखेगा. यदि लोशन न लगाना चाहें तो जेल इमल्सन तकनीक वाले उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं. ■

धोनी का सितारा डूबना इतना आसान नहीं!

यह भी एक कटु सत्य है कि जब तक आप ऊंचाई पर होते हैं, तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जमीन पर आते ही सारे ऐब सामने आ जाते हैं. उन तमाम उपलब्धियों को एक पल में भुला दिया जाता है और आलोचनाओं का अम्बार लग जाता है. धोनी के साथ भी यही है. अभी उनकी चारों तरफ से आलोचना हो रही है. लेकिन हमें याद रखना होगा कि धोनी इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं, वह हमेशा विजयी होने का दम रखते हैं. अब यह देखना है कि धोनी क्रिकेट को अलविदा कहते हैं या एक बार फिर धूमकेतु की तरह वापस लौटते हैं.

सैय्यद मोहम्मद अब्बास

धोनी एक ऐसा नाम है जो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सितारा रहा है. धोनी ने अपने खेल से टीम इंडिया के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. क्रिकेट के फलक पर माही लगातार टीम इंडिया का मान बढ़ाते रहे हैं, लेकिन हालिया नाकामियों ने माही की साख पर बट्टा लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. इतना ही नहीं उनका खामोश बल्ला भी विरोधियों को बोलने का अवसर दे रहा है. कप्तानी में भी वह लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. 2105 विश्व कप की बात हो या फिर हाल में समाप्त हुए टी-20 विश्व कप की, दोनों जगह धोनी का सिक्का नहीं चला. आलम तो यह रहा कि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से भी पीछा छुड़ाना बेहतर समझा. अब वह वन डे और टी-20 में जौहर दिखाने को बेताब हैं. यह बात भी सत्य है कि माही का खूबसूरत अतीत वर्तमान को नई दिशा नहीं दे रहा है. एक वक्त था जब धोनी बतौर कप्तान टीम इंडिया को बुलन्दियों पर पहुंचा रहे थे, लेकिन वक्त ने अब करवट ली तो कप्तानी को लेकर उन पर तलवार लटकने लगी है. भारतीय क्रिकेट में लगातार आलोचना के बाद यह आवाज उठने लगी है कि माही की जगह विराट को टीम की कमान सौंप दी जाए. टेस्ट में विराट कप्तान के रूप में चमक रहे हैं, लेकिन वन-डे में अभी उनको आजमाया नहीं गया है. कप्तान बदलने की आवाज लगातार उठ रही है. यह पहला मौका नहीं है कि कप्तानी को लेकर हाय तौबा मची हो. इससे पूर्व 90 के दशक में अजहर और सचिन के बीच कप्तानी को लेकर उठापटक हुई थी. बाद के दौर में सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ के बीच भी कप्तानी को लेकर गहरा मदभेद उत्पन्न हो गया था. हालांकि 80 और 90 के दशक में कपिल देव से लेकर सुनील गावस्कर के बीच भी कप्तानी को लेकर कई बार ड्रेसिंग रूम की बातें सामने आ चुकी हैं. मौजूदा दौर में कप्तानी को लेकर काफी बहस चल रही है. दरअसल हाल के दिनों में माही का जादू कम हुआ है. बतौर कप्तान वह लगातर शिकस्त झेल रहे हैं. जिस मैच में वह जीतते हैं उसमें विराट का पराक्रम शामिल होता है. बीते एक साल से विराट का बल्ला बोल रहा है. उनके जौहर को देखकर पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें तीनों फॉरमेट में कप्तान बनाने की वकालत तेज कर दी है.

धोनी के करियर पर नजर डाली जाए तो वह बेहद शानदार रहा है. उनकी बदौलत टीम इंडिया ने विदेश में जीत का डंका बजाया है. विश्व क्रिकेट में धोनी की धूम उनके कप्तान बनते दिखने लगी थी. यह बात भी सत्य है कि माही को जो टीम मिली थी वह लगभग तैयार थी. तमाम ऐसे खिलाड़ी टीम में शामिल थे जो मैच जिताने वाले हुआ करते थे. अभी कुछ साल पहले राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली के बीच कप्तानी को लेकर कई बात सामने आई थी. चैपल की खुराफाती साजिश के आगे दादा को कप्तानी ही नहीं बल्कि टीम से भी बाहर होना पड़ा था. चैपल अपने फायदे के लिए खिलाड़ियों को चुनते थे. उनके कोच रहते हुए मोहम्मद कैफ और इरफान पठान जैसे खिलाड़ियों का करियर गर्त की ओर ढकेल दिया गया. चैपल एक तरह से ऐसी टीम खड़ी करना चाहते थे जिसमें गांगुली समेत कोई भी दमदार खिलाड़ी न हो. उनका एकमात्र मकसद भारतीय क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना था. वहीं राहुल द्रविड़ ने गांगुली के बाद टीम इंडिया की बागडोर सम्भाल ली. इस दौरान चैपल के निशाने पर दादा बने रहे. चैपल के उठापटक से सौरभ टीम से अंदर और बाहर होते रहे. इतना ही नहीं चैपल की दादागीरी से त्रस्त दादा क्रिकेट से संन्यास लेने को मजबूर हो गए. इस युग का पटाक्षेप कर धोनी को कप्तान बना दिया गया. अगर आप और पीछे जाएंगे तो अजहर और सचिन के बीच कप्तानी को लेकर खूब टकराव हुआ था. 90 के दशक में अजहर की कप्तानी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था. इसी दौरान सचिन को भी टीम इंडिया की कमान दी गई थी. जानकारों की मानें तो कप्तान बनने के दौरान दोनों ही खिलाड़ियों में नहीं बनती थी. एक वक्त ऐसा भी आया जब सचिन को हटाकर बतौर कप्तान अजहर की टीम में वापसी हो गई.

धोनी के दौर की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि केवल विराट के साथ उनका पंगा चल रहा हो, बल्कि वीरू के साथ भी उनकी ठन गई थी. दरअसल धोनी ने कप्तान बनते ही उन खिलाड़ियों को रडार पर रखा जो किसी दौर में सौरभ गांगुली के चहेते हुआ करते थे. चाहे वह वीरू हों या युवी. इतना ही नहीं गम्भीर, जहीर व भज्जी जैसे खिलाड़ी एकाएक टीम से बाहर कर दिए गए. दूसरी ओर दिग्गज खिलाड़ियों में टीम इंडिया की दीवार के नाम से मशहूर द्रविड़, वेरी-वेरी स्पेशल लक्ष्मण तथा स्पिन के जादूगर कुम्बले को भी वक्त से पहले संन्यास लेना पड़ा. इस दौर में सचिन किसी तरह से अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे. क्रिकेट के रिकॉर्ड-पुरुष सचिन तेंदुलकर टीम में लगातर जमे हुए थे, लेकिन किसी तरह उन्हें भी सम्मानपूर्वक विदाई दे दी गई. धोनी का दखल टीम इंडिया में लगातर बढ़ रहा था. टीम इंडिया उनकी कप्तानी में लगातर जीत रही थी. आए दिन नए-नए रिकॉर्ड बन रहे थे. बतौर कप्तान पहले उन्होंने अजहर को पीछे छोड़ा और बाद में दादा से आगे निकल गए. धोनी ने युवा खिलाड़ियों की अच्छी फौज तैयार कर ली. उनमें रोहित शर्मा, सुरैश रैना और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. मौजूदा समय में विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के हर प्रारूप में रनों का अम्बार लगा रहे हैं. उनके बल्ले की चमक पूरी दुनिया के गेंदबाजों के लिए खौफ का केंद्र बनी हुई है. विराट जिस अंदाज में खेल रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो क्रिकेट के कई रिकॉर्ड बौने साबित कर सकते हैं. पिछले एक साल के प्रदर्शन को देखा जाए तो उनका खेल गजब का रहा है. वह टीम इंडिया के मैच फिनिशर के रूप में सामने आए हैं. उनका रिकॉर्ड बयान कर रहा है कि आने वाले दिनों में वह कई और रिकॉर्ड बना सकते हैं. इतना ही नहीं वह रिकॉर्ड में सचिन को भी पीछे छोड़ सकते हैं. एक साल में कोहली ने 15 टी-20 में 95.57 की औसत से 669 रन बनाए हैं जबकि एक साल में धोनी 18 टी-20 में 48 की औसत से केवल 192 रन ही बना सके हैं. विराट के करियर की शुरुआत बेहद खराब थी लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे इसमें काफी सुधार किया. उन्होंने 171 वन-डे में 7212 रन बनाए, शायद सचिन भी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़े थे. विराट का वन-डे औसत भी बेहद कमाल का है. कोहली ने 51.51 के औसत से 25 शतक और 36 पचासा जड़कर साबित कर दिया है कि वह आने वालों दिनों में कई और रिकॉर्ड बना सकते हैं. इतना ही नहीं टेस्ट में भी वह बेस्ट दे रहे हैं. दुनिया की हर बड़ी टीम के खिलाफ विराट रन बनाते हैं. टेस्ट में उन्होंने अब तक 41 मैचों में 44.02 की औसत से 2994 रन बनाए हैं. माही की टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद उन्हें टेस्ट टीम की बागडोर सौंपी गई. टेस्ट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया आगे बढ़ रही है. वहीं धोनी की बात की जाए तो इतना तो साफ है कि उनका मौजूदा ग्राफ काफी नीचे आया है. न बल्ला चल रहा है और न ही टीम जीत रही है. बतौर बल्लेबाज वह कई अहम मौकों पर नाकाम रहे हैं. अब तक 277 वन-डे में धोनी ने 8918 रन बनाए. शुरुआत में वह बेहद ऊंचाई पर थे. अब वे टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. उन्होंने 90 टेस्ट में 4876 रन बनाए. धोनी का क्रिकेट करियर अब ढलान पर है. उनके बल्ले की धार भी कुन्द हो चुकी है. आलम तो यह है कि अब वह गेंदें ज्यादा खेलते हैं और रन बेहद कम बनाते हैं. कप्तानी में भी उनका दांव उल्टा पड़ जाता है. कुल मिलाकर धोनी का क्रिकेट करियर खात्मे की ओर बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट को काफी क्रिकेट खेलना है. ऐसे में धोनी के पास फिर से साबित करने का भले ही मौका हो लेकिन इतना तो तय है कि उनका खराब खेल उनके करियर को गर्त में ले जा सकता है. दूसरी ओर विराट लगातार शिखर पर चमकते सूरज की भांति चमक रहे हैं. यह भी एक कटु सत्य है कि जब तक आप ऊंचाई पर होते हैं, तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जमीन पर आते ही सारे ऐब सामने आ जाते हैं. उन तमाम उपलब्धियों को एक पल में भुला दिया जाता है और आलोचनाओं का अम्बार लग जाता है. धोनी के साथ भी यही है. अभी उनकी चारों तरफ से आलोचना हो रही है. लेकिन हमें याद रखना होगा धोनी इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं, वह हमेशा विजयी होने का दम रखते हैं. अब यह देखना है कि धोनी क्रिकेट को अलविदा कहते हैं या एक बार फिर धूमकेतु की तरह वापस लौटते हैं. ■

बतौर बल्लेबाज वह कई अहम मौकों पर नाकाम रहे हैं. अब तक 277 वन-डे में धोनी ने 8918 रन बनाए. शुरुआत में वह बेहद ऊंचाई पर थे. अब वे टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. उन्होंने 90 टेस्ट में 4876 रन बनाए. धोनी का क्रिकेट करियर अब ढलान पर है. उनके बल्ले की धार भी कुन्द हो चुकी है. आलम तो यह है कि अब वह गेंदें ज्यादा खेलते हैं और रन बेहद कम बनाते हैं. कप्तानी में भी उनका दांव उल्टा पड़ जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

माही ने रचा इतिहास, रणतुंगा से आगे निकले

जिम्बाब्वे में भारतीय क्रिकेट टीम का जानदार प्रदर्शन जारी है. वन-डे मैचों की सीरीज में युवा खिलाड़ियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है. जिम्बाब्वे की टीम बेहद कमजोर दिखी. तीसरा मैच बुधवार 15 जून को हरारे में खेला गया. इस मैच के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा वन-डे मैचों में कप्तानी करने के मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुना रणतुंगा को पीछे कर दिया. इस तरह शीर्ष दस कप्तानों की सूची में वह तीसरे नम्बर पर काबिज हो गए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में कप्तानी कर धोनी ने रणतुंगा की बराबरी कर ली थी. यह बतौर कप्तान धोनी का 193वां वन-डे था. इस मामले में केवल दो ही कप्तान धोनी से आगे हैं. सबसे ज्यादा वन-डे मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग के नाम है. पोंटिंग ने जहां 230 वन-डे मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व किया, वहीं दूसरे नम्बर पर न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज स्टिफन फ्लैमिंग हैं जिन्होंने 218 वन-डे मैचों में न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी की है. धोनी ने वह सफलता भी हासिल कर ली जो शायद अब तक उनकी कामयाबी में शामिल नहीं थी. दरअसल जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वन-डे में मिली जीत के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने नए सीजन की शुरुआत श्रृंखला जीतकर की है. इतना ही नहीं धोनी ने कप्तान के तौर पर जिम्बाब्वे की जमीन पर पहली बार सीरीज जीतने का गौरव हासिल किया. माही की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी-20 वर्ल्ड कप जीता, वन-डे वर्ल्ड कप जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट में नम्बर-1 बनाया, वन-डे और टी-20 रैंकिंग में भी नम्बर-1 का खिताब दिलाया. कुल मिलाकर तमाम आलोचनाओं के बावजूद धोनी लगातार नया इतिहास बनाते जा रहे हैं. धोनी ने यह पहले भी कहा है कि अगर उन्हें लम्बे समय तक क्रिकेट खेलना है तो उनका फिट रहना बेहद जरूरी है. अगले महीने माही 35 साल के हो जाएंगे. ऐसे में धोनी को अपनी फिटनेस के साथ अच्छी फॉर्म को भी बनाए रखने की कड़ी चुनौती है. ■

फिल्म सुल्तान से हटाया गया अरिजीत का गाना

सलमान ने नहीं सुनी अरिजीत की अर्ज़ी

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

सलमान खान की फिल्म सुल्तान में अरिजीत सिंह ने जो गाना गाया था उसे सलमान ने फिर से नए सिंगर से गवा लिया है. सलमान ने ट्वीट किया और कहा कि पेश है राहत फतेह अली खान की आवाज में जग घुमया... इस ट्वीट से साफ हो गया है कि माफी मांगने के बाद भी सलमान ने अरिजीत की अर्ज़ी ठुकरा दी और फिल्म सुल्तान के गाने जग घुमया को राहत फतेह अली खान की अवाज़ में रिकॉर्ड करके दर्शकों के बीच रिलीज़ भी कर दिया गया है. जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है. इससे पहले अरिजीत ने सलमान खान से अपने द्वारा गाए इस गाने को फिल्म सुल्तान से न हटाने की अपील की थी और अरिजीत ने अपने फेसबुक पेज पर सलमान खान से माफ़ी भी मांगी थी. लेकिन सलमान खान पर उसका कोई असर नहीं हुआ और फिल्म सुल्तान से अरिजीत का गाना हटवा दिया गया.

बात 2 साल पहले रिनॉल्ट स्टार गिल्ट अवॉर्ड 2014 में हुए शो की है जिसको सलमान खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहें थे. बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवॉर्ड अरिजीत सिंह को फिल्म आशिकी-2 (तुम ही हो...) के लिए दिया गया. जब अरिजीत सिंह स्टेज पर आए तो थोड़े सुस्त लग रहे थे. तभी सलमान खान चुटकी लेते हुए बोलते हैं कि...सो गए थे क्या...इस पर अरिजीत सिंह सलमान को बोलते हैं...आप लोगों ने सुला दिया यार तब से.

तब सलमान बोलते हैं...मगर इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, अगर ऐसे गाने बजते रहेंगे (सलमान गुन-गुनाते हुए...तुम ही हो...तुम ही हो...) तो नींद ही आएगी यार.

इसके बाद सलमान अरिजीत को अवॉर्ड देने के बाद बोलते हैं...लीजिए आपका अवॉर्ड ... थैंक्यू, अब जाओ.

अरिजीत सिंह सलमान से जिस तरह से बात कर रहे थे सलमान को शायद उनका यह बर्ताव पंसद नहीं आया. बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद बेस्ट लिरिक्स का अवॉर्ड फिल्म आशिकी-2 (तुम ही हो...) के लिए मिथुन को दिया गया. मिथुन ने अवॉर्ड लेते ही सलमान को बोला की सर...तुम ही हो...ने लोगों को सुलाया नहीं है बल्कि जगाया है. इस पर सलमान ने कहा कि... अरे आपके सिंगर (अरिजीत सिंह) सोते-सोते आए हैं सर...इस पर मिथुन अपना बचाव करते हुए बोलते हैं कि सर अरिजीत ने इस गाने को बहुत सबर और प्यार से गाया है. फिर सालमान हंसते हुए मिथुन से कहते हैं कि सॉरी सर... मुझे माफ़ कर दीजिए... मैं आपके पैर पकड़ता हूं सर...कुछ देर बाद सलमान मिथुन को थोड़ा घमुने के लिए कहते हैं, मिथुन की जींस पर एक स्टिकर चिपका था जिसे सलमान हटाना चाहते थे. लेकिन मिथुन को लगा की सलमान उनकी टांग खींच रहे हैं और वह पीछे हट गए. लेकिन जब सलमान मिथुन की जींस से स्टिकर निकालकर दिखाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि...यह तुम्हारे सिंगर ने ही चिपकाया है तुम पर.. इसके बाद मिथुन सलमान से माइक लेते हुए बोलते हैं कि आप लोग 6 घंटे बिठाकर रखते हैं तभी ऐसा होता है. सलमान को यह बात ठीक नहीं लगी और बोले...वाह यार... सभी दे ही रहे हैं. इसके बाद सलमान मिथुन पर गुस्से से चिल्लाते हुए बालते हैं...चलो निकलो... मिथुन सलमान खान को देखते ही रह जाते हैं और घबराते-मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं नहीं डरा सर. फिर सलमान उनको गले से लगाकर जाने को कहते हैं.

कहने को तो यह एक मज़ाकिया किस्सा था जो आमतौर पर किसी भी अवॉर्ड शो में होता रहता है पर यह मज़ाक अरिजीत को इतना भारी पड़ेगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

खैर अब तो वक्त ही बताएगा कि सलमान खान अरिजीत से कब तक नाराज़ रहते हैं. उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और अरिजीत सिंह सलमान खान की फिल्मों के लिए ढेरों गीत गाएं.■

> सलमान ने अरिजीत की अर्ज़ी ठुकरा दी और फिल्म सुल्तान के गाने जग घुमया को राहत फतेह अली खान की अवाज़ में रिकॉर्ड करके दर्शकों के बीच रिलीज़ भी कर दिया गया है. जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है.

विद्या बालन करेंगी मराठी फिल्मों में डेब्यू

पिछले कुछ समय से मराठी सिनेमा को काफी पसंद किया जाने लगा है. जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में आई मराठी फिल्म *सैराट* है. जिसने क्षेत्रीय बॉक्स ऑफिस पर रहकर 100 करोड़ का व्यवसाय कर सारे रिकॉर्डस तोड़ दिए.

न स्लिम-ट्रिम फिगर, न स्टाइलिश डिजाइनर ड्रेसेज, टैलेंट हो तो फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम सिर्फ एक्टिंग के दम पर हासिल किया जा सकता है. एक्ट्रेस विद्या बालन इस बात की सटीक मिसाल हैं. बॉलीवुड में विद्या बालन ने एक के बाद एक लगातार चार साल फिल्म *इश्किया, पा, द डर्टी पिक्चर्स* और *कहानी* जैसी फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के तमाम अवॉर्ड्स अपने नाम किए. ये सिनेमा के प्रति उनकी समझ ही थी, जिसने उन्हें साल 2013 में प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल की जूरी मेंबर में शामिल किया. वहीं बीते साल वह मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की जूरी सदस्य बनीं. इन सब उपलब्धियों के बाद विद्या बालन फिल्म *एक अलबेला* में गीता बाली के रोल में मराठी सिनेमा में डेब्यू कर रहीं हैं. बतां दे कि गीता बाली शम्मी कपूर की पहली पत्नी थीं. जिनका निधन स्मॉलपॉक्स के कारण 1965 में हो गया.

विद्या का कहना है कि वह बहुत वक्त से मराठी फिल्म करनी चाह रही थी. विद्याधर भट्टे, जिन्होंने *एक अलबेला* में मेरा मेकअप किया है, वह मेरी शुरुआती फिल्मों में भी जुड़े रहे थे. उनसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं. उन्होंने कुछ मराठी फिल्में प्रोड्यूस भी की थीं, तो मैंने उनको कहा था कि अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट हो तो मेरे पास जरूर लाइएगा. कुछ समय बाद वह *एक अलबेला* की पटकथा लेकर मेरे पास आए और मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बताया और कहा कि फिल्म में स्पेशल अपियरेंस के तौर पर गीता बाली का रोल है, क्या आप करना पसंद करेंगी? मैंने तुरंत हां कर दी.

पिछले कुछ समय से मराठी सिनेमा को काफी पसंद किया जाने लगा है. जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में आई मराठी फिल्म *सैराट* है. जिसने क्षेत्रीय बॉक्स ऑफिस पर रहकर 100 करोड़ का व्यवसाय कर सारे रिकॉर्डस तोड़ दिए.■

अक्षय करेंगे डबल रोमांस

अक्षय कुमार स्टारर नमस्ते इंग्लैंड का काम अगस्त में शुरू हो जाएगा और हाल ही में फैंस को ख़बर मिली कि फिल्म में अक्षय के साथ सोनाक्षी सिन्हा नज़र आएंगी. लेकिन ख़बर यहीं खत्म नहीं होती है, दरअसल फिल्म में अक्षय कुमार एक नहीं दो रोमांस करते दिखेंगे और यह दूसरा फिरंगी रोमांस होगा आएशा शर्मा के साथ. आएशा शर्मा फिल्म में बाहरवाली बनेंगी और सोनाक्षी सिन्हा घरवाली बनेंगी. अक्षय कुमार इस घरवाली बाहरवाली के बीच में फंस जाएंगे. जिस तरह नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार ने फिरंगी से अपना प्यार यानि कि कैटरीना कैफ को छीन लिया था उसी तरह इस बार सोनाक्षी सिन्हा भी एक फिरंगी यानि कि आएशा शर्मा से अपना प्यार अक्षय कुमार को छीनती नज़र आएंगी. फिल्म को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फ्लैशबैक

बॉलीवुड के रॉकस्टार थे शम्मी कपूर

बॉलीवुड में बिंदास मिज़ाज़ के चलते शम्मी कपूर एक ऐसा सितारा थे, जिन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से दर्शकों का बेपनाह प्यार पाया. महान फिल्म अभिनेता और थिएटर कलाकार पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी रमा मेहरा के दूसरे बेटे शम्मी सच्चे अर्थों में एक रॉकस्टार थे. उनका वास्तविक नाम शमशेर राज कपूर था. पृथ्वीराज कपूर के दो और बेटे शशि कपूर और राज कपूर हैं.

मुंबई में 21 अक्टूबर, 1931 को जन्मे शम्मी कपूर को घर में बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला था. उन्होंने वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्म जीवन ज्योति से बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. वह जिस दौर में फिल्मों में आए, तब तक उनके बड़े भाई राज कपूर की मासूमियत और सधा हुआ अभिनय दर्शकों के दिल-दिमाग पर छा चुका था. लेकिन शम्मी ने अल्हड़-रोमांटिक अभिनेता की जो छवि निर्मित की, वह आज भी लोगों के जेहन में ताजा है.

वर्ष 1957 में आई फिल्म *तुम सा नहीं देखा* ने शम्मी को पहचान तो दी, लेकिन उन्हें मनचाही सफलता जंगली से मिली. उनके डांस करने का एक अलग ही अंदाज था, वह डांस से चाहने वालों का मन मोह लेते थे. उनके करियर की सबसे सुपरहिट फिल्मों में *ऐन इवनिंग इन पेरिस, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, जानवर, जंगली, तुमसा नहीं देखा, प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, ब्रह्मचारी, तीसरी मंजिल* का नाम शामिल है.

शम्मी को सफल कलाकार बनाने में विख्यात गायक मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा योगदान है. रफ़ी साहब ने उनके लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिनमें तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जन्म जन्म का साथ है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, इस रंग बदलती दुनिया में और निकला ना करो तुम सजधज कर शामिल हैं. वह अपनी फिल्मों में कभी लंबी टोपी पहनकर शैतानी करते, तो कभी कंबल लपेट कर फुदकते, कभी पहाड़ियों से लुढ़कते हुए याहू चिल्लाते. उनकी हर अदा अनूठी और हर बात निराली थी. शम्मी कपूर और सायरा बानो अभिनीत फिल्म जंगली (1961) ने बॉक्स आफिस को हिलाकर रख दिया था और शम्मी रातोंरात स्टार बन गए. शम्मी ने अपने जमाने की हर सितारा अभिनेत्री सुरैया, मधुबाला, नूतन, आशा पारेख, मुमताज, साधना, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी व कल्पना के साथ हिट फिल्में दीं.

फिल्मी पर्दे पर रोमांटिक किरदारों में नज़र आने वाले शम्मी असल जिंदगी में भी रोमांटिक और इश्किया मिज़ाज़ की वजह से काफी चर्चा में रहते थे. उन्होंने फिल्म अदाकारा गीता बाली से इश्क किया और उन्हें अपनी जीवन संगिनी बना लिया, लेकिन स्मॉलपॉक्स के कारण 1965 में गीता बाली का निधन हो गया. गीता बाली ने उनके साथ 14 फिल्मों में काम किया था. गीता बाली के निधन के बाद उन्होंने 1969 में नीला देवी से शादी की.

अभिनेता रणबीर कपूर के साथ आई रॉकस्टार फिल्म उनके करियर की आखिरी फिल्म थी. शम्मी कपूर को फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिले. उन्हें वर्ष 1995 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और वर्ष 2004 में दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से नवाज़ा गया. इस जिंदादिल अभिनेता ने 14 अगस्त, 2011 को मुंबई में अंतिम सास ली.■